तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३६

शनिवार, ६ अप्रैल, १९६३
१६ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२ और ७४४ से ७५६ ३५६३—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७५७ और ७५८ . ३५८७—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५८४ . ३५८८—३६२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३६२२—२३

प्राक्कलन समिति—

चौंतीसवां प्रतिवेदन ३६२३

विधेयक पर राय ३६२३

सभा का कार्य . . . . . ३६२३—२४

सरकारी उपक्रमों के लिये स्थायी समिति संबंधी प्रस्ताव के बारे में . ३६२४

अनुदानों की मांगें . ३६२४—६२

प्रतिरक्षा मंत्रालय

श्री फ्रैंक एन्थनी . ३६२४—२६

श्री जोकिम आल्वा ३६२६—२७

श्री ब्रजराज सिंह कोटा ३६२७—२८

श्री कृ० च० पन्त ३२२८—२९

श्री काशी राम गुप्त . . ३६२९—३४

श्री दि० ना० सिंह ३६३४—३५

श्री अ० व० राघवन ३६३५—३६

श्री भागवत झा आज़ाद ३६३६—३७

श्री प्र० चं० बरुआ ३६३७—३८

श्री कृष्णपाल सिंह ३६३९

श्री बालकृष्णन् . ३६४०

श्री रवीन्द्र वर्मा . ३६४०—४१

श्री नाथ पाई . . . . . ३६४२—४३

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, ६ अप्रैल, १९६३
१६ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखक उत्तर

भाप-इंजनों का निर्यात

+

†*७४१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप-इंजनों के निर्यात के लिये विदेशी मंडी ढूंढ़ने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या किसी देश ने कोई क्रयादेश (आर्डर) दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों ने ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) स्टील के इंजनों की विदेशी मांग का पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : भारतीय रेलवे इंजनों की मांग का पता लगाने के लिए किन देशों में प्रयास किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने श्रीलंका, मलाया, पाकिस्तान, आदि जैसे पड़ौसी देशों में पता लगाया था ।

†**श्री सुबोध् हंसदा** : यदि सरकार मांग का पता लगा सके, तो क्या सरकार इंजनों का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा करेगी या अन्य किसी एजेन्सी द्वारा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : काल्पनिक ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या पता लगाया गया है कि निकट भविष्य में हमारे पास कितने इंजनों का अतिरेक होगा और क्या इससे पहिले सभी रेलवे इंजनों को बदल दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह एक निरन्तर क्रिया है । स्टीम इंजनों के बेकार होने पर, वे स्वतः ही बदल दिये जाते हैं । परन्तु यह कार्य किसी भी भान्ति विदेशी मांग का पता लगाने के हमारे प्रयासों में नहीं आता ।

†**श्री ब० कु० दास** : हमारे प्रयासों के अब तक सफल न होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति डीजल और बिजली के इंजन प्राप्त करने की है ।

†**श्री वीरभद्र सिंह** : क्या हमारे रेलवे इंजनों के लिए विदेशी मांग का पता इस कारण नहीं लगा है कि हमारे इन इंजनों का मूल्य अधिक है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी नहीं । अन्य देशों में रेलवे इंजनों के मूल्यों की अपेक्षा हमारे रेलवे इंजनों के मूल्य काफी अच्छे हैं ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या उत्पादन की हमारी दर इतनी अधिक हो गई है । कि हम अन्य देशों को इनका निर्यात कर सकें ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम देश की मांग पूरी कर सकते हैं और हम केवल विदेशी मांग का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अधिक मात्रा में निर्यात कर सकेंगे ।

†**डा० रानेन सेन** : मैंने उत्पादन के बारे में पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं ।

श्री कछवाय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इसमें सरकार की कितनी लागत लगेगी ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य क्या है ?

श्री कछवाय : आप के इंजन पूरी तरह से लेने के लिए ।

श्री शाहनवाज़ खां : इंजन तो पूरे बन गये हैं ।

†**श्री बसुमतारी** : अन्य देशों में इन इंजनों की किस्म के बारे में क्या मत है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने अपने इंजनों के बारे में अन्य देशों के मतों की जांच नहीं की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"भारत के मानचित्र" वाले डाक टिकट

†*७४२. **श्री पे० वेंकटासुब्बया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारत के मानचित्र' वाले वर्तमान डाक टिकटों के स्थान पर अधिक आकर्षक डिजाइन वाले टिकट चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निकाले जाने वाले नये टिकटों का ब्यौरा क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

†**श्री पे० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार का विचार हमारे डाक टिकटों का डिजाइन ऐसा बनाने का है कि उनसे हमारे देश में कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में आरम्भ की गई अनेक कार्य-वाही का भास हो ?

†**श्री भगवती** : टिकटों पर जिन विषयों के चित्र बनाये जायेंगे वे विचाराधीन है। यह निश्चय किया गया है कि .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या यह विचार है या किया जा रहा है कि उन पर हमारी विकास योजनाओं के चित्र बनाये जायें ।

†**श्री भगवती** : यह भी विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जो नये टिकट छापने का विचार किया जा रहा है, तो क्या पहिले के टिकट सुन्दर और आकर्षक नहीं थे जिसकी वजह से यह जरूरत पड़ रही है।

†**श्री भगवती** : पिछली टिकट माला १-४-५७ को छापी गई थी। अतः उनके स्थान पर नये चित्र व नये टिकट छापना आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक वस्तु समय के साथ कम आकर्षक हो जाती है।

†**श्री पे० वेंकटासुब्बया** : इस बारे में निश्चय करने में सरकार को कितना समय लगेगा कि ये विचाराधीन लागू किये जायें ?

†**श्री भगवती** : पहिली माला इस वर्ष के अन्त तक प्रकाशित होगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह प्रस्ताव है या क्या सरकार का प्रोग्राम टिकटों को प्रतिरक्षा का आधार देने का है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे चित्र जारी करने का है जैसे मेजर शैतान सिंह का चित्र, जिन्हों ने चुशुल में वीरगति प्राप्त की और जारी किये जाने वाले अनेक टिकटों पर अन्य नायकों के चित्र ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा सुझाव है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह विचार है या क्या उन का यह प्रोग्राम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का विचार या प्रोग्राम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री भगवती** : अनेक सुझाव दिये गये हैं और वे विचाराधीन हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन में यह भी है ? यह वह अभी नहीं बता सकते ?

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि हमारे डाक टिकटों के कला पहलू पर समूचे संसार में प्रतिकूल मत व्यक्त किये जाते हैं ?

†**श्री भगवती** : यह अनुकूल होता है ।

†**श्री दाजी** : क्या यह निश्चय एतदर्थ रूप में किया गया है या विभाग की कोई स्थायी व्यवस्था ह जो समय समय पर, दो या तीन वर्षों में, डिज़ाइन बदलने का काम करती है ?

†**श्री भगवती** : इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और उस ने इस मामले पर विचार किया है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या शिक्षाप्रद बनाने के विचार से टिकट जारी करने का विचार है या प्रदर्शनार्थ जारी करने का और यदि पहिला विचार हो, तो ब्योरा क्या है ?

†**श्री भगवती** : दोनों । पिछले दो प्रकार के टिकट जारी किये गये थे । एक भारतीय पुरा-तत्व के बारे में थे और दूसरे विकास योजनाओं के बारे में थे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ये लैस अट्रैक्टिव स्टाम्प किस ने डिजाइन किये थे और किस ने एप्रूव किये थे और क्या जो एप्रूव करने वाले हैं उन के अन्दर इतनी सेंस आफ़ एट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की गई है ताकि आगे ये स्टाम्प मोर एट्रैक्टिव बन सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आप गढ़े क्यों खोदने लगे हैं ।

अगला प्रश्न । श्री रघुनाथ सिंह । नहीं हैं । श्री चक्रवर्ती ।

"भूख से छुटकारा" आंदोलन

+

†*७४४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्रीमती जमुना देवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने देश में सर्वसाधारण में यह भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है कि खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित "विश्व में भूख से छुटकारा" सप्ताह के अनुसार कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाये ।

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में इस के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से किन विशेष कार्यक्रमों और परियोजनाओं का आयोजन किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में विश्व विश्वविद्यालय सेवा के प्रधान से अनुरोध किया गया है कि शिक्षित युवकों के लिये कार्यक्रम बनायें ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रतिक्रियायें पता लगी हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** (क) और (ख): "भूख से छुटकारा" आन्दोलन के उद्देश्यों तथा महत्व में रेडियो पर राष्ट्रपति तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के प्रसारणों, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के सन्देशों, और ग्रामीण रेली का आयोजन कर के ग्राम वासियों सहित सभी व्यक्तियों में जागृति तथा रुचि पैदा करने का प्रयास किया गया था ।

(ग) और (घ): विश्वविश्वविद्यालय सेवा के सभापति से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में प्रोग्रामों का आयोजन करने की प्रार्थना की गई है और इस सेवा की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने अपनी स्थानीय समितियों से अपने-अपने विश्वविद्यालयों में उपयुक्त कार्यवाही करने को कहा है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात का ध्यान रख कर कि जनसंख्या में १९० लाख की वार्षिक वृद्धि भूख की समस्या को बढ़ा देती है, क्या यह प्रोग्राम,जहां तक जनसंख्या-नियंत्रण का सम्बन्ध है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोग्राम के साथ मिलाया गया था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हालांकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति सरकारी है, उसे स्वास्थ्य मंत्रालय के उस प्रोग्राम से नहीं मिलाया गया क्योंकि यह प्रोग्राम खाद्य तथा कृषि संगठन ने आरम्भ किया था । जैसाकि मैं ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा, इस आन्दोलन के लिए हमारी एक राष्ट्रीय समिति है और यह देश भर में राष्ट्रीय समिति के निदेशों के अन्तर्गत कार्य कर रही है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने इस सप्ताह के मनाये जाने से पैदा हुए जोश को बनाये रखने के लिए कोई योजना बनाई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हां, जोश को बनाये रखा जायेगा, और यह बढ़ता रहेगा वास्तव में, हम ने आधी दर्जन से अधिक प्रोग्राम आरम्भ किये हैं । देश के अनेक भागों में कुल ग्यारह प्रोग्राम चलाये जायेंगे ।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या प्रोग्राम केवल शिक्षाप्रद हैं या खाद्य उत्पादन प्रोग्राम पर इस का कोई प्रभाव पड़ता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह दोनों ही हैं, शिक्षाप्रद भी हैं और कार्यान्विति पर भी प्रभाव डालते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : पहिले बताया गया था विश्व खाद्य कांग्रेस, जो वाशिंगटन में होगी, इस आन्दोलन का एक अंग है । क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नाम निश्चित कर लिये गये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे सदस्यों के नाम शीघ्र घोषित कर दिये जायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि गांवों के अंदर भूख से मुक्ति के बारे में लोगों को परिचित कराया गया है, क्या उन के ध्यान में यह बात आई है कि गांवों में लाखों लोग ऐसे हैं जोकि भूख से मुक्ति चाहते हैं और खेती करने के लिए भूमि प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उन को भूमि नहीं मिल रही है, तो क्या इस के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम बनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा सवाल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन श्रीमन्, जो नहीं यह तो इस से सम्बन्धित है। हम उन्हें भूख से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और वे उस से मुक्ति पाने के लिए खेती करने के वास्ते ज़मीन चाहते हैं जोकि उन को नहीं मिल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस के लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : सम्बन्ध तो ज़रूर बनता है मगर बहुत दूर रास्ते में चलना पड़ता है।

†**श्री दाजी** : खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस आन्दोलन के बीच अनुमान लगाया है कि संसार की लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या प्रायः भूखी रहती है। क्या इस आन्दोलन के बीच हम ने भी भारत में कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो हमारी कितनी प्रतिशत संख्या को खाद्य तथा कृषि संगठन की परिभाषा के अनुसार भूखा कहा जा सकता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन के अनुमान में इस देश में भी भूख की मात्रा शामिल है।

†**श्री दाजी** : क्या हम ने अपने देश के लिए कोई अनुमान लगाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमारे देश के लिए कोई पृथक् प्रतिशत निर्धारित किया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : नहीं

†**श्री पे० वेंकटासुब्बया** : सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थायें इस कार्य के लिए कहां तक प्रयोग की जा रही हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब हम ने सहारपुनर जिले में रामपुर में यह बड़ी ग्रामीण रैली आयोजित की, तो सामुदायिक विकास मंत्रालय के कर्मचारियों ने हमें पूर्ण सहयोग दिया और उन्होंने वह सब किया जो हम चाहते थे।

श्री तरजू पाण्डेय : भूख से मुक्ति आन्दोलन के सिलसिले में क्या सरकार मुख्य रूप से अपने देश में बेकारों को काम देने के लिए कोई योजना पर विचार कर रही है अथवा उसे चला रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : उस के बारे में योजना चल रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क़रीब १२-१३ योजनाएं ऐसी चालू की जा रही हैं कि जिन में ऐसे लोगों को काम मिलेगा जोकि इस वक्त तक काम नहीं कर रहे हैं और बेकार हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस भूख से बचाव आन्दोलन को यूनिवर्सिटिज के ग्रेजुएट्स चलायेंगे या भूखे किसान चलायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : दोनों की ज़रूरत है। विश्वविद्यालयों के स्नातक और गांवों के किसान और मज़दूर सब मिल जुल कर इस काम को चलायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने प्रश्न को पुनः दुहराना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि खेती करने के इच्छुक लोगों को खेती के लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही है इसलिए क्या राज्य सरकारों को इस के लिए लिखा गया है, और मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : उस के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े देने के लिए तो मैं नोटिस चाहूंगा लेकिन इधर क़रीब ७०००० एकड़ के क़रीब ज़मीन का बटवारा हुआ है। ज़मीन को बांटने के लिए विस्तृत योजना बन रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिव नारायण : अब तक इस आन्दोलन में सरकार ने कितना रुपया खर्च किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सप्ताह जो १७ से ले कर २३ मार्च तक मनाया गया इस में दो बड़े अच्छे काम खास दिल्ली में किये। एक मोबाइल वैन चारों ओर घूम-घूम कर ऐसे पौष्टिक पदार्थों को बांटने की कोशिश करेगी जो बर्बाद हो जाते हैं, खास कर . . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल जहां तक मैंने समझा वह यह था कि सरकार ने कितना रुपया खर्च किया ?

डा० राम सभग सिंह : अमृतसर के नज़दीक बर्के गांव में एक दूध का कारखाना चालू किया गया है उस में क़रीब ६० लाख रुपये लगेंगे और २२ लाख उसमें अमरीका की मदद दी जायेगी। इसी प्रकार को अन्य योजनाएं हैं

क्षेत्रीय परिवहन निगम

+

†*७४५. { श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री ने हाल में ही बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आसाम के राज्यों के लिये क्षेत्रीय परिवहन निगम बनाने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों से कहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

(क) और (ख). बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम सरकारों के लिए क्षेत्रीय परिवहन निगम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

२. फिर भी, पश्चिम बंगाल और आसाम क्षेत्र में सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी कुछ मामलों पर विचार करने के लिए ८–२–१९६३ को पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के कमरे में हुई बैठक में, यह सुझाव दिया गया था कि एक योजना बनाई जा सकती है जिसके अन्तर्गत आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें सड़क परिवहन संगठन से, जो आसाम तथा उत्तर बंगाल को, अनिवार्य वस्तुयें भेजने के लिए परिवहन विभाग ने बनाया है, सम्बन्धित हो सकती हैं।

३. भारत सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है। इस के बाद, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० की योजना में एक से अधिक राज्य में परिवहन सेवायें जुटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम बनाने का उपबन्ध नहीं है। सड़क परिवहन उपक्रम को, जो विभाग द्वारा चलाया

†मूल अंग्रेज़ी में

जाता है, कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनी बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि कम्पनी बनाई जाती है, तो इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम की सरकारें यथासमय अंशधारी के रूप में भाग ले सकेंगी।

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से मैं देखता हूं कि विभागी सड़क परिवहन उपक्रम लिमिटेड कम्पनी बनाया जायेगा जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम अंशधारी होंगे। उड़ीसा को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह भी पूर्वी खण्ड में आता है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह अनिवार्य रूप में खण्डीय कार्यक्रम नहीं है। सड़क परिवहन संगठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये बनाया गया था ताकि नदी सेवाओं में पाकिस्तानी मल्लाहों की हड़ताल से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना किया जा सके। आजकल, हमने एक विभागीय संगठन बनाया है जो कम्पनी में बदल दिया जायेगा। जिसमें सम्बन्धित राज्य सरकारें भाग ले सकती हैं। यदि उड़ीसा सरकार केवल वाणिज्यिक दृष्टि में इसमें सम्मिलित होना चाहे, तो उस पर केवल विचार विमर्श द्वारा निश्चय किया जायेगा।

†**श्री महेश्वर नायक** : यह योजना बनाने में क्या अब तक विभिन्न राज्यों में कराधान सम्बन्धी विद्यमान असमानता को समाप्त किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रश्न मूल प्रश्न से असम्बन्धित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी भी यही भावना है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस निगम का गठन केवल इस उद्देश्य से हो रहा है कि हमारी नौवहन सेवा को पाकिस्तानी मल्लाहों से सुरक्षित रखा जाये या यह आसाम से आने और जाने वाले यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सड़क परिवहन संगठन हमारे नौवहन या अन्तर्देशीय जल परिवहन का संरक्षण नहीं कर सकता। यह वैकल्पिक संचार साधन की व्यवस्था करने के लिए है क्योंकि एक ही संचार साधन पर निर्भर रहना अर्थात् रेलवे पर या इन परिस्थितियों पर निर्भर करना कि अन्तर्देशीय जल परिवहन में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि इसे पाकिस्तान-क्षेत्र से जाना होता है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : नेशनल इनमरजेंसी की वजह से ईस्टर्न जोन में ट्रांसपोर्ट और कम्यनिकेशन्स का जो सवाल पैदा हुआ है तो उसके सम्बन्ध में क्या कोआरडिनेशन मिनिस्टर ने कुछ खास सुझाव दिये थे, यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है और यदि किया गया है तो क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कोआरडिनेशन मिनिस्टर ने जब उस इलाक़े का दौरा किया उसके पहले ही यह आरगनाइजेशन सेट अप कर दी गई थी और उस सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही की गई थी उसको उन्होंने एक प्रकार से अच्छा ही समझा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इन राज्यों में और विशेष कर पश्चिमी सीमान्तर राज्यों में उत्तम और अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या प्रोग्राम है ? क्या भारत के पश्चिमी सीमान्त राज्यों के लिए एक ऐसा निगम बनाने का विचार है जैसा कि पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मेरा ख्याल है कि यह बड़ा ही असम्बन्धित प्रश्न है। परन्तु जहां तक रेलों के साथ सहयोग का प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि मुझे उत्तर देना चाहिये। हमारा विचार एक प्रबन्धक मण्डल बनाने का है जिसमें रेलों के भी प्रतिनिधि होंगे जो सड़क तथा रेल के बीच आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

श्री काशी राम गुप्त : इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और असम के लिए माल ढोने में इससे कुछ सहूलियत बढ़ी है या नहीं ?

श्री राज बहादुर : इस समय तक ५० ट्रक्स लिये जा चुके हैं और जैसे काम मिलता रहता है उनको काम में लगाया जाता है। ५० ट्रक्स और लिये जा रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अब तक के जो नतीजे हैं वे सन्तोषजनक हैं।

†**श्री बसुमतारी** : इसका ध्यान रख कर कि ज्वाइण्ट स्टीमर कम्पनी के चालकों ने हड़ताल की थी, क्या यह निगम संकटकाल में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए बनाया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : ठीक यही उद्देश्य है। हम पहिले से नहीं जान सकते कि पाकिस्तानी चालक क्या करेंगे और क्या उन्हें हड़ताल करने का कोई अवसर मिलेगा। यह योजना किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करने के लिए बनाई गई है।

†**श्री ए० बरुआ** : यदि निगम वाणिज्यिक दृष्टि से सुदृढ़ न हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देगी ?

†**श्री राज बहादुर** : आजकल यह केन्द्रीय सरकारी संगठन है। इसे परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत चलाने का विचार है। आर्थिक सहायता का प्रश्न अभी नहीं उठा है क्योंकि प्रथम परिणाम हमें उत्साहवर्धक लगते हैं। वास्तव में, हमारा विचार है कि यदि यातायात या सामान की आज की सी भी स्थिति बनी रहती है, तो यह ठीक से काम करता रहेगा।

†**श्री पे० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार का विचार इस निगम का क्षेत्र बढ़ा कर इसमें अन्य राज्यों, विशेषकर दक्षिण खण्ड में राज्यों को मिलाने का है जहां बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मूल प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है।

अलीगढ़ में कृषि औजार केन्द्र

†*७४६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पैकेज प्रोग्राम के अधीन अलीगढ़ में कृषि औजार केन्द्र चालू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिले में सुधारे हुये कृषि औजारों के प्रदर्शन और लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम को बढ़ावा

---

†मूल अंग्रेजी में

देने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अलीगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में एक कृषि औजार वर्कशाप स्थापित की गई है ।

पांच वर्षों की अवधि में वर्कशाप पर ५ लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । इसमें वर्कशाप की इमारतों के निर्माण और आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए १.४२ लाख रुपये का अनादर्ती व्यय तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और औजारों के बनाने के लिये सामान की प्राप्ति तथा औजारों और मशीनों के प्रतिस्थापन के लिये ३.५८ लाख रुपयों का आवर्ती व्यय सम्मिलित है । वर्कशाप विशेषतः इसी प्रयोजन के लिये नियुक्त एक कृषि इंजीनियर के अधीन होगी ।

वर्कशाप निम्नलिखित कामों के करने के लिये है :–

(क) जिले के लिये उपयुक्त कृषि औजारों में शिक्षात्मक और विकास कार्य करना ;

(ख) औजारों के क्षेत्र-परीक्षण का निरीक्षण करना ;

(ग) नये औजारों के आद्य रूपों का पर्याप्त संख्या में उत्पादन ताकि उनका प्रदर्शन किया जा सके तथा खाद्य उत्पादनों को बढ़ाने में उन का जो हाथ है उस का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सके ;

(घ) औजारों का विकास करने तथा मरम्मत करने में ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण देना तथा सुधारे गये औजारों का प्रयोग करने में किसानों और उन के पुत्रों को प्रशिक्षित करना ; और

(ङ) ट्रकों, जीपों, ट्रैक्टरों आदि गाड़ियों की मरम्मत करना जिन्हें कि इस कार्यक्रम में काम में लाया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : ये औज़ार वहां तैयार किए जा रहे हैं या बाहर से मंगा कर वहां भेजे जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : कुछ औज़ार बनाये भी जा रहे हैं और कुछ बाहर से आए हुए औज़ार भी वहां हैं क्योंकि प्रोटोटाइप बाहर से आया है ।

श्री यशपाल सिंह : दूसरे जो पैकेज सैंटर हैं, उनको कितनी तादाद में यहां से औज़ार भेजे जायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : दूसरे जो पैकेज के ज़िले हैं उन में और जो यहां पर बन रहे हैं वे, बहुत ज्यादा बन नहीं पाए हैं । अभी इस को खोला ही गया है । शाहबाद (बिहार), पाली (राजस्थान) और लधियाना (पंजाब) में ऐसे कारखाने बनाये गये हैं । बाकी हर ज़िले में एक एक कारखाना बनाने की बात है ।

श्री कछवाय : इस प्रकार के औज़ार क्या विदेशों से मंगाये जाते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : विदेशों से मंगाने की बात नहीं है । यह जो कारखाना चालू किया जा रहा है, खोला जा रहा है, इसका मूल मकसद यह है कि यहां या अन्य जगहों पर भी जो कुछ औज़ार बने हैं, उन को टैस्ट करके तथा उन की उपयोगिता को देख कर उन का प्रचलन किया जाए और उनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर नए तरीके के और अच्छे औज़ार बनायें और उन को जारी करें ।

श्री कछवाय : विदेशों से भी मंगाये जा रहे हैं, यह मेरा प्रश्न था ।

डा० राम सुभग सिंह : विदेशी इस में नहीं मंगाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : देश के पैकेज प्रान्तों में कृषि औज़ारों की कुल आवश्यकता कितनी है और पैकेज प्रान्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन का कुल लक्ष्य क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा कि मैंने एक अन्य अनुपूरक के उत्तर में कहा है, अभी हमने पूरा उत्पादन आरम्भ नहीं किया है क्योंकि ये सभी वर्कशापें अभी स्थापित ही की जा रही हैं ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्राक्कलन क्या हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह**: मुख्य विचार यह है कि हमें आद्य रूपों का विकास करना चाहिये, इन वर्कशापों के द्वारा औजारों को प्रमापीकृत करने का प्रयास करना चाहिये तथा उपयुक्त पाये जाने वाले औजारों के निर्माण के लिये सहकारी समितियां तथा अन्य निर्माताओं को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये । इस तरह समय पाकर सारी चीज नियमित हो जायगी । अभी तक ऐसे कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं कि लक्ष्य क्या होगा ।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की कृषि औजार समिति ने विशेषतः पैकेज प्रोग्राम वाले प्रान्तों के लिये सुधरे हुये औजारों की एक सूचि स्वीकृत की है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां, उस समिति ने कुछ औजारों की सिफारिश की है और वह हमने पैकेज प्रान्तों समेत सभी स्थानों पर परिचालित करवा दी है ।

रेलवे के लिये विश्व बैंक ऋण

†*७४७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के लिये विश्व बैंक से ५० करोड़ रुपये के ऋण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) ऋण के द्वारा किन योजनाओं को धन दिया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) विश्व बैंक की सह-संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ३२·१४ करोड़ रुपये के बराबर के ६७५ लाख डालर के ऋण के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ख) ऋण पर कोई व्याज नहीं लिया जायेगा परन्तु निकाली गई और अवशिष्ट राशियों पर ३/४ % प्रति वर्ष का सेवा-भार लिया जायेगा । ऋण ५० वर्षों में वापिस किया जाना है तथा पुनर्भुगतान १० वर्षों की अवधि के बाद आरम्भ होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) ऋण रेलवे सामग्री और उपकरण प्राप्त करने के लिए है मुख्यत: इंजन-डिब्बे आदि जैसे कि भाप और बिजली के इंजन और डिब्बे तथा रेल की पटरियों के लिये सामग्री और अन्य उपकरणों के देशीय निर्माण के लिये पुर्जे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्तमान ऋण समेत भारतीय रेलवे द्वारा १९५१-५२ से ले कर विश्व बैंक से कितना ऋण लिया गया है और उसमें से कितना वापिस दे दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रश्न के दो भाग हैं। जहां तक विश्व बैंक से लिये गये ऋणों का सम्बंध है, वे लगभग १८० करोड़ रुपये के बनते हैं। दूसरे भाग के सम्बंध में वित्त मंत्रालय से पूछा जाए।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना की क्रियान्विति से रेल की पटरी की लम्बाई तथा भाप इंजनों के स्थान पर डीजल या बिजली के इंजन लाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह ऋण तीसरी योजना की आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिये है जोकि इस प्रकार है :

नई लाइनें लगभग १,९२० किलोमीटर होंगी; लाइनों का दोहरा किया जाना ३,९२८ किलोमीटर; पटरी का नवीकरण १२,००० किलोमीटर ; विद्युतीकरण २,५०० किलोमीटर।

†**श्री मुरारका** : तीसरी योजना के दौरान रेलवे के लिये विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता क्या है तथा उसमें से कितनी पूरी कर ली गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता के २४९ करोड़ रुपये होने की संभावना है और अभी तक हमने लगभग १६७·४२ करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं तथा ३३·३ करोड़ रुपयों की हमें इस वर्ष में मिल जाने की आशा है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : मैं जानना चाहती हूं कि क्या उपकरण प्राप्त करने में सरकार को कोई कठिनाइयां हुई थीं ? क्या ऐसे उपकरणों के चुनाव में पूरी छूट है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जहां तक विश्व बैंक का सम्बंध है, सदस्य देशों से खरीद की जा सकती है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण का सम्बंध है, इसे अमरीका में खरीदा जाना चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सामने कितनी मांग रखी गई थी और कितनी स्वीकृत हुई थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सामने हमारी कुल निर्धारित मांग रखी गई थी और जैसा कि मैंने कहा हमें ३२ करोड़ रुपये मिले। इस के अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने अन्य ऋणों के बारे में भी बातचीत की है जिस की कुल राशि १६·५ करोड़ रुपये होगी जिस से कि हमारी वर्तमान आवश्यकतायें पूरी होंगी।

सरकार द्वारा गेहूं की खरीद

+

†*७४८. **श्री राम हरख यादव** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी फसल के दौरान मूल्यों में स्थिरता रखने के लिये गेहूं खरीदने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा इस को किस मूल्य पर खरीदने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) से (ग) सरकार ऐसा करने का इरादा रखती है । सुकरता और ब्योरों की अभी जांच हो रही है ।

श्री हेडा : क्या कृषि मंत्रालय भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के समान सोच रहा है जिन्हों ने कहा था कि वे पटसन का मूल्य निर्धारित करेंगे और अगले सोमवार उस की घोषणा करेंगे और यदि हां, तो और किन वस्तुओं के मूल्यों की घोषणा की जाएगी ? क्या मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता रहेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : हम ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से परामर्श किया था । सोमवार को जो भी घोषणा की जायेगी वह हमारी सहमति से भी होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह योजना उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की स्थिरता योजना का भाग है और यदि हां, तो गेहूं का मूल्य किस स्तर पर निर्धारित किया जायगा ?

†**श्री शिन्दे** : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्यों के बारे में सरकार के पिछले अनुभव का ध्यान रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब कृषि उत्पादों के लिये मूल्य निर्धारण का एक स्थायी निकाय बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने की स्थिति में है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : उस पर हम बहुत विचार कर रहे हैं । परन्तु उस के अतिरिक्त गेहूं का मूल्य फसल से पहले ही समय पर घोषित कर दिया जायेगा । विलम्ब केवल इस कारण है कि मैं इसे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जो कदम उठाया जा रहा है, यह क्या अपने ढंग का सब से पहला कदम है या इससे पहले भी कभी गेहूं खरीदा गया था ? अगर खरीदा गया था तो उससे क्या अनुभव प्राप्त हुआ, अर्थात् कितना किसानों को लाभ हुआ या कितनी सरकार को हानि हुई ?

श्री स० का० पाटिल : गेहूं खरीदने की जरूरत इसलिए महसूस हुई है कि हम स्टाक रखना चाहते हैं । अब तक हम ने नहीं रखा था, फारेन व्हीट से ही हम ने अपना स्टाक बनाया था । लेकिन हर साल उस स्टाक को बदलना पड़ता है । अब हम गेहूं खरीद कर के स्टाक बनाना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने जा रही है और क्या मूल्य पारिश्रमात्मक होंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : क्या 'पारिश्रमात्मक' है और क्या व्यावहारिक है, इसमें हम सीमा निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु मेरी अपनी इच्छा है कि वे पारिश्रमात्मक के इतना निकट हों जितना कि बताना मेरे लिए संभव है ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या प्रदेशों की सरकारें भी व्हीट की खरीद करेंगी विशेष कर वे सरकारें जहां पर अधिक अन्न की उपज होती है ?

†**श्री शिन्दे** : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उन सम्बन्धित सरकारों का ध्यान जहां विशेषकर गेहूं आदि उगाया जाता है आवश्यकता पड़ने पर उपाय करने की ओर दिलाया है।

श्री कछवाय : इस समय कितने गल्ले की खरीद का लक्ष्य आप ने अपने सामने रखा है और पिछला कितना खरीदा हुआ है ?

श्री स० का० पाटिल : ऐसा है कि जब कोई दाम निश्चित होता है और वह कभी उस से नीचे चला जाय तब गवर्नमेंट मार्केट में जाती है । जब तक ऐसी चीज नहीं होती है तब तक खरीदने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है । मैं नहीं मानता हूं कि इस देश में ऐसी कोई आवश्यकता आयेगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि किसानों से जो गल्ला खरीदा जाता है और अमरीका से जो गेहूं सरकार खरीदती है उन के रेट्स में कितना अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : आयात किये गये गेहूं का यहां आने तक का मूल्य लगभग १५ रुपये बैठता है ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं समझ नहीं पाया ।

†**श्री अ० म० थामस** : १५ रुपये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल्यों की तुलनात्मक दर क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता ही चुके हैं कि हम वर्तमान समाहार मूल्य को बढ़ाने की सोच रहे हैं । गेहूं की साधारण श्रेणी का वर्तमान समाहार मूल्य ३४८३ रुपये प्रति क्विंटल है ; लाल गेहूं का ३२·१५ रुपये प्रति क्विंटल है; अधिक बढ़िया किस्म का ३७·५१ रुपये प्रति क्विंटल होगा ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस उपाय के परिणामस्वरूप जिन राज्यों में फालतू गेहूं है उन से अन्य राज्यों को बिना सरकारी नियंत्रण या रोक-टोक के गेहूं जाने दिया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक गेहूं के जाने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि अब भी हम ने इसे एक खंड बना दिया है । प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या हम मूल्य निर्धारित कर के गेहूं खरीदने जा रहे हैं । मैंने कहा था कि हम ऐसा करना चाहते हैं और समय पर करना चाहते हैं । परन्तु जहां तक गेहूं के ले जाने का सम्बन्ध है, उसकी अब भी अनुमति है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पु० र० पटेल** : हाल ही में यह उत्तर दिया गया है कि जो मूल्य निर्धारित किया जायेगा वह पारिश्रमात्मक मूल्य के बहुत निकट होगा । मैं कृषकों को न्यूनतम पारिश्रमात्मक मूल्य देने के सम्बन्ध में तीसरी योजना में दिये गये वचन के बारे में जानना चाहता हूं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : 'पारिश्रमात्मक' शब्द विवेचना का विषय है । माननीय सदस्य जिसे पारिश्रमात्मक कहते हैं, हो सकता है कोई दूसरा उसे पारिश्रमात्मक न समझता हो । अतः मैं ने "पारिश्रमात्मक के इतना निकट जितना कि हम संभवतः कर सकते हैं" कह कर अपना बचाव किया था ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्य में वर्तमान वृद्धि के बारे में जानती है और क्या सरकार के पास इसके लिये कोई योजना है, कि मूल्य कम हो जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह यहां संगत नहीं है । अगला प्रश्न ।

दिल्ली में रेल संग्रहालय

*७४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि **दिल्ली** में एक रेल संग्रहालय स्थापित करने के बारे में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): देश की वर्तमान आपातिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने स्थायी प्रदर्शनी का संगठन और आयोजन मुल्तवी कर दिया है । प्रस्तावित रेल संग्रहालय इसी प्रदर्शनी के एक अंग के रूप में स्थापित किया जाना था।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मैं जानता हूं इस के बारे में कुछ वर्षों पहले से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी । तो जो कार्रवाई शुरू कर दी गई थी क्या उसे भी समाप्त किया जा रहा है या उसे स्थगित किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : वह वहां पर है वहीं रहेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस संग्रहालय में किस तरह की चीज़ों का संग्रह किया जायेगा ? क्या उस में उन व्यक्तियों के चित्र तथा उनकी मूर्तियां भी स्थापित की जायेंगी जिन्होंने रेलों के निर्माण में या विस्तार में भाग लिया है, और क्या हमारे भूतपूर्व मंत्रियों के चित्र भी उस में होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य की तजवीज़ बहुत मुनासिब है और इसके ऊपर अमल किया जायेगा । लेकिन अब तक हमारा इरादा यह था कि जो रिसर्च रेलवे में की गई है उसकी नुमाइश की जाय, और जो रेलवेज़ ने तरक्की की है या जो बड़े बड़े काम वह कर रही है उसकी प्रदर्शनी या नुमाइश की जाय ।

बर्मा से लकड़ी के स्लीपरों का आयात

+

*७५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बर्मा से लकड़ी के स्लीपरों का आयात कर रहा था तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्मा ने अब स्लीपरों का देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) बर्मा स्टेट टिम्बर बोर्ड के साथ जो ठेके किये गये हैं, उनके अधीन बर्मा ने लकड़ी के स्लीपर दिये हैं और उसने किसी समय स्लीपर देना बन्द नहीं किया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) बर्मा स्टेट टिम्बर बोर्ड ने भारतीय रेलवे को और टिम्बर बेचने की इच्छा प्रकट की है और रेलवे बोर्ड इस पर विचार कर रहा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस टिम्बर बोर्ड के साथ कोई बातचीत चल रही है जो बर्मा में टिम्बर व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बाद बनाया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वहाँ टिम्बर व्यापार के राष्ट्रीयकरण हो जाने का मुझे पता नहीं है परन्तु हम बर्मा स्टेट टिम्बर बोर्ड के साथ व्यौहार करते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि बर्मा से कितनी मात्रा में स्लीपरों का आयात किया गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमने १९५७ में क्रयादेश (आर्डर) दिया था और हमें १,७४,७५० घन फुट प्राप्त हुये । हमने अब विशेष प्रकार की लकड़ी के लिये क्रयादेश दिया है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह नहीं सोचती कि भारत के समृद्ध वन संसाधन रेलवे के लिये आवश्यक स्लीपरों का संभरण करने की स्थिति में नहीं है और क्या बर्मा से स्लीपर आयात करना आवश्यक समझा जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसमें सन्देश नहीं कि यहाँ पर वन हैं परन्तु वे सारी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं विशेषकर सख्त टिम्बर जिसकी कि हमें प्वाइंट्स और क्रासिंग्स आदि जैसे विशेष काम के लिये जरूरत है । यह सख्त टीक लकड़ी होती है और उसका आयात करना ही पड़ता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं क्या बर्मा से स्लीपरों के आयात में कुछ विदेशी मुद्रा भी लगती है और यदि ऐसा है तो स्वयं देश में ही, विशेषत: मेरे राज्य जम्मू तथा काश्मीर में, टिम्बर के संभरण को तेज करने और बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वहाँ सख्त टिम्बर पैदा होता है ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : हाँ ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसा कि मैंने कहा यह एक विशेष किस्म की लकड़ी थी जो कि हमने बर्मा से मंगवायी....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैंने पूछा था कि क्या बर्मा से स्लीपरों का आयात करने में कोई विदेशी मुद्रा लगती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई विदेशी मुद्रा लगती है और जम्मू तथा काश्मीर में इसे पैदा करने के प्रयत्न क्यों नहीं किये जा रहे हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : काश्मीर में उस किस्म की लकड़ी उपलब्ध नहीं है। वहाँ तो केवल बहुत ही नरम सी लकड़ी मिलती है। वित्त मंत्रालय ७५ लाख रुपये देने के लिये तैयार हो गया है।

†**श्री बसुमतारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे विभाग ने जाँच की है और पाया है कि साल के स्लीपर बर्मी स्लीपरों से अधिक पक्के हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम उतना ही साल की लकड़ी खरीदना पसन्द करेंगे जितना कि राज्य सरकार दे सकेगी।

श्री काशी राम गुप्त : जो बर्मा की सस्त टिम्बर है यदि उस तरह की टिम्बर भारतवर्ष में नहीं होती तो उसकी जगह पर आयरन या सीमेंट के स्लीपर क्यों न चलाये जायें जिससे फारेन एक्स्चेंज बचे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हाँ, तीसरी योजना में हमें कुल लगभग ४७५ लाख स्लीपरों की आवश्यकता होगी जिनमें से १५ लाख इस्पात के बनायेंगे, २३५ लाख ढलवाँ लोहे के और लकड़ी के स्लीपर केवल १७५ लाख होंगे।

†**डा० क० ल० राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में विकसित प्रविधियों से स्लीपरों के लिये भारतीय जंगलों का प्रयोग करना संभव होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : भारतीय जंगलों का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि जम्मू तथा काश्मीर से आने वाला टिम्बर नरम है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जानती है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस बात पर बल देती रही है कि यदि रेलवे को वनीय क्षेत्रों के यथासंभव समीप ले आया जाये तो वे देवदार जंगलों से सस्त से सस्त टिम्बर बना सकते हैं जो कि बहुत सा बनाया भी जा रहा है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जम्मू तथा काश्मीर से हम बहुत सा खरीद रहे हैं।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि आँध्र प्रदेश समेत कुछ राज्य सरकारों ने बर्मा जैसी बढ़िया टिम्बर देने को कहा है परन्तु बढ़ी हुई परिवहन लागत के कारण वे भारत में प्रचलित मूल्य से कुछ अधिक परन्तु बर्मा की टिम्बर के आयात मूल्य से कम मूल्य चाहते थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं कहना चाहता हूं कि आँध्र प्रदेश ने जितने संभरण के लिये कहा है वह अन्य राज्यों से बहुत कम है। प्रश्न लागत का नहीं है। कठिनाई तो आँध्र प्रदेश में टिम्बर की उपलब्धता की है।

श्री कछवाय : पिछले दिनों समाचार पत्रों में आया था कि काश्मीर से बहुत से स्लीपर हमारे पाकिस्तान की तरफ बह गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वह कितने थे और उनको लौटाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रानेन सेन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम बर्मा के अतिरिक्त अन्य देशों से भी लकड़ी के स्लीपर आयात करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहाँ हमारा संबंध केवल बर्मा से है।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नरम लकड़ी के तेल दिये हुये स्लीपर सख्त लकड़ी के स्लीपरों से अधिक समय तक चलते हैं और वे उपलब्ध हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमें इसे क्रिसोट देते हैं। भारत के विभिन्न भागों में चार ऐसे संयंत्र हैं ।

आदर्श गांव

†*७५१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोग तथा प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिये आदर्श गाँवों की कोई योजना चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों और विस्तार विशेषज्ञों की सहायता से मामले का अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह उन्हीं के परामर्श पर है कि सरकार ने किसी भी ऐसे प्रस्ताव को हाथ में नहीं लिया है अथवा ऐसे अध्ययन के विरुद्ध जाते हुये इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वस्तुतः इस बात का बड़े ध्यान से अध्ययन किया गया था। सच तो यह है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय आदर्श गाँवों के लिये कुछ पुरस्कार देता है। परन्तु वास्तविक कृषि क्षेत्र में परामर्श लेने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रयोग अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिये आदर्श गाँव बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अतः हम कृषकों के खेतों में ही प्रदर्शन कर रहे हैं तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विचारों का प्रचार करने के लिये हम इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस सामग्री तथा विशेषज्ञों के मतों के आधार पर यह निर्णय किया गया था क्या सरकार उन्हें सभा पटल पर रखने अथवा सदस्यों में परिचालित करने के लिये राजी होगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में हम प्रति दिन परामर्श लेते हैं और जो कोई सामग्री भी उपलब्ध होगी उसे सभा पटल पर रखने से हमें खुशी ही होगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इसे आश्वासन समझा जाये ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हाँ, हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी राम गुप्त : क्या सरकार इसराइल के अनुभव से फायदा उठाने का विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : इसराइल के अनुभव को थोड़ा तो मैं जानता हूं। वहाँ बड़े मेहनती लोग हैं और वे डेजर्ट में भी काम करते हैं। उसका हम लोग उपयोग करेंगे और खासकर के पर्वतीय इलाके में जरूर करेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भी ऐसे आदर्श गाँव बनाने का प्रयत्न कर रहा है, यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उनकी सहायता करेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : परन्तु दोनों कामों के रूप में बड़ा अन्तर है। हमारा काम खेत से संबंध रखता है। हमारे प्रदर्शन खेत होंगे और हम अधिक से अधिक ऐसे प्रदर्शन खेत बनाने जा रहे हैं। इस वर्ष हम ऐसे खेतों की संख्या ३०० प्रतिशत तक बढ़ाने वाले हैं—इस समय के एक लाख प्रदर्शन खेतों से तीन लाख तक बढ़ाने वाले हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग वाले लोग क्या करने जा रहे हैं यह मैं नहीं जानता।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक गाँव आदर्श होगा, तो क्या उसके आस-पास के गाँव आदर्शहीन नहीं हो जायेंगे और क्या यह सरकार की समाजवादी भावना के खिलाफ नहीं होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : इसीलिये तो हम नहीं कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गाँवों में प्रदर्शन फार्मों का काम इस समय पूर्णतः खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है अथवा यह सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में सारा काम सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पूरे सहयोग के साथ करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम ग्रामसेवकों की सहायता नहीं लेंगे तब तक कोई प्रदर्शन फार्म स्थापित करना संभव नहीं होगा। अतः अन्य एजेंसियों का सहयोग तो होगा ही परन्तु निर्देशन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का होगा।

†**श्री बालकृष्णन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जानती है कि कुछ वर्ष पूर्व आदर्श गाँवों का एक सर्वेक्षण हुआ था ; यदि हाँ, तो क्या वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन किया गया था अथवा किसी अन्य मंत्रालय के अधीन ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण आवास बोर्ड ने कभी विचार किया है कि किस प्रकार के आदर्श गाँव होने चाहियें तथा कृषकों और कृषिकार श्रमिकों के लिये किस प्रकार के मकान होने चाहियें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमारे पास वह जानकारी नहीं है। इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

खराब हुये खाद्यान्नों की बिक्री

†*७५२. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) बम्बई के टेंडर नोटिस संख्या ७/१/६३, दिनांक १७ मार्च, १९६३ के अनुसार बम्बई नगर, कांडला तथा अन्य जिला गोदामों से बड़ी मात्रा में खराब हुये खाद्यान्नों की बिक्री के लिये टेंडर आमन्त्रित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो बिक्री की शर्तें तथा ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) खाद्यान्न के खराब होने तथा बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) टेंडर की एक कापी पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०७७/६३**] टेंडर में विक्रय की शर्तें और विक्रय के लिए वस्तुओं का ब्यौरा दिया है।

(ग) ये खाद्यान्न मुख्यकर जहाज-यात्रा में खराब हो गये थे। मानव-प्रयोग के लिए अनोपयोगी होने के कारण, इन्हें ढोर/मुर्गियों आदि के भोजन, खाद या माढ़ बनाने के लिए रखा गया है यह प्रयोग स्टाक की स्थिति पर निर्भर है और इन खाद्यान्नों को इन्हीं विशिष्ट प्रयोगों के लिए बेचा जायेगा।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस सौदे में क्षति के कारण कितनी हानि हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे बेचे न जाने तक वह यह कैसे कह सकते हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: क्षति मुख्यकर जहाज-यात्रा में हुई है और इसके कारण हमारे नियन्त्रण से बाहर थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न हानि की मात्रा के बारे में था।

†**श्री अ० म० थामस** : मेरे पास वर्तमान मामले में क्षतिग्रस्त किस्म के बारे में भाण्डागार हानियों की मात्रा सम्बन्धी अनेक आंकड़े हैं यह मात्रा बम्बई में ८६२ टन, काण्डला में १,२६२ टन और अन्य जिला गोदामों में ११० टन।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह देखने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि क्षतिग्रस्त खाद्यान्न बाजार में मानव प्रयोग के लिए न बेचा जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सावधानियां एक विवरण में दी हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : टेंडर में भी उनका उल्लेख है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस क्षति से कितना खाद्यान्न बेकार हुआ है।

†**श्री अ० म० थामस** : मेरे पास आंकड़े हैं। यह बड़ी नगण्य मात्रा है। १९६१–६२ में ०.४८० प्रतिशत रहा है, जिसमें बाढ़ से हुई क्षति भी सम्मिलित है। १९६०–६१ में यह प्रतिशत ०.१३६ था, बहुत ही नगण्यमात्रा, जबकि कुल मात्रा ४,५०,००० टन थी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मन्त्री जी ने बताया है कि टेण्डर मांगे गये हैं ताकि पशु प्रयोग के लिए खाद्यान्न बाजार में बेचा जा सके। क्या इसकी डाक्टरी परीक्षा की गई थी कि क्या इन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के प्रयोग का ढोरों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : हमारे पास कुछ टैक्निकल कर्मचारी हैं जिन्होंने वर्गीकरण किया है कि कौन अन्न किस के लिए उचित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब विवरण में दिया है ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या क्षति के फलस्वरूप हानि कुछ अचानक परिस्थितियों के कारण हुई या उचित दूरदर्शिता के अभाव के कारण हुई ?

†**श्री अ० म० थामस** : क्षति मुख्यकर जहाज-यात्रा में हुई थी ।

सघन कृषि कार्यक्रम

†*७५३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रत्येक राज्य में चार जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय चालू "पैकज प्रोग्राम" योजना और इसमें क्या अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं । फिर भी, भारत सरकार ने निम्न वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन-कृषि के प्रोग्राम की सिफारिश की है :

(१) ४० जिलों में चावल; (२) १०० जिलों में ज्वार बाजरा और दालें; (३) १९ क्षेत्रों में कपास; (४) २४ यूनिटों में मूंगफली; और (५) आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार के सीमान्त राज्यों में सब्जियां ।

(ख) दो प्रोग्रामों में अन्तर यह है कि "पैकेज" योजना का उद्देश्य चुने हुए जिलों में सभी मुख्य फसलों और व्यापारी फसलों का उत्पादन बढ़ाने का है, तो गहन कृषि प्रोग्राम एक पण्य-वस्तु के बारे में विचार करता है । आगे, गहन कृषि प्रोग्राम 'पैकेज' प्रोग्राम के प्रतिकूल विदेशी सहायता (टैक्निकल तथा वित्तीय) के बिना ही लागू किया जायेगा । इसके लिए पैकेज जिलों में कर्मचारियों की अपेक्षा थोड़े कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : क्या सरकार ने इस प्रोग्राम के आरम्भ होने से अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा निर्धारित की है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस पहलू की परीक्षा की जा रही है । स्वाभाविक है कि हम मामले पर कार्यवाही करने से पहिले हर बात की जांच करेंगे ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : इस कार्य के लिए कितना अतिरिक्त धन दिया जायेगा?

†**डा० राम सुभग सिंह** : योजना आयोग ने निम्न अतिरिक्त आवंटन का सुझाव दिया है: आन्ध्र प्रदेश १०० लाख रु०, आसाम ३० लाख रु०, बिहार १०० लाख रु०, महाराष्ट्र ४०० लाख रु०, आदि । मैं यह पटल पर रख दूंगा, क्योंकि यह सूची बड़ी लम्बी है ।

†**श्री बसुमतारी** : "पैकेज" प्रोग्राम और "गहन" प्रोग्राम में क्या अन्तर है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी प्रश्न का तो उत्तर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रात्रि विमान डाक सेवायें

*७५४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा गत अक्तूबर में चालू की गई रात्रि विमान डाक सेवा की नई व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पुरानी व्यवस्था को पुनः चालू करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि रात्रि विमान सेवा का यात्री यातायात गत पांच वर्षों में स्थिर सा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). चार मुख्य नगरों, अर्थात्, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बीच १ अक्टूबर, १९६२ को प्रयोगात्मक रूप में चालू की गई सीधी विस्काउन्ट सेवाओं से कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, इस कारण इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन ने १ मार्च, १९६३ से पुराने ढंग की रात्रि विमान डाक सेवायें पुनः आरम्भ कर दी हैं।

(ग) जी हां।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पुराने ढंग की रात्रि विमान डाक सेवा स्काईमास्टरों विमानों से कुछ अन्य विमानों से पुनः आरम्भ की गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हां, अधिकतर स्काई मास्टर विमानों से। कदाचित् एक मात्रा पर जहां आवश्यक होता है विस्काउण्ट विमान भी प्रयोग किया जाता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि रात्रि विमान डाक सेवा में इस कारण भारी हानि होती है कि स्काईमास्टर विमान दोनों अधिक वस्तु परिवहन तथा अत्यधिक यात्री-यातायात को लम्बे मार्गों पर पूरा नहीं कर सकते ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : अभी तो, कठिनाई विमानों की उपलब्धि की है। यदि अधिक मितव्ययी विमान उपलब्ध हों, तो इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन सहर्ष ऐसा करेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैंने पूछा था कि क्या इस अभाव के कारण भारी हानि होती है ? वह 'हां' या 'न' कह सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हानियां हो रही हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे निश्चित रूप से विदित नहीं है कि क्या किसी विशेष मार्ग पर एक विमान के चलने से हानि होती है या नहीं। हां, उतार व चढ़ाव होते रहे हैं। तीन वर्ष पूर्व, रात्रि विमान डाक सेवा काफी लाभप्रद थी। नवीनतम आंकड़ों के बारे में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी**: माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया था कि इसे इसके लाभप्रद न होने के कारण बन्द कर दिया गया। यह भी बताया गया था कि कुछ विमान जो लाभदायक या मितव्ययी हो सकते हैं, उपलब्ध नहीं हैं। इस नई सेवा को त्यागने का मुख्य कारण क्या है, अनोपलब्धता या उनका लाभप्रद न होना ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : आजकल, सेवा इसलिए बदली गई कि पिछले अक्टूबर में चालू की गई सेवा अलाभप्रद थी। माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि १ अक्टूबर से चालू की गई सेवा यह थी कि दो मुख्य

---

†मूल अंग्रेजी में

नगरों के बीच सीधी उड़ान होगी। पहले तरीके के अनुसार मुख्य नगरों का मिला जुला 'लोड' एक स्थान से नागपुर ले जाया जाता है और फिर वे विभाजित हो जाते हैं। बड़ा अन्तर है।

संयुक्त खेती

†*७५५. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त खेती पद्धति प्रयोग के रूप में देश के सभी राज्यों में लागू कर दी गई है ; और

(ख) क्या उन सभी राज्यों में जिनमें यह योजना आरम्भ की गई है किसानों ने इसमें रूचि दिखाई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):** (क) जी हां, किसानों को सहकारी संयुक्त खेती के लाभ दर्शाने के लिये सभी राज्यों में अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। तीसरी योजना में प्रति जिला एक के हिसाब से ३२० अग्रिम परियोजानाएं आरम्भ की जानी हैं। अब तक १३७ परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं, और ६५७ सहकारी खेती संस्थाएं संगठित की जा चुकी हैं।

(ख) यद्यपि कार्यक्रमों का मूल्यांकन या किसानों का मतसंग्रह अभी तक नहीं किया गया, अग्रिम और दूसरी संस्थाओं के अध्ययन से यह बात पता लगा है कि इन सहकारी खेती संस्थाओं ने कृषि उपज बढ़ाने में छोटे और सीमांत किसानों की सहायता की है और उन लोगों में बड़ी सकल सिद्ध हुई हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** कृषि मंत्रालय के सहयोग से क्या कदम उठाये गये हैं ताकि किसानों को प्रोत्साहन देकर संयुक्त खेती करने के लिये प्रेरित किया जा सके ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त हमने संस्थाओं को अंशपूंजी काम चलाने के लिये ऋण और सहायता के रूप में प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** अब तक जो संयुक्त खेत बनाये गये हैं, वे दूसरे खेतों की तुलना में कैसे चल रहे हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** अभी तक तीसरी योजना म लगभग १४०० खेती संस्थाएं आरम्भ हुई हैं। सरकार की ओर से किये गये सीमित अध्ययन से यह पता चला है कि उत्पादन उत्तम है और रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

श्री सरजू पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो ज्वाइंट फार्म स्थापित किये गये थे उनमें से बहुत सारे टूट गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको फिर से बनाने का विचार कर रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : सरकार को मालूम है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में पहली और दूसरी योजना में जो ढाई हजार सोसाइटीज थीं उनमें से कई खराब थीं। जो खराब थीं उनको वीड आउट करके अब १४०० की लिस्ट बना ली गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और इन सोसाइटीज को योजना के अनुसार मदद दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने आधुनिक आर्थिक विचारधारा में आधुनिकतम प्रवत्ति की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है कि कृषि-जन्य उत्पादन समाजवादी ढंग के तरीकों के लिये अनुकूल नहीं है ?

†**श्री पे० वेंकटासुब्बया** : इस बात की दृष्टि से कि साझी खेती के लिए भूमि की चकबन्दी पूर्व आवश्यकता होती है क्या इस दशा में कोई कार्रवाही की गई है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि की चकबन्दी करने को कहा गया है। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि पहले चकबन्दी हो अभी-तभी सहकारी खेती हो सकती है।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सरकार ने काफी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है कि इस प्रकार के कृषि उत्पादन से समाजवादी विचार बढ़ता है।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो १४०० फार्म खोले हैं उनमें किसी को ट्रेक्टर सप्लाई किया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी हां, महाराष्ट्र की कुछ सोसाइटीज में ट्रेक्टर सप्लाई किया गया है।

†**श्री पु० र० पटेल** : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इस संयुक्त खेती के लिये अर्थ सहायता और ऋण तथा अंशपूंजी के लिये कितनी राशि लगाई गई है ? क्या संयुक्त खेती में उत्पादन उसी आकार की लोगों द्वारा की गई खेती की तुलना में अधिक है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मुख्य प्रश्न में बताया गया है कि अभी तक कोई क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया गया। किन्तु एक सीमित अध्ययन से पता चला है कि उत्पादन अधिक है। वास्तव में, हम स्वयं गये हैं, अफसर गये है, संसद सदस्य ८ दलों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर इन चार राज्यों में गये हैं और उन्होंने यह भी सूचना दी है कि कुछ राज्यों में उत्पादन २५ से ५० प्रतिशत तक अधिक है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या सरकार ने यह परियोजना आरम्भ करते हुए, ऋण या अन्य चीजों के रूप में सहायता का कोई ढंग निकाला है। जिससे किसान संयुक्त खेती करने की ओर आकर्षित हों ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : अंश पूंजी के रूप में सहायता है जो लगभग २००० रुपये तक जाती है, कार्यकारी पूंजी ४००० रुपये तक होती है, गोदाम ऋण ५००० रुपये तक तथा लगभग १२०० रुपये तक अर्थ सहायता होती है।

चीनी का निर्यात

†*७५६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में निर्यात के लिये निर्धारित चीनी में से कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात (१) राज्य व्यापार निगम तथा (२) भारतीय चीनी मिल संस्था के द्वारा किया जायेगा ; और

(ख) इसमें से कितनी मात्रा का निर्यात वस्तु विनिमय आधार पर किया जायेगा तथा उसके बदले में किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)**: (क) ३.६ लाख मीट्रीक टन चीनी की बिक्री के संबंध में राजकीय व्यापार निगम द्वारा तथा ६३००० मीट्रिक टन भारतीय चीनी मिल संस्था द्वारा बातचीत की गई है ।

(ख) ३ लाख मीट्रिक टन प्राप्त चीनी के ५० प्रतिशत का उर्वरकों, जस्ता घोलक गूदा, कच्चा ऐस्बैस्टस और गन्धक का आयात करने के लिये उपयोग किया जायेगा ।'

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमको कितनी कम चीनी का एक्सपोर्ट करना है ?

†**श्री शिन्दे** : इस वर्ष हम गत वर्ष की तुलना में अधिक निर्यात कर रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि शुगर की सेल बढ़ रही है या घट रही है ?

†**श्री शिन्दे** : यदि वह आन्तरिक बिक्री का उल्लेख करते हैं, तो वे भी बढ़ रही हैं । जहां तक अन्त-राष्ट्रीय व्यापार का संबंध है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये भी चीनी की बड़ी मांग है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस दृष्टि से कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन कम हो गया है, क्या इस वर्ष किसी प्रकार से निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा और यदि हां, तो कितनी चीनी निर्यात की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: ये निर्यात आंकड़े हैं जिनके लिये सौदा तय हो चुका है । भारी निर्यात तब तक नहीं किया जायेगा जब तक हमें अगलें वर्ष उत्पादन का स्वरूप न पता लगे ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख**: चीनी के रा०व्या०निगम के निर्यात का कितना अंश सहकारी संस्थाओं के लिये आरक्षित है और निर्यात के लिये दानेदार चीनी के लिये कितना अंश आरक्षित है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: यह प्रत्येक फैक्टरी के उत्पादन के अनुपात में है, चाहे वह सहकारी चीनी फैक्टरी हो या अन्यथा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय नौवहन समवाय द्वारा जहाजों की खरीद

†*७४३. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय नौवहन समवाय ने कोई जहाज खरीदा है जो चीन को किराये पर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जयन्ती नौवहन समवाय ने ब्रिटेन की फर्म कोर्ट लाइन लिमिटेड से पांच जहाज खरीदे थे जिनमें एक बैरिंगटन कोर्ट चीन को किराये पर था । वह जहाज किराया भाड़ा से मुक्त भारतीय समवाय को दिया जाना था । यह भाड़ा भार से मुक्त मिलने पर भारतीय जहाज के नाते पंजीबद्ध किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिलीगुड़ी-जोगीगोपा रेलवे लाइन

†*७५७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती बसन्त कुमारी :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में सिलीगुड़ी तथा जोगीगोपा के बीच बड़ी लाइन बनाने की योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या काम शुरू कर दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). सीलीगुडी के समीप से आसाम में जोगी गोपा तक एक ब्राड गेज लाइन के लिये अन्तिम स्थान सर्वेक्षण मंजूर हो चुका है। लाइन का निर्माण आरम्भ करने की मंजूरी सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर होगी। इस काम पर लगभग ३२ करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

'एयर लेंस'

†*७५८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमान मार्गों पर विमानों के मार्गदर्शन के लिए 'एयर लेंस' निर्धारित करने तथा सुरक्षा उपाय लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन मार्गों पर ये लागू किये जायेंगे ;

(ग) क्या अपेक्षित उपकरण प्राप्त कर लिये गये हैं, तथा यदि हां, तो कहां से ; और

(घ) इस संबंध में अब तक और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). जी हां, मुख्य ट्रेक मार्गों के साथ-साथ तथा देश के पार यातायात के आसानी से आने जाने के लिये एयर वैज प्रणाली जारी करने का विचार है।

(ग) और (घ). मार्गों पर कुछ स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हैं। अतिरिक्त उपकरण की जरूरत होगी। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रंक टेलीफोन लाइनें

†१५१४. **श्री कर्णोसिंह जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी और महत्वपूर्ण राज्य राजधानियों तथा जयपुर जैसे महत्व के स्थानों के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइनों में बराबर गड़बड़ी होती रहती है, उदाहरणार्थ २५ फरबरी, १९६३ को जब कि जयपुर और बीकानेर दोनों के लिए लाइनें बहुत देर तक खराब रहीं; और

(ख) यदि हां, तो इन बार-बार की गड़बड़ों को रोकने के लियेसरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) सरकार को पता है कि कई बार ट्रंक लाइनों पर गड़बड़ी होती है। इनका कारण कुछ अनिवार्य कारण होते हैं; चाहे बवण्डर, गर्ज के साथ वर्षा, तांबे के तारों की चोरियां, आदि। जहां तक इस बात का संबन्ध है २५-२-६३ को जयपुर और नई दिल्ली के बीच की लाइनों में गड़बड़ का कारण यह था कि नई दिल्ली से ४६ किलोमीटर की दूरी पर पंक्तिबंधन के नीचे कुछ मकानों में आग लग गई थी।

(ख) ऐसी गड़बड़ी बिलकुल तो रोकी नहीं जा सकती। यदि किसी पंक्तिबंध विशेष कर गड़बड़ी की बारम्बारता अधिक देखी जाती है, तो विशेष जांच करवाई जाती है और साधनों की उपलब्धि के साथ समुचित कार्यवाही की जाती है।

डीजल इंजन

†१५१५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या तीसरी योजना अवधि के अन्त तक डीजल इंजनों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) तीसरी योजना के अन्त तक डीजल इंजनों की अनुमानित आवश्यकता इस प्रकार थी :—

	डीजल मेन लाइन इंजन	डीजल शंटिंग इंजन	कुल
ब्राड गेज . . .	४४०	१०३	५४३
मीटर गेज . . .	१६७	..	१६७
नैरो गेज . . .	६८	..	६८

उड़ीसा में कृषि की उन्नति

†१५१६. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में खेती की उन्नति के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी रकम मंजूर की गयी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). १९६२-६३ में खेती के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को ८४.५५ लाख रुपये का ऋण और ३८.४० लाख रुपये का अनुदान दिया गया था जिसका ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	विकास का मद	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता	
		ऋण	अनुदान
१	बिक्री सहित कृषि का उत्पादन		
२	छोटी सिंचाई	६८.००	२६.२९
३	जमीन का विकास		
४	पशुपालन, दुग्धशाला और मीनक्षेत्र . .	४.०५	९.०८
५	वन तथा भूमि संरक्षण . .	१२.५०	३.०३
	जोड़ . . .	८४.५५	३८.४०

उड़ीसा में फल उत्पादन का विकास

†१५१७. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ के लिए उड़ीसा सरकार ने फल उत्पादन के विकास सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जो योजनाएं चालू हैं उनके अलावा और कोई योजना उड़ीसा सरकार ने १९६३-६४ में केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारी

†१५१८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे ने १९६२-६३ में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये ;

(ख) उसी अवधि में खुरदा सड़क-प्रभाग ने चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये ; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी कितने थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में डाक सेवायें

†१५१९. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि के अन्त तक उत्तर प्रदेश के कितने गांव डाक सेवा के अन्तर्गत आ गये थे ; और

(ख) तीसरी योजना के आरम्भ से अब तक कितने गांव डाक सेवा के अन्तर्गत आ गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में उत्तर प्रदेश में केवल दो गांव ही ऐसे थे जहां डाक सेवा नहीं थी । अब इस बीच उन्हें समाप्त कर दिया गया है । तीसरी योजना की अवधि में डाक सेवा की बारंबारता में सुधार किया गया है । दैनिक सेवा के अन्तर्गत आने वाले गांवों की संख्या १ अप्रैल, १९६१ को ३५,०६७ थी जो १ मार्च, १९६३ को ४१,६१५ हो गयी है ।

२. उत्तर प्रदेश में, अधिकतर देहाती इलाकों में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २,३२७ डाकखाने और तीसरी योजना की अवधि में २८-२-६३ तक १,०१६ डाकखाने खोले गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन

†१५२०. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में तीसरी योजना की अवधि में टेलीफोन प्रणाली चालू की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : जिन शहरों में टेलीफोन सुविधाएं (टेलीफोन एक्सचेन्ज और पब्लिक कॉल आफ़िसेज़) तीसरी योजना में मन्जूर की गयी हैं या की जाने वाली हैं, उन के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१०७८/६३**] यदि ये लाभदायक मालूम हुए तो और ६० एक्सचेन्ज और ११० सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय (पब्लिक कॉल आफिसेज़) तीसरी योजना में संभवतः खोले जायेंगे ।

सिंचाई के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

†१५२१. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में 'अधिक अन्न उपजाओ'

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्दोलन के अधीन सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की नई प्रक्रिया के अनुसार जो १९५८-५९ से चालू की गई है, 'कृषि उत्पादन' शीर्षक के अधीन योजनाओं के लिए जिस में छोटी सिंचाई और भूमि विकास शामिल है, केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को इकट्ठा दी जाती है । इसलिए १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश सरकार को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता की रकम बताना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को १९६२-६३ में छोटी और भूमि विकास सहित कृषि उत्पादन योजनाओं के लिए स्वीकृत अनुदान और ऋण का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९६२–६३ . . .	१६३.४७ लाख रुपया	७५३.९६ लाख रुपया

उत्तर प्रदेश में खेती की उन्नति

†१५२२. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि के पहले दो वर्षों में खेती के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी रकम दी गई ;

(ख) क्या वह पूरी खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के लिये माल डिब्बे

†१५२३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल और धान का आयात निर्यात करने के लिए उड़ीसा सरकार को सालाना कितने माल डिब्बों की जरूरत होती है ;

(ख) क्या आवश्यक संख्या में वे सप्लाई किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) चावल और धान का आयात निर्यात करने के लिए उड़ीसा राज्य की माल डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता उस राज्य में स्टाक की आवश्यकता और उपलब्धि के अनुसार बदलती रहती है । १९६१ और १९६२ में धान और चावल के क्रमशः १९,६२९ और १५,३५९ माल डिब्बे उड़ीसा राज्य से बाहर गये और क्रमशः ६ और २७० माल डिब्बे राज्य में आये ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अरहनपुर और निहालगढ़ के बीच हाल्ट स्टेशन

१५२४. श्री रणन्जय सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर रेलवे की जौनपुर-सुल्तानपुर-लखनऊ लाइनपर अरहनपुर तथा निहालगढ़ स्टेशनों के बीच वारिसगंज में स्टेशन बनाने अथवा हाल्ट का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

मालगाड़ी की भिड़न्त

†**१५२५. श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद डिविजन के राबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के पास लेवल क्रासिंग पर १६ मार्च, १९६३ को एक ट्रैक्टर और मालगाड़ी में टक्कर हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) लगभग ६ बजे जब कि नं० ७ अप मालगाड़ी राबर्ट्सगंज और खैराही स्टेशनों के बीच लेवल क्रासिंग फाटक से गुजर रही थी तब एक ट्रैक्टर पूरब की ओर से आ कर ब्रेक के डिब्बे से टकरा गया । नतीजा यह हुआ कि ट्रैक्टर ब्रेक के डिब्बे के साथ फंस गया और लगभग ९२.५ फीट की दूरी तक घसीटा गया । ब्रेकवैन पटरी पर से नीचे उत्तर गया ।

खाद्य को डिब्बे में बन्द करने और उसे सुरक्षित रखने का केन्द्र

†**१५२६. श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य को डिब्बे में बन्द करने और उसे सुरक्षित रखने का एक सामुदायिक केन्द्र राजधानी में खोलने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य जनता के लिए इस योजना की क्या उपयोगिता है ; और

(ग) यह केन्द्र स्थापित करने में क्या लागत आयेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) २३ मार्च, १९६३ को किदवई नगर (पश्चिम) में फ्लैट संख्या १८३ (डी-२ टाइप) में एक प्रदर्शन तथा सामुदायिक परिरक्षण केन्द्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था ।

(ख) यह प्रयास घरों में खपत के लिए फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने और मूल्यवान पोषकतत्व वाली जल्द खराब होने वाली चीजों के उपयोग का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयत्न का आरम्भ है । जनता द्वारा सर्विस चार्ज दिये जाने पर और डिब्बों

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा बोतलों की कीमत चुकाये जाने पर इस केन्द्र में फलों और सब्जियों को डिब्बों में बन्द कराया जा सकता है और सुरक्षित रखवाया जा सकता है। घरों में फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने की शैलियों के संबंध में जनता को, विशेषकर गृहणियों को, शिक्षित करने के लिए निशुल्क प्रदर्शन तथा भाषण कक्षाएँ भी चलायी जायेंगी। अनुमान है कि इस केन्द्र में मुहैया की गयी सुविधाओं से जनता को मौसमी फल और सब्जियों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से संकटकाल में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए परिष्कृत खाद्य की सप्लाई में मदद मिलेगी।

(ग) अनुमान है कि साज सामान, मशीनों आदि की कुल लागत ४३,००० रुपया है और अनावर्तक व्यय लगभग ३०,००० रुपया वार्षिक होगा। इसमें डिब्बों, बोतलों, रसायनिक आदि पर लगभग १०,००० रुपये का प्रारंभिक खर्च शामिल है। इनकी लागत जनता से वसूल की जायेगी। इस प्रकार वास्तविक खर्च उस हद तक कम हो जायेगा।

केरल में टेलीफोन एक्स्चेंज और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

†१५२७. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में केरल राज्य में किन-किन जगहों पर कितने टेलीफोन एक्स्चेंज और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और एक्स्चेन्ज खोलने के लिए मंजूरी दी गयी है उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं। सामान उपलब्ध होने पर ये निर्माण कार्य पूरे कर दिये जायेंगे।

सूची

	एक्स्चेन्ज		सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय
१.	अंगमाली	१.	अंचलपेट्टी
२.	छिथिरापुरम्	२.	एडावन्ना
३.	एलाप्पल्ली	३.	कक्कोडी
४.	एलाधारा	४.	कवलम्
५.	इरूपेली	५.	कंकाचल
६.	करुमागप्पिल्ली	६.	कदम्पानाड
७.	कोडाकारा	७.	कुरुवत्ता
८.	कोल्लेन्गोडे	८.	कूडण
९.	कुथुपरम्बा	९.	कोट्टपी
१०.	मरमपल्ली	१०.	कुलीसेरी
११.	मन्नारघाट	११.	कुमाथानम्
१२.	मट्टम्	१२.	मनीड
१३.	नेम्मारा	१३.	मल्लास्सेरी

†मूल अंग्रेजी में

एक्सचेंज	सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय
१४. निलेश्वर	१४. मीनागपल्ली
१५. नाराक्कल	१५. ओलयापुरम्
१६. पारली	१६. पय्याप्पडी
१७. पाछलपलोडे	१७. पडुआपुरम
१८. पन्डलम्	१८. परडाला
१९. क्विलान्डी	१९. मीजाकू
२०. रामपुरन्	२०. वेल्लामुन्डा
२१. भिकनपुर	
२२. वडक्कनचेरी	
२३. वाकाथानम्	
२४. वेल्लूर-कोचीन	

वारंगल में पुल

†१५२८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वारंगल में ऊपरी या नीचे का पुल बनाने के संबंध में कोई कार्रवाई की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वारंगल में नीचे का पुल बनाने का खर्च उठाना मंजूर कर लिया है और उसने विस्तृत योजनाओं पर अपनी स्वीकृति सूचित कर दी है । रेलवे विभाग विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर रहा है और वह शीघ्र ही राज्य सरकार के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिये जायेंगे ।

दिल्ली दुग्ध योजना की एजेंसी

†१५२९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दूकानदारों को घी की बिक्री के लिए एजेन्सी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली दुग्ध डीपो में हर महीने घी का उत्पादन कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां । दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार किया गया घी १० दूकानों के अलावा जो योजना द्वारा ही चलाये जाते हैं, ८ एजेन्टों द्वारा बेचा जाता है ।

(ख) अधिक क्षेत्रों में बिक्री करने के लिए एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं क्योंकि योजना द्वारा चलायी गयी अधिकांश दूकानें सरकारी इमारतों में स्थित हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले वर्ष घी का माहवार उत्पादन इस प्रकार रहा :

महीना	किलोग्राम में परिमाण
अप्रैल, १९६२	१२,६३२
मई, १९६२	६२७
जून, १९६२	१५७
जुलाई, १९६२	२,५१५
अगस्त, १९६२	३,२२४
सितम्बर, १९६२	११,९३९
अक्तूबर, १९६२	१७,१३७
नवम्बर, १९६२	४२,०७२
दिसम्बर, १९६२	६३,८४९
जनवरी, १९६३	९२,९८२
फरवरी, १९६३	१०,६४०
मार्च, १९६३	९,२५०

उड़ीसा में मीनक्षेत्रों का विकास

†१५३०. **श्री उलाका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य में मीनक्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में वित्तीय सहायता 'पशुपालन, दुग्धशाला और मीनक्षेत्र' के समूह शीर्षक के लिए राज्य सरकारों के लिए मंजूर की गयी थी। इसलिए उन वर्षों में मीनक्षेत्रों के संबंध में कोई अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने १९६१–६२ में २२.७३ लाख रुपये की बजट व्यवस्था के मुकाबले २४.२४ लाख रुपये की रकम खर्च की। १९६२–६३ में ३०.२५ लाख रुपये की बजट व्यवस्था के मुकाबले ५५.४६ लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।

उड़ीसा में टेलीफोन

†१५३१. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा में सरकारी दफ्तरों और जनता ने कितने टेलीफोन लगवाये ;

(ख) १९६२–६३ में उड़ीसा की जनता से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) उसी अवधि में सरकार ने कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया और कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) १९६२–६३ में सरकार और जनता को दिये गये कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार रही :

सरकार के लिए	२४३
जनता के लिए .	४९२

(ख) १९६२–६३ में ७३५ नये आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

(ग) १९६२–६३ में सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया गया ।

सिंगरेनी कोयला खानें

†**१५३२. श्री यल्लमन्दा रेड्डी : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिंगारेनी कोयला खानों से कोयला लादने के लिए माल डिब्बों और साइडिंग की आवश्यकता का अनुमान सरकार ने लगाया है ;

(ख) यदि हां तो उस अनुमान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब संभवतः कितने माल डिब्बे दिये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सिंगारेनी कोयला खानों से परिवहन संबंधी आवश्यकता समय समय पर रेलवे तथा खान और ईंधन मंत्रालयों के बीच परस्पर परामर्श से निर्धारित की जाती है । इस समय प्रति दिन ३८० माल डिब्बों की ढुलाई का लक्ष्य है । खान और ईंधन मंत्रालय ने १ मई, १९६३ से उस लक्ष्य में २० माल डिब्बों की वृद्धि, अर्थात ४०० डिब्बे प्रति दिन, का सुझाव दिया है । रेलवे ने यह मंजूर कर लिया है ।

रायपुर–वाल्टेयर रेलवे लाइन

†**१५३३. श्री महानन्द** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में रायपुर से वाल्टेयर तक डबल रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) वाल्टेयर और रायपुर के बीच ३३० मील लम्बे सैक्शन में से, वाल्टेयर और विजयानगरम के बीच ३८ मील लाइन दोहरी की जा चुकी है । लोजीगढ़ रोड और अम्बोडाला के बीच ९ मील तथा वीसमकटक और थेरूवाली के बीच ११ मील लाइन को दोहरा करने का काम चल रहा है और उस की दिसम्बर १९६३ तक पूर्ण हो जाने की आशा है । अवशिष्ट इकहरी लाइन को दोहरी करने के काम के बारे में तब विचार किया जाएगा चालू यातायात में वृद्धि के कारण उस की आवश्यकता होगी ।

(ख) अब तक वाल्टेयर-विजयानगरम को दोहरा करने के काम पर २९३.४ लाख रुपये तथा लोजीगढ रोड और अम्बोडाला तथा वीसमकटक और थेरुवाली के बीच २० मील लाइन को दोहरा करने पर ३३.३० लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लघु सिंचाई परियोजनायें

१५३४. श्री विभूति मिश्र : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ फरवरी १९६३, तक खंड समितियों को सरकार ने छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये जितनी राशियां मंजूर की थी उन का इन पांच वर्षों की अवधि में पूरी तरह प्रयोग नहीं हो पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) व (ख). राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई

†१५३५. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर १९६२ तथा जनवरी १९६३ में प्रति दिन औसतन कितना कोयला लादा गया ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार के इस्पात संयंत्रों और कोयला ढोने के कारखानों की कुल आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो गई थी; और

(ग) असैनिक माल की ढुलाई किस हद तक बन्द रही ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :

(क)	महीना	प्रति दिन लादी गई गाड़ियों की औसत संख्या
	नवम्बर ६२	६९००
	दिसम्बर ६२	६९७५
	जनवरी ६३	६९१७

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को बीज देना

१५३६. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को १९६२-६३ और १९६३-६४ में गेहूं, चावल, पटसन और कपास के सुधरे हुए बीज उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा बनाई गयी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बीजों के मूल्य भी निर्धारित कर दिये है ; और

(ग) किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). पूछी गई जानकारी का एक विवरण नत्थी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

भाग (क)

गेहूं और चावल

सुधरी हुई किस्मों के शुद्ध बीजों के गुणन और उनके वितरण के सम्बंध में एक योजना देश में दूसरी योजना के समय से ही चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में खंड तालुक स्तर पर ३६१७ बीज गुणन फार्म स्थापित किए गए थे जिनका मुख्य उद्देश्य गेहूं चावल तथा अन्य खाद्यान्नों में सुधरी हुई किस्मों के शुद्ध बीजों के मूल स्टाक का उत्पादन करना था। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना में ४६१ फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। १९६२-६३ तक २८३ फार्म स्थापित किए जाने की सम्भावना है। आशा है कि शेष फार्म १९६३-६४ में पूरे हो जायेंगे। इन फार्मों में उत्पन्न किया हुआ मूल बीज राज्य के कृषि विभाग की देख-रेख में तथा स्थानीय पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर खंडों में बढ़ाया जायेगा। अभिप्राय यह है कि जो बीज ग्रामीण किसानों जिनको कि रजिस्टर्ड उत्पादक के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, की सहायता से जो बीज बढ़ाया जाये उसे कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित होने के बाद किसानों में वितरण किया जाये।

कपास

किसानों को सुधरी हुई किस्मों के शुद्ध बीजों की सप्लाई कपास विकास योजनाओं के द्वारा की जाती है जो विभिन्न राज्यों में चल रही हैं

जूट

जूट के बीज की सुधरी हुई किस्में जूट कृषि अनुसन्धान संस्थान, निलगंज, बैरकपुर में विकसित की जाती है। सुधरी हुई किस्मों के न्यूकलियस जूट के बीजों को सैन्ट्रल न्यूकलियस जूट सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, पो० आ० बुदबुद जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) में बढ़ाया जाता है।

ये न्युकलियस जूट के बीज जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों के कृषि विभागों को सप्लाई किये जाते हैं जो बदले में उन्हें अपने स्टेट डिपार्टमेंट सीड फार्मस और उन फार्मों पर जो एन० ई० एस० खंडों से सम्बद्ध हैं और रजिस्टर्ड बीज उत्पादकों के द्वारा बढ़ाते है। ये बीज जो राज्य बीज फार्म और एन० ई० एस० खण्डों से सम्बद्ध फार्मों पर और रजिस्टर्ड बीज उत्पादकों के द्वारा बढ़ाये जाते हैं, कृषकों को बांट दिए जाते हैं

इंडियन जूट मिल्ज़ एसोसिएशन ने भी जूट कृषकों में बांटने के लिए जूट के बीजों के गुणन के कार्यक्रम को शुरू किया है।

थोड़े से न्यूकलियस बीज कुछ ऐसे प्रसिद्ध बीज के व्यापारियों को भी सप्लाई किए गए हैं जो कृषकों में बेचने के लिए सुधरे हुए जूट के बीजों का उत्पादन करते हैं।

भाग (ख)

गेहूं, चावल और कपास

स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों के कृषि विभाग ही मूल्य निर्धारित करते हैं।

जूट

राज्य सरकारें कृषकों में बेचने के लिए सुधरे हुए जूट के बीजों का भाव निर्धारित करती हैं। ऐसा करते समय वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों का भी ध्यान रखती हैं और २० रुपये प्रति मन उस

आर्थिक सहायता के रूप में छोड़ती है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है ।

भाग (ग)

गेहूं और चावल

ठीक समय पर बीजों को वितरण करने के लिए प्रत्येक राज्य के खण्डों में बीज-भंडार स्थापित कर दिए गए हैं । जो ग्राम पंचायतों या सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को समय पर बांटने के लिए रजिस्टर्ड और प्रमाणित बीजों को जमा करते है ।

कपास

बोने के मौसम से काफी समय पहले कृषि विभाग अथवा अन्य एजेन्सियां सुधरी इई किस्मों के बीजों को उपलब्ध कर लेती हैं और उन को साफ और शुद्ध करके बोरियों में भर कर मुहर लगा दी जाती है । कृषकों में बीजों का वितरण कृषि विभाग अथवा स्वीकृत सहकारी समितियों अथवा अन्य एजैन्सियों द्वारा किया जाता है ।

जूट

राज्यों के कृषि विभाग सुधरे हुए जूट के बीजों की प्राप्ति के लिए कृषकों से एक निश्चित तारीख तक इन्डेन्ट मांग लेते हैं और राज्यों के कृषि विभाग यह सुनिश्चित कर लेते है कि जूट के सुधरे बीज किसानों को ठीक समय पर मिल सकेंगे ।

बाजार संबंधी सूचना

†१५३७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय द्वारा चलाई गई बाजार सूचना सुधार की योजना के अन्तर्गत जिन राज्य सरकारों ने आंकड़े एकत्र किये हैं उन की क्या निर्णय लिया है ;

(ख) संचालन कार्य का अवीक्षण करने के लिए स्थापित किये गये प्रादेशिक कार्यालयों के द्वारा बाजार प्रवृति का अध्ययन कहां तक बढ़ाया गया है ;

(ग) क्या बाजार के लाभों के अध्ययन कार्य को विपणन के विभिन्न स्तरों पर तथा एक विशिष्ट समय पर मूल्यों की तुलना करने का उपाय अपना कर संगठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस से उपभोक्ता रुपये में उत्पादक का भाग थोक तथा खुदरा बेचने वालों के लाभ का पता चलता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) बाजार सूचना सुधार की योजना किन्हीं ठोस निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये नहीं बनाई गई। योजना केवल बाजार सूचना सेवा में सुधार लाने तथा बाजार के आंकड़ों को एकत्र करने मे सुधार करने तथा उन को विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है ।

(ख) प्रादेशिक देशों के द्वारा लगभग १००० बाजारों के सम्बंध में बाजार प्रवृति के अध्ययन से सम्बन्धित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) जी हां, प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर ।

(घ) उपभोक्ता रुपये में उत्पादक के भाग तथा थोक एवं खुदरा व्यापारी के लाभों का अनुमानित हिसाब इन प्रयोगात्मक अध्ययनों से लगाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काजू की खेती

†१५३८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और संघ राज्य क्षेत्रों में काजू की खेती के लिये किसानों को किन किन नवीन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता तथा प्रविधिक मंत्रणा दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : **उत्तर प्रदेश** : कोई वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता नहीं दी गई क्योंकि वहां काजू खेती की कोई संभावना दिखाई नहीं देती ।

बिहार : काजू की खेती दूसरी योजना में प्रयोगात्मक आधार पर की गई थी । राज्य के पठारों में इस फसल के पैदा होने की गुंजाइश है । काजू के बीज और प्रविधिक सहायता किसानों को विस्तार कर्मचारियों के द्वारा इसकी खेती के लिये प्रोत्साहन देने के लिये दी जाती है । अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

संघ राज्य क्षेत्र : लक्कादीव, हिमाचल प्रदेश, गोआ, मनीपुर और दिल्ली में किसानों को कोई वित्तीय या प्रविधिक सहायता नहीं दी गई । अन्दमान और निकोबार द्वीपों में प्रविधिक मंत्रणा दी गई थी । तीसरी योजना में त्रिपुरा के उत्पादकों को वित्तीय तथा प्रविधिक दोनों सहायतायें दी गई हैं । पाँडीचेरी के लिये १९६३–६४ से एक योजना चालू की जाने वाली है । गोआ में काजू की खेती अच्छी तरह होती है । हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में परिस्थितियाँ इसकी खेती के अनुकूल नहीं हैं ।

कारवार में नौका निर्माण कारखाना

†१५३९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने कारवार में एक १२०० मील लम्बा घाट और एक नौका निर्माण कारखाना बनाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). दरम्याने पत्तन विकास समिति ने सिफारिश की थी कि कारवार में 'लाइटरेज व्हार्फ' (घाट) बनाने और उस के साथ साथ तथा उसके साथ मिलाने वाली नहर में ८ फुट गहराई तक मिट्टी निकालने की प्रथम अग्रता दी जानी चाहिये । यह योजना तीसरी योजना में केन्द्रीय सहायता वाली योजना के तौर पर शामिल है, इस के लिये २१.२२ लाख रुपये का नियतन है । राज्य सरकार ने १९६१–६२ में कार्य आरम्भ किया था । ३,७६,७०० रुपये तक् व्यय ३१ दिसम्बर, १९६२ तक किया गया । नौका निर्माण कारखाने की योजना का ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

फेरोक में रेलवे क्रासिंग

†१५४०. **श्री कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारम्पुरथी-फेरोक रोड के लिये फेरोक में रेलवे क्रासिंग बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को पता है कि कारावंपुरुथी से किसी पड़ौसी गाँव को मिलाने वाली सड़क नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार फेरोक में रेलवे क्रासिंग बनाने का विचार रखती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) इस स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से लेवल क्रासिंग संभव नहीं। एकमात्र उपाय यह है कि दोनों सड़कों को—कारावंपुरुथी-पालियम सड़क और मद्रास-कालीकट रोड को सड़क के ऊपरीपुल के द्वारा मिला दिया जाये, और यह योजना १९५७ से राज्य सरकार के विचाराधीन है। रेलवे कार्य आरम्भ करेगी जब राज्य सरकार द्वारा योजना अंतिम रूप से तय हो जायेगी, और उन को संगत नियमों के अधीन काम की लागत देने के लिये भी सहमत होना पड़ेगा।

वन विभाग, पोर्ट ब्लेयर

†**१५४१. श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० मई, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अफसरों और आम जनता के लिये वन विभाग, पोर्ट ब्लेयर ने दो पृथक इंडेंट रजिस्टर क्यों रखे हैं ; और

(ख) वन विभाग द्वारा गैर-सरकारी लोगों को, जलाने की लकड़ी देने के कारण क्या हैं, जबकि सरकार की अपनी जरूरतें पूरी नहीं होतीं और बिजली घर को ३० से ४० रुपये प्रति गट्ठा लकड़ी खरीदनी पड़ती है, जबकि वन विभाग का दाम ५ रुपये ५० नये पैसे प्रति गट्ठा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कारण यह है कि इससे काम चलाने में अधिक सुविधा होती है।

(ख) गैर-सरकारी लोगों को चाथम आरा मिल से थोड़ी मात्रा में लकड़ी देने की प्रथा, अतीत काल से उन द्वीपों में प्रचलित है। मूलत: उन की कठिनाई को कम करने के लिये यह प्रथा जारी की गई थी। जनता को वहाँ से लकड़ी बन्द करके भी बिजली घर की पूरी जरूरत पूरी नहीं की जा सकती। फिर भी चाथम आरा मिल से जनता को लकड़ी देने की प्रथा को जारी रखने के प्रश्न पर नये सिरे से पोर्ट ब्लेयर के वन विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

रहरा में तारघर

†**१५४२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद जिले में रहरा में कुछ समय पूर्व तारघर खोला गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह तारघर महीने में कई-कई दिनों तक लगातार खराब रहता है जिसके कारण उस क्षेत्र की जनता तारघर की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाती और न ही बाहर से भेजे गये तार वहाँ शीघ्र पहुंचते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के पास कई शिकायतें भी की गई हैं, परन्तु अभी तक उन्होंने कोई उचित निर्णय नहीं लिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो अब इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। पिछले दिनों हसनपुर-रहरा खंड में सड़क निर्माण-कार्य के कारण तार परिपथ में कुछ खराबियाँ हो गई थीं।

(ग) १८ फरवरी, १९६३ को भेजे गये एक तार की देरी की बाबत एक शिकायत की गई थी जिसकी जाँच जारी है।

(घ) लाइन को फिर से ठीक-ठाक और दुबारा बनाया जा रहा है।

राजस्थान में नलकूप लगाना

१५४३. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान में केन्द्रीय सरकार की ओर से कितने नलकूप लगाये जायेंगे और इनमें से बीकानेर डिवीजन में कितने लगेंगे ; और

(ख) बीकानेर क्षेत्र में प्रत्येक नलकूप के लिये कितनी धन राशि नियत की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार की ओर से नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है। फिर भी तीसरी योजना की शेष अवधि में ५४ विभिन्न स्थानों पर गवेषणात्मक कुएं खोदे जायेंगे और जिन से काफी पानी निकलता है उनको उत्पादन-कुओं में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर जिले में दस गवेषणात्मक कुएं खोदना भी सम्मिलित है।

(ख) बीकानेर जिले के दस स्थानों में गवेषणात्मक कुएं खोदने पर ३.५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक नलकूप पर किया गया खर्च कार्य पूरा होने के बाद ही मालूम हो सकता है।

रेल डाक सेवा कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता

†१५४४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६२ तथा उसके बाद अधिक समय तक काम करने के भत्ते का भुगतान अभी तक भी रेल डाक सेवा 'क' विभाग, अलाहाबाद के कर्मचारियों को नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं, अक्तूबर, १९६२ से फरवरी, १९६३ तक आये अधिक समय तक काम करने के भत्तों के कुल बिलों में से ७१ प्रतिशत का भुगतान हो चुका है।

(ख) उप-अभिलेख कार्यालयों से अधिक समय तक काम करने के भत्तों के बिल देर से आने के कारण कुछ विलम्ब हो गया था। तथापि इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार के सीमा जिलों में परिवहन और संचार

†**१५४५. श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सीमा जिलों में परिवहन और संचार साधनों की व्यवस्था करने के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कितना धन नियत किया है;

(ख) क्या संकट काल के कारण उक्त नियतन में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विचारित नवीन ढांचे का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). लगभग ४० लाख रुपये की लागत के काम बिहार के सीमा जिलों में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं। लगभग ४० लाख रुपये के अन्य काम भी अब इन कामों के साथ मिलाये गये हैं।

सीमा जिलों में राष्ट्रीय राजपथों से भिन्न सड़कों के नवीन काम विचाराधीन हैं और यदि आवश्यकता होगी तो नवीन ढांचे के संबंध में निर्णय साथ ही साथ कर लिया जायेगा।

आंध्र में सड़कें और पुल

†**१५४६. श्री लक्ष्मी दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सड़क विकास योजना के दूसरे प्रक्रम में हैदराबाद-नागार्जुनसागर रोड और देवरकोंडा-डिंडी परियोजना रोड पर सड़कों, पुलों और पुलियों के सुधार के लिये कोई प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ। ये राज्यों की सड़कें हैं और इनका विकास करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी के सहकारी कारखाने

१५४७. श्री कछवाय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चीनी के कितने सहकारी कारखाने कार्य कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गत दो वर्षों में उनमें चीनी का कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इस समय देश में चीनी के ४१ चालू सहकारी कारखाने हैं ।

(ख) १९६०-६१ . . . ४.५८ लाख मीट्रिक टन
१९६१-६२ . . . . ४.६६ लाख मीट्रिक टन

(ग) जी हाँ ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़कें

१५४८. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़कों के विकास व सुधार के लिये तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो क्रमशः १२·४८ करोड़ रु० तथा ०·५४ करोड़ रु० की सहायता का उपबन्ध किया गया है, उसमें से कितने धन का अब तक उपयोग किया जा चुका है ;

(ख) यह राशि किन किन नई सड़कों के निर्माण व पुरानी सड़कों के सुधार पर व्यय की गई ; और

(ग) इस सारी राशि का पूरी तरह ठीक ढंग से उपयोग हो सके, इस उद्देश्य से कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन-मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (ग). आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मंगायी गयी है और यथा संभव सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

घास व चारा गवेषणा संस्था

१५४९. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घास व चारा गवेषणा संस्था (ग्रासलैंड एंड फालिएज रिसर्च इन्स्टीट्यूट) को किस स्थान पर स्थापित करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त संस्था की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह निश्चय किया गया है कि भारतीय घास व चारा गवेषणा संस्था की स्थापना उस भूमि में की जाये जोकि झांसी जिले के भारारी स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानान्तरित की गई है।

(ख) न्यूक्लियस स्टाफ को नियुक्त किया गया है। भूमि उत्तर प्रदेश सरकार से ले ली गई है। इस संस्था को सहायता देने के संबंध में हमारी प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटन का विकास

†१५५०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के लिये नियुक्त समिति के निर्देश निबन्धन क्या हैं;

(ख) पर्यटन के विकास में कौन से कारण बाधक हैं और इन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) पर्यटन पर २० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का (१) विदेशी मुद्रा की कमाई, (२) विकास सेवा, (३) होटल स्थान, (४) अन्य अप्रत्यक्ष और अदृश्य लाभों, पर क्या असर होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) पर्यटन सम्बन्धी तदर्थ समिति के ये निर्देश निबन्धन हैं :—

(१) पर्यटन यातायात वृद्धि के दृष्टिकोण से देश में फैले हुए हालात का सामान्यतया परीक्षण करना और आगामी ३ वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम २० प्रतिशत तक और बाद में अधिक गति से बढ़ाने के लिये पर्यटन यातायात का विस्तार करने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देना ;

(२) विशेष कर :

(१) होटल आवास तथा परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यटन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और इन सुविधाओं की उन्नति शीघ्रतापूर्वक इन की व्यवस्था के लिये अपेक्षित आयों का सुझाव देना ;

(२) बीजा, सीमा शुल्क और अन्य औपचारिकताओं से सम्बन्धित वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करना, जिससे पर्यटकों को आने जाने में सुविधा हो ;

(३) यातायात के वांछित विस्तार के लिये अपेक्षित प्रचार कार्य तथा अन्य कार्रवाई के अपेक्षित पुनर्गठन की सिफारिश करना ;

(३) पर्यटन से प्राप्त तथा इसके विस्तार से होने वाली विदेशी मुद्रा को नष्ट होने से बचाने के लिये आवश्यक उपायों का सुझाव देना ।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में जो बाधक बातें दिखाई देती हैं वे ये हैं :—

(१) होटल आवास तथा परिवहन की अपर्याप्त सुविधाएं ।

(२) अन्य किस्मों की कमियां, जो यात्रा व्यापार के विविध अंगों को पर्यटकों को सर्वोत्तम सम्भव सेवा देने से रोकती हैं और पर्यटकों को देश में उनके ठहरने का आनन्द लेने से रोकती हैं ।

(३) प्रतियोगी बाजार में कुछ अन्य देश अधिक तेज गति से अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकी हैं और पर्यटन को कुछ सस्ता बनाने के लिये विशेष कदम उठाये हैं । यदि भारत सरकार के कुछ सर्वोत्तम पर्यटक का आकर्षक है, अधिकतर पर्यटक जापान, हांगकांग, न्यूज़ीलैण्ड, थाईलैण्ड, और फिलिपाइन तथा दूसरी ओर सं० अरब गणराज्य,

†मूल अंग्रेजी में

लैबनान, इजराईल, जोर्डन को जाते हैं। अतः भारत उनके अधिक पर्यटक आकर्षित नहीं कर सका, जितने कुछ अन्य पड़ौसी देश कर सके हैं।

(४) पर्यटकों से सम्बन्ध रखने वाली विविध प्रकार की औपचारिकताएं उस मात्रा तक सरल नहीं की गई हैं, जितनी अन्य देशों द्वारा कर दी गई हैं।

(५) विविध कारणों से, देश में पर्यटकों द्वारा खर्च की गई सब राशि बैंकिंग व्यवस्था में नहीं लाई जातीं। अतः विदेशी मुद्रा में पर्यटकों द्वारा खर्च और विदेशी मुद्रा की कमाई में पर्याप्त अन्तर रहता है।

कुछ निम्न महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गई हैं :

पर्यटन विभाग उपरोक्त बाधाओं में से कुछ एक को रखने का प्रयत्न कर रहा है। होटलों के निर्माण तथा विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिये, औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगमों ने अपने नियमों में इस प्रकार संशोधन किया है कि वे होटल उद्योग को ऋण दे सकें जैसे वे अब तक अन्य औद्योगिक समवायों को देते हैं। आयकर अधिनियम के संशोधन के द्वारा, नवीन औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध कर छूट का लाभ नवीन होटलों के लिये बढ़ा दिया गया है। 'पर्यटन संवर्धन' के लिये विदेशी मुद्रा नियतन से, पर्यटन विभाग, विदेशी पर्यटकों के पसन्द वाले होटलों और रैस्टोरेंटों को अत्यावश्यक उपकरण और खाद्य सामान आदि का आयात करने की अनुमति देता है।

पिछले २ वर्षों में दूरस्थ पर्यटन केन्द्रों में बहुत से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पर्यटक बंगले बनाये गये हैं। तीसरी योजना में लगभग ३० चुने हुए पर्यटन केन्द्रों में विदेशी पर्यटकों के आवास तथा सड़क परिवहन सुविधाओं को सुधारने के लिये २.९० करोड़ रुपये का नियतन किया गया है तथा उन्हीं स्थानों पर देशी या मध्यम श्रेणी के पर्यटकों की सुविधाओं के लिये २.२ करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

१९५५ से पर्यटकों के लिये बीजा और सीमा शुल्क नियमों में यथासम्भव पुनर्विचार करके ढील कर दी गई है।

(ग) (१) रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, १९६० और १९६१ के वर्षों में अनुमानित विदेशी मुद्रा कमाई क्रमशः २०.६ करोड़ रुपये और १८.५ करोड़ रुपये थी। यदि पर्यटन में २० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो गई तो उसका प्रभाव यह होगा कि अगले तीन वर्षों में अनुमानित आय इस प्रकार होने की सम्भावना होगी :

क्रमांक	वर्ष	कमाई
१.	१९६३	२३.५ करोड़ रुपये
२.	१९६४	२८.० करोड़ रुपये
३.	१९६५	३३.५ करोड़ रुपये

(२) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों में २५ से ३० प्रतिशत तक सम्भवतः विदेशी पर्यटक होते हैं और उनकी ३० प्रतिशत आय इससे होती है। प्रतिवर्ष पर्यटक यातायात में २० प्रतिशत वृद्धि से इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की यात्री बैठाने की क्षमता पर अग्रेतर भार पड़ने की सम्भावना है, विशेषकर ट्रंक मार्गों पर, जब तक कि इन मार्गों के ऊपर रखी गई क्षमता भी इस निगम के जहाजों के अतिरिक्त उतनी ही नहीं बढ़ाई जाती, आगामी दो वर्षों में कम से कम तीन जहाज जिनमें प्रत्येक में ८० लोगों की बैठने की क्षमता हो, और जो वाइकाउण्टों से बड़े हों।

(३) पाश्चात्य ढंग के होटलों की वर्तमान ठहरने की क्षमता पर्यटकों के लिये स्वीकृत, मोटे तौर पर ११५०० पलंग या ७००० कमरे हैं। १९६८ तक लगभग ५००० से ६००० अतिरिक्त कमरों या ८५०० से १०,००० पलंगों की आवश्यकता होगी।

(४) पर्यटन के अदृश्य लाभ बहुत और विविध प्रकार के हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि अविकसित देशों में पर्यटक व्यय से आर्थिक गतविधि बढ़ती है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और इसका कुछ प्रतिशत का राजस्व के तौर पर सरकारी कोष में जाता है एवं बहुत सा भाग पर्यटन व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले बहुत से लोगों को मजूरी के रूप में दिया जाता है। प्रसिद्ध विपणन अनुसन्धान समवाय द्वारा १९६० में पेश किये गये सूत्र के अनुसार, जब भारत ने पर्यटन से २०.६ करोड़ रुपये कमाये थे, ६.६ करोड़ रुपये राशि कर राजस्व के रूप में ३६ करोड़ रुपये मजूरी के तौर पर प्राप्त हुआ।

समृद्ध पर्यटन उद्योग के कारण बहुत से स्थानों की, जो अपने स्मारकों, वैज्ञानिक आकर्षणादि के लिये प्रसिद्ध हैं, बड़े पैमाने पर उन्नति होगी और देशी प्रचलित उद्योगों और लोककला का विकास होगा। पर्यटक से बड़े पैमाने पर मान्य लाभ अन्तर्राष्ट्रीय मेल मिलाप की वृद्धि होती है। सन्तुष्ट पर्यटक तो हमारे देश में अपने खर्च से आता है अपना धन खर्च करता है, वह इस देश के लिये सद्-भावना लेकर जाता है, जिसका वास्तविक मूल्य आंकना हमेशा कठिन होता है।

पौष्टिक भोजन का संभरण

†१५५१. **श्री बाल्मीकी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली में सस्ते दामों पर जनता को अच्छी किस्म के देशी गेहूँ और जावल, चीनी तथा अन्य सँरक्षणात्मक खाद्यान्नों का सँभरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या के कम आय वाले वर्गों को पौष्टिक भोजन का संभरण करने के लिये कोई प्रबन्ध किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) 'संतुलित खुराक' के व्यापक प्रचार के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) पंजाब के पास फालतू गेहूँ है और देहली की देशी गेहूँ की आवश्यकता पंजाब द्वारा पूरी की जाती है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, देहली उत्तरी चावल खँड में सम्मिलित है जिस के पास कि फालतू चावल है और पंजाब से पर्याप्त मात्रा में चावल देहली में उपलब्ध है। इसलिए देहली में देशी गेहूं या चावल के संभरण के बारे में कोई विशेष उपाय करना आवश्यक नहीं समझा गया है। कारखानों से बिक्री के लिए संगत मात्रा में चीनी छोड़ कर उस की कीमत वाजबी स्तर पर रखी जाती है तथा देहली की आवश्यकताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पड़ौसी कारखानों से प्रभावी ढंग से पूरा किया जाता है। दूध तथा अन्य डेयरी उत्पाद भी देहली दुग्ध योजना द्वारा वाजबी कीमतों पर दिये जा रहे हैं। अच्छी और चुनी हुई समुद्री मछली को वाजबी कीमतों पर बेचने के लिए गुजरात मीनक्षेत्र केन्द्रीय सहकारी संघ ने सरकार की सहायता से देहली में मछली की परचून दुकानों की एक श्रृंखला स्थापित

†मूल अँग्रेजी में

कर रखी है। फलों और सब्जियों की आवश्यकतायें सामान्य व्यापार माध्यमों द्वारा पूरी की जाती हैं। सरकार अच्छी किस्म के बीजों के वितरण करने तथा लोकप्रिय बनाने में, रसोई-उद्यानों को प्रोत्साहन देने आदि में भी सहायता कर रही है।

(ख) सरकार देहली की आटा मिलों को आयात किया हुआ गेहूँ दे रही है जोकि आटा, मैदा और सूजी जैसे गेहूँ उत्पादों संविधि द्वारा निर्धारित मूल्यों पर वितरित कर रही है। इस से लोगों के कम आय वाले वर्गों को वाजबी कीमतों पर पौष्टिक गेहूँ उत्पादों का संभरण सुनिश्चित हो जाता है। प्रोटीनयुक्त खाद्य-सामग्री भी जैसेकि बहुप्रयोजनीय भोजन तथा कम आय वाले वर्गों के लिए विशेषतः उपयुक्त 'नट्रो' बिस्कुट लाखों के लिए भोजन संघ द्वारा सरकार की वित्तीय सहायता से देहली में वितरित किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) समाचारपत्रों, पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियां, फिल्मों, वार्ताओं तथा जन संचार की अन्य प्रणालियों द्वारा प्रचार के अतिरिक्त व्यावहारिक प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों तथा प्रचार की अन्य प्रविधियों द्वारा जनता को खाद्य परिरक्षण और संतुलित खुराक का महत्व बताने के लिए एक चलते-फिरते पोषण प्रचार एकक ने हाल ही में एक व्यवस्थित आन्दोलन आरम्भ किया है। सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई भोजन प्रविधि तथा व्यावहारिक आहार पोषण संस्था, नई देहली, भी ऐसे ज्ञान का प्रसार करने का काम करती है।

मनीपुर में टेलीफोन

†१५५२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितनी मांग है ;

(ख) तीसरी योजना अवधि में मनीपुर में टेलीफोन कनेक्शन के प्रसार के लिये यदि कोई योजना हो तो वह क्या है ; और

(ग) मनीपुर में टेलीफोनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९६२ को शेष बची कुल मांग निम्नलिखित है :

(१) इम्फाल में स्थानीय टेलीफोन कनेक्शन . .	१२७
(२) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर . .	९

(ख) इम्फाल के टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता को ३०० लाइनों से ५०० लाइनों तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है। चार लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) योजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

सेहल रेलवे स्टेशन का लूटा जाना

१५५३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री २० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के निकट सेहल स्टेशन को लूटने वाले अपराधियों को दंड दिलाने और उन से रुपया बरामद करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : अब तक कुल ७ डाकू गिरफ्तार किये गये हैं। इनमें से २ का चालान किया गया है और ४ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६९ के अधीन रिहा किया गया है और अभी १ की शिनाख्त होने को बाकी है। अब तक कोई माल बरामद होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

दिल्ली दुग्ध योजना

†१५५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध याजना का अपनी इकट्ठा करने और ठंडा करने की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के प्रसार कार्यक्रम में १० अतिरिक्त दुग्ध संग्रह तथा शीतण केन्द्र सम्मिलित किये गये हैं जिन से उन की कुल संख्या ३० हो जायेगी।

दिल्ली के चिड़िया घर में पक्षियों की संख्या

†१५५५: **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गीदड़ों, नेवलों और चूहों द्वारा रात को मारे जाने वाले छापों के कारण देहली के चिड़ियाघर में पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं। इस कारण से गये प्राणों की संख्या नगण्य है। फिर भी इस क्षति को और कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) रात के चौकीदार बाड़ों के पास लगातार निगाह रखते हैं ;

(२) गीदड़ों को मारने के लिये विभागीय श्रमिकों को काम में लाया जाता है ;

(३) गीदड़ों के पेशावर शिकारियों को गीदड़ों को फंसाने और मार डालने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ;

(४) नेवलों और चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाये जाते हैं ;

(५) पक्के फर्श और मजबूत कांटेदार तारों वाले नये चिड़ियाखाने बनाये जायेंगे ; और

(६) चूहों को मारने के लिये खुले हरे मैदानों में उन के बिल पानी से भर दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्नमलाई विश्वविद्यालय में कृषि कालेज

†१५५६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ के लिए मद्रास राज्य के दक्षिण अर्काट जिले में अन्नमलाई विश्वविद्यालय में कृषि कालेज के लिये कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल राशि कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के कारण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) हां। इस कालेज के लिए १९६२–६३ के लिये १,५०,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। इस के अतिरिक्त, १९६२-६३ के दौरान अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अधीन २७,१९८.७९ लाख रुपये की पुस्तकें और उपकरण प्राप्त किये गये थे और अन्नमलाई विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान के रूप में दिये गये थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम के पोस्टमास्टर जनरल का मुख्यालय

†१५५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम खंड के पोस्टमास्टर जनरल का मुख्यालय शिलांग में स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या शुरू में मुख्यालय गौहाटी में बनाने की योजना थी ; और

(ग) यदि हां, तो मूल योजना को बदलने के कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) जैसाकि सोचा गया था पोस्टमास्टर जनरल का मुख्यालय गौहाटी में होगा परन्तु उन का मुख्य कार्यालय शिलांग में रहेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खुदागंज स्टेशन का लूटा जाना

१५५८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे मंत्री** ३१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ३ व ४ अगस्त, १९६२ की मध्य रात्रि को पूर्वोत्तर रेलवे के फतेहपुर–कानपुर सेक्शन के खुदागंज स्टेशन पर कुछ सशस्त्र डकैतों ने जो लूटमार की थी, उस की जांच पड़ताल करके उन अपराधियों को दंड दिलाने व लूटी हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अब तक कुल ५ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं। इन में से ३ का चालान किया गया है और २ को दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा १६९ के अधीन रिहा कर दिया गया है। कुछ माल भी बरामद हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेती की स्थिति का अध्ययन करने वाली समिति

१५५९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बुवाई के मौसम के पहले खेती की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन किस तरह किया जा रहा है ; और

(ग) इस की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिकानेर डिवीजन में नये रेलवे स्टेशन

१५६०. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में कितने नये स्टेशन भवन बेनाने की मांग है और अगामी वर्ष में कितने नये स्टेशन खोले जाने की संभावना है ; और

(ख) कितने वर्तमान स्टेशनों पर नये यार्ड बनाये जायेंगे, और कब तक ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) किसी स्टेशन पर नयी इमारत बनाने की मांग नहीं की गई है और १९६३–६४ में कोई नया रेलवे स्टेशन खोले जाने की संभावना नहीं है । लेकिन १९६३-६४ में कई हाल्ट स्टेशन खोलने का विचार है ।

(ख) कोई नहीं ।

टेलीफोन तथा तारघर

१५६१. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत और नेपाल के निकटवर्ती पहाड़ी क्षत्रों में टेलीफोन तथा टेलीग्राफ कार्यालय कई जगह पर खोले जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना काल में उस क्षेत्र में कितने टेलीफोन व टेलीग्राफ कार्यालय खोले जायेंगे ; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च होगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३० तारघर और २० सार्वजनिक टलीफोन घर ।

(ग) लगभग १० लाख ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में उड्डयन क्लब

†१५६२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चल रहे उड्डयन क्लबों की संख्या क्या है ;

(ख) अगले तीन वर्षों में कितने नये उड्डयन क्लब स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) राष्ट्रीय आपात स्थिति को देखते हुए राज्य के वर्तमान उड्डयन क्लबों को क्या सहायता दी जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) मध्य प्रदेश में केवल एक उड्डयन क्लब है अर्थात् मध्य प्रदेश उड्डयन क्लब लि०, इन्दौर, जिसका एक अनुधावी केन्द्र भोपाल में है ।

(ख) सरकार ने रायपुर में एक फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब की स्थापना को सिद्धान्त-रूप में मान लिया है और आशा है कि निकट भविष्य में ही क्लब उड्डयन कार्य आरम्भ कर देगा । सरकार के सामने और कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) क्लब द्वारा दिये जाने वाले उड्डयन प्रशिक्षण के घंटों की संख्या के अनुसार मध्य प्रदेश उड्डयन क्लब लि०, इन्दौर, को सामान्य वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

केरल में कृषि परिवार

†१५६३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केरल से कुछ कृषि परिवारों को केरल से मध्य प्रदेश में बसने के लिये भेजने का विचार अन्तिम रूप से रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोच कर केरल सरकार इस निर्णय पर पहुंची ; और

(ग) क्या कोई राज्य सरकारें अपने कृषि परिवार मध्य प्रदेश भेज रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) और (ख) केरल सरकार मान गई थी कि यदि बसने वालों को सिंचाई की सुविधायें, बांध के निर्माण तथा कुछ अन्य सुविधायें दी जायें तो कुछ भूमिहीन परिवारों को मध्य प्रदेश के पन्ना प्रान्त में बसाया जायेगा । क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को देना आरंभ न कर सकी, केरल सरकार ने सुझाव दिया कि सिंचाई की सुविधायें दिये जाने तक योजना को आस्थगित कर देना चाहिये क्योंकि अन्यथा केवल मात्र वर्षा द्वारा सिंचाई होने की स्थिति में केरल परिवार अपना निर्वाह करना बड़ा कठिन पायेंगे ।

(ग) नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टोंक जिल में टेलीफोन एक्सचेंज

†१५६४. **श्री केसर लाल :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला टोंक राजस्थान में कोई टेलीफोन एक्सचेंज है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या तीसरी योजना में वहां ऐसा एक्सचेंज बनाने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जिला टोंक (राजस्थान) में टोंक और नेवाई में दो एक्सचेंज हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मालपुरा तथा देवली में भी एक्सचेंजों की स्वीकृति दे दी गई है और सामान प्राप्त हो जाने पर वे खोले जायेंगे ।

सवाई माधोपुर में रेलवे पुल

†१५६५. **श्री केसर लाल :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर (राजस्थान) रेलवे स्टेशन पर कोई रेलवे पुल नहीं है ;

(ख) क्या कुछ समय पहले रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण का प्रतिवेदन क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

माननीय सदस्यों के प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि संकेत पैदल-ऊपरी पुल की ओर है अथवा सड़क-ऊपरी पुल की ओर । प्रत्येक के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

पैदल-ऊपरी पुल

अप और डाउन प्लेटफार्मों को मिलाने के लिये बड़ी लाइन को दोहरा करने के साथ-साथ एक पैदल-ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सड़क ऊपरी पुल

रेलवे उस उस स्थान पर वर्तमान समपार की जगह ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करती है जहां कि राज्य सरकारें सिफारिश करती हैं तथा तत्सम्बन्धी पूर्ववर्तिता दर्शाते हुये लागत के अपने भाग के रूप में आवश्यक धन राशि देती है। सवाई माधोपुर में एक सड़क ऊपरी-पुल की योजना को राज्य सरकार ने तीसरी योजना अवधि के दौरान ऊपरी/निचले पुलों के अपने प्रस्तावों में अस्थायी रूप में सम्मिलित किया था। ज्यों ही राज्य सरकार इस बारे में अपना अन्तिम निर्णय बतायेगी कि वह किस वर्ष काम पर आने वाली लागत का अपना भाग दे सकेगी, रेलवे द्वारा योजना की क्रियान्विति का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

मंत्रियों के टेलीफोन बिल

†१५६६. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६२ से प्रत्येक महीने में सरकार ने संघीय मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य के टलीफोन बिलों की आदायगी में कितनी राशि दी है ; और

(ख) उसमें से ट्रंक कालों पर अलग से कितना दिया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

यंत्रीकृत फार्म, जस्तर

†१५६७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जस्तर, राजस्थान, में बड़े पैमान के यंत्रीकृत फार्म की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सभी अपेक्षित मशीनरी और औजार बाहर से अथवा देश में से ही समाहृत कर लिये गये हैं ; और

(ग) क्या प्रयोग में लाई जाने वाली प्रविधियां सूरतगढ़ से भिन्न होंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) योजना का ब्योरा परीक्षाधीन है।

(ख) इस फार्म के लिए कोई मशीनरी या औजार अभी तक बाहर से अथवा स्थानीय स्रोतों से समाहृत नहीं किये गये हैं।

(ग) नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा

†१५६८. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९६२ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के फरस्वरूप भरी जाने वाली टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी प्रथम के पदों की संख्या अब बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मूलतः कितने पदों को विज्ञापित किया गया था तथा अब कितने रिक्त पदों को भरा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) ३० पदों का विज्ञापन किया गया था । भरती किये जाने वाले पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

रेलगाड़ियों की टक्कर

१५६९. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदह डिवीजन पर १५ मार्च, १९६३ की रात्रि को काकुरगाछी गुमटी के पास रेलगाड़ियों में भिड़ंत हो गई ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी जन-धन हानि हुई है ; और

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) दुर्घटना १४ मार्च, १९६३ को हुई ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) दुर्घटना कर्मचारियों की ग़लती से हुई ।

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रेलवे विस्फोट

१५७०. **श्री कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन स्टेशन पर ११ सितम्बर, १९६२ को क्लोरीन गैस के सिलेंडर के फटने से जितने व्यक्ति आहत हुए उनके माल असबाब का कितना नुकसान हुआ है ; और

(ख) उनको मुआवजा देने के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). एक बिस्तर, एक एयर बैग जिसमें श्रंगार का सामान रखा हुआ था और चमड़े का एक सूटकेश गुम हो जाने की शिकायत की गयी थी जिसके बारे में पश्चिम रेलवे जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध योजना

१५७१. श्री कछवाय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना हर साल कुल कितना दूध इकटठा करती है ;

(ख) उसमें से कितना दूध पीने के लिये बेचा जाता है ; और

(ग) यह दूध कुल कितने गांवों से आता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा १९६२ में निम्न मात्रा में दूध इकटठा किया गया :—

भैंस	गाय
१०,६८,०९५ मन	४५,७२८ मन

(ख) १९६२ में तरल खपत के लिये बेचे गये दूध की मात्रा निम्न है :—

भैंस	गाय	टोन्ड
८,६०,४८० मन	४४, ९१८ मन	२,०४,३०६ मन

(ग) यह दूध राजस्थान को छोड़कर योजना द्वारा स्थापित किये गये मिल्क क्लेक्शन तथा चिलिंग केन्द्रों तथा उनके सहायक असेम्बलिंग केन्द्रों से आता है, न कि सीधा गांवों से। अतः इस बात का पता नहीं कि दूध कितने गांवों से आता है।

सिरोज टोंक रेलवे लाइन

१५७२. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री केसर लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में चौथ के बरवाड़ा स्टेशन के पास सिरोज से टोंक तक २० मील लम्बी रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका सर्वेक्षण पहिले हो चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

हवाई अड्डों के लिये राडार

†**१५७३. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक यातायात वाले कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर कुछ विमान भरसक राडार उपकरण (प्रिसीजन अप्रोच राडार) लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन हवाई अड्डों पर ;

(ग) अपेक्षित उपकरण कहां से मंगाने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) योजना की कियान्विति के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये है ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी हां। बम्बई (सांताक्रुज) तथा कलकत्ता (डमडम) हवाई अड्डों पर।

(ग) उपकरण भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग योजना के अधीन पश्चिम जर्मन संस्था से मंगाया गया है।

(घ) राडार लगाने के लिए स्थानों का चुनाव कर लिया गया है। इसके लिए भवन निर्माण के लिए कार्यवाही की जा रही है। भवन बन जाने पर उपकरण स्थापित कर दिया जायेगा।

चलता-फिरता वेल्डिंग संयंत्र

†**१५७४. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने इस बीच तीन चलते फिरते वेल्डिंग संयंत्र खरीद लिए है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवर्ष १००० किलोमीटर रेलवे के जोड़ों का वेल्डिंग करने का काम बढ़ा कर १९०० हो गया है ; और

(ग) बल्हारशाह तथा विजयवाड़ा के बीच रेल की पटरी को वेल्ड करने का काम कब किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तीन चलते फिरते फ्लैशवर वेल्डिंग संयंत्र के क्रयादेश दे दिए गए हैं तथा उनके शीघ्र मिल जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बल्हारशाह-विजयवाड़ा सैक्शन का लगभग ४४ मील रेल की पटरी को वेल्ड कर दिया गया है तथा अन्य ७४ मील के लिए कार्यक्रम बना लिया गया है और १९६३–६४ में काम शुरू कर दिया जायेगा।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी

†**१५७५. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटीग्रल कोच फैक्टरी में १ अप्रैल, १९६३ से मीटरगाज के माल तथा यात्री डिब्बे बनने लगेंगे ;

(क) यदि हां, तो वर्ष में कितने डिब्बे तैयार होने लगेंगे ; और

(ग) ब्राडाज के माल तथा यात्री डिब्बों की मांग किस प्रकार पूरी होगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अगस्त, १९६३ से इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में मीटरगाज के माल तथा यात्री डिब्बों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) १९६३–६४ में १५० मीटरगाज के डिब्बे।

(ग) इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर तथा रेलवे वर्कशापों में ब्राडगाज के डिब्बे भी बनते रहेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

लालगुडा में बाक्स टाइप के वैगनों का निर्माण

†१५७६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लालगुडा वर्कशाप में अब तक बाक्स टाइप के कितने वैगनों का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या इनको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में इस्पात की प्लेटों का संभरण कर दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४१ बाक्स वैगन लालगुडा वर्कशाप में फरवरी १९६३ के अन्त तक बन चुके हैं ।

(ख) जी हां । काम के प्रतिदिन २ वैगनों के लिये निर्माण की क्षमता बनाने का विचार है ।

(ग) जी हां ।

दक्षिण रेलवे के लिये 'फिश प्लेट' तथा 'टाई बार'

†१५७७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल को पटरी को बदलने के लिए दक्षिण रेलवे को कितनी फिश प्लेटों तथा टाई बारों की जरूरत रहती है ;

(ख) १९६३-६४ में कितनी संभरण होने की संभावना है ; और

(ग) इसमें से कितनों का आयात किया गया था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : (क) प्रत्येक वर्ष के रेलकी पटरी बदलने के कार्यक्रम के आधार पर प्रत्येक वर्ष फिशप्लेट तथा टाई बार की आवश्यकता बदलती रहती है । १९६३-६४ की आवश्यकता नीचे दी जाती है :-

फिशप्लेट	१,१०० मीट्रिक टन
टाई बार	९.०० लाख

(ख) उपरोक्त (क) में दिखाई गई पूरी आवश्यक गयें

(ग) ९०० मीट्रिक टनों की फिशप्लेटों का अयात होगा । टाईबार का आयात नहीं होगा ।

इस्पात नगरों के लिये विमान सेवायें

१५७८. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गोकर्ण प्रसाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक लाख से अधिक आबादी वाले इस्पात नगरों तक इंडियन एयरलाइन्स को विमान सेवायें चलाने का विचार किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी म

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें किन-किन नगरों के लिये चलाई जायेंगी ; और

(ग) उपरोक्त सेवाओं पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कितना मासिक व्यय होगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी नहीं। लेकिन कलकत्ता जमशेदपुर विमान सेवा हफ्ते में तीन बार रूरकेला तक चलायी जाने लगी है।

(ख) और (ग) : सवाल ही नहीं उठता ।

दिल्ली के गांवों में टेलीफोन

१५७९. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गोगर्ण प्रसाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के पास वाले कुछ गांवों में टेलीथोन लगाने की व्यवस्था कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन गांवों में और कितने क्षेत्र में ; और

(ग) वर्त्तमान योजना काल में इन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) गांवों के आधार पर टेलीफोन नही लगाए जाते । दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की कुछ योजनाएं हैं ।

(ख) (१) नजफगढ़
(२) नांगलोई

इसके अलावा कुछ मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का आवश्यकतानुसार विस्तार करना है ।

सामान्य रूप से एक एक्सचेंज के अंतर्गत उसके चारों ओर का लगभग ६ कि० मी० का क्षेत्र आता है ।

(ग) (१) ६४००० रु० ।
(२) १५००० रु० ।

यात्रा अभिकरण

†१५८०. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तथा विदेशी, अलग अलग पंजीबद्ध कितने यात्रा अभिकरण हैं ; और

(ख) क्या भारतीय अभिकरण विश्व के अन्य भागों में बिना प्रतिबन्ध के काम कर सकती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) पर्यटन विभाग भी स्वीकृत सूची में ३१ भाग अभिकरण हैं जिनकी ३५ शाखायें हैं। इसमें से ४ यात्रा अभिकरण अर्थात्

†मूल अंग्रेजी में

मैसर्स अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी, बम्बई, मैसर्स काक्स एण्ड किंग्स, बम्बई, मैसर्स थामंस कुक एण्ड सन (कान्टीनैन्टल ओवरसीज) लिमिटेड, बम्बई तथा मैसर्स एवरैटैट ट्रैवल सर्विस, कलकत्ता, विदेशी हैं तथा शेष भारतीय हैं।

(ख) भारतीय अभिकरण तब तक विश्व के अन्य भागों में काम नहीं कर सकते हैं जब तक उनको अपने कार्यालयों के प्रबन्ध के लिए व्यय करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग से स्वीकृति न मिल जाये।

अन्य देशों द्वारा प्रतिबन्धों के मामले में ऐसा है कि जिन देशों में भारतीय यात्रा अभिकरण काम करना चाहते हैं उन देशों की अपनी नीति पर ऐसा करना आधारित होता है और यह प्रक्रिया अन्य देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की है।

लखनऊ—बाराबंकी रेलवे लाइन

†१५८१. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ तथा बाराबंकी के बीच रेलवे लाइन बाढ़ से टूट गई थी ;

(ख) क्या रेलवे लाइन का स्तर ऊंचा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यय क्या होगा तथा परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) आशा है कि काम १० लाख रुपये की लागत स जून १९६३ के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

कलकत्ता में पत्तन शुल्क

†१५८२. **श्री महेश्वर नायक** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती बसन्त कुमारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के सुझाव के अनुसार पत्तन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) किन कारणों से इनको बढ़ाने की आवश्यकता हुई ; और

(ग) इन प्रस्तावों के कारण राजस्व में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां। कलकत्ता पत्तन पर खाद्यान्नों तथा कोयला, रेलवे भार शुल्क, बर्थ किराये पर लेना, तथापि टाल तथा पायलेट्ज फीस बढ़ाने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को मिले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऋण पर सूद का भुगतान, मूलधन का भुगतान, कार्यालय व्यय में वृद्धि तथा मूल्य तथा लागत बढ़ जाने के कारण शुल्क बढ़ाना आवश्यक समझा गया ।

(ग) वार्षिक लगभग ९२.६ लाख रुपये ।

रेलवे सैलून

†१५८३. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वातानुकूलित रेलवे सैलून रेलवे अधिकारियों के प्रयोगार्थ बनाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये कितने बनाये जायेंगे तथा उनकी कुल लागत क्या होगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई वातानुकूलित निरीक्षण डिब्बे बनाये गये हैं ।

मार्ग में खोई गई वस्तुयें

†१५८४. { **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ नवम्बर, १९६२ को मनिहारी घाट रेलवे स्टेशन से इच्छापुर के लिए हथियारों से भरे २३ बक्से बुक किए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त २३ बक्सों में से वहां पर २२ बक्से पहुंचे तथा एक खोया गया जो अब तक नहीं मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). १५-११-१९६२ को रंगापाड़ा नार्थ से इच्छापुर को हथियारों से भरे हुए २३ बक्से भेजे गये थे, मनिहारी घाट से नहीं । २२ बक्से २१-११-६२ को तथा शेष एक ११-१-६३ को इच्छापुर पहुंच गया था और क्रमशः २१-११-६२ तथा १२-१-६३ को कमांडिंग आफिसर राइफल फैक्टरी को उनको दे दिया गया था ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य के बारे में वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१०८०/६३]

---

†मूल अंगजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २२ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१२ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) दूसरा मूल्य नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(२) दिनांक २९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७१ में प्रकाशित दिल्ली रोलर आटा मिलें गेहूं की चीजें (मूल्य नियन्त्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(३) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७६ में प्रकाशित भारतीय मक्का (माण्ड उत्पादन में अस्थायी रूप से प्रयोग) संशोधन, आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–१०८१/६३]

प्राक्कलन समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** : मैं खान और ईंधन मन्त्रालय—इण्डियन रिफाइनरीज लि०, नई दिल्ली के बारे में प्राक्कलन समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विधेयक पर राय

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६२ के बारे में, जिसे २२ जून, १९६२ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया गया था, पत्र संख्या २ सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करता हूं कि ८ अप्रैल, १९६३ को शुरू होने वाले सप्ताह में सदन में सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(१) आज की कार्यसूची से बने हुए कार्य पर विचार ।

(२) निम्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :

वाणिज्य तथा उद्योग

परिवहन तथा संचार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

खान और ईंधन

इस्पात और भारी उद्योग ; और

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय ।

सरकारी उपक्रमों के लिये स्थायी समिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : इस से पहले कि आप अगला कार्य आरम्भ करें मैं आप का ध्यान सरकारी उपक्रमों के लिए स्थायी समिति सम्बंधी प्रस्ताव के बारे में उठाये गये प्रश्न की ओर दिलाता हूं । मैंने इस के बारे में आप को लिखा था किन्तु अभी तक मालूम नहीं हो सका कि इस सम्बंध में क्या प्रगति की गई है ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : उस दिन मैंने सम्बन्धित मंत्रालय को बता दिया था और मेरे विचार में उसने अभी तक निश्चय नहीं किया । जब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हो, तो माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं और उन्हें उत्तर मिल जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात और है । यह बताया जाना चाहिये कि सरकार इस पर विचार कर रही है या वह कुछ समय और लेगी । सरकार को निश्चित रूप में बताना चाहिये कि वादविवाद के उत्तर के समय माननीय मंत्री इस के बारे में वक्तव्य देंगे या एक अलग वक्तव्य दिया जायेगा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह**: जी हां, इस सम्बंध में बताया जायेगा कि क्या सरकार इस को हाथ में लेगी या नहीं ।

श्री यशपाल सिंह (कराना): अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं एक सैकेन्ड में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक़ डिगनेटरीज़ की औनर को मेंटेन करना सरकार का काम है । मैंने आज भी लिख कर दिया और पहले भी एक कौलिंग अटैंशन दिया था कि हिन्दुस्तान के एक्स गवर्नर जनरल की शान के खिलाफ श्री वी० पटनायक ने एक बयान दिया है, और . . .

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए माननीय सदस्य उनसे क्या पूछते हैं ? यह तो मुझ से उन्हें पूछना चाहिए ।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय ही फिर बतला दें कि उस मामले को उठाने का हमें कब मौक़ा मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझ से पूछने का तरीका और है और वे उसे इस्तेमाल करें।

अनुदानों की माँगें—जारी

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रतर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगा ।

†**श्री फ्रैंक ऐंथनी** (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : सदन में और देश में सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने की बहुत आवश्यकता है । इसी कारण हम इतना भारी खर्च उठा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री चह्वाण इस सदन में नये हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैं, सदन का एक पुराना सदस्य होते हुए हमेशा इस बात की आलोचना करता आया हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की यह एक परम्परा बन गई है कि वह जानबूझ कर सदन को प्रतिरक्षा की तैयारियों के बारे में अन्धकार में रखता है, और प्रतिरक्षा मंत्री ने इस परम्परा को कायम रखा है। यह अधिक ईमानदारी की बात होती, यदि प्रतिरक्षा सम्बंधी लेखे राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किये जाते और देश को यह बताया जाता कि विधायकों पर प्रतिरक्षा सम्बंधी तैयारी की मामूली बातों के बारे में भी विश्वास नही किया जा सकता। प्रतिरक्षा मंत्री ने जितने भी आश्वासन दिये हैं, वे सब गलत और झूठे सिद्ध हुए हैं। तथ्य यह है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे और हमने अपने सैनिकों को बिना सामान और कपड़ के और बिना तैयारी के ऊंचाई पर लड़ने के लिए भज दिया था। मैं यह भी कहूंगा कि हम अपने सैनिक गुप्तचर विभाग को विकसित करने में बिल्कुल असफल रहे हैं, जिसके कारण हमने चीनियों की शक्ति का बहुत कम अनुमान लगाया। प्रधान मंत्री ने सैनिक गुप्तचर विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर कि नेफा क्षेत्र में थोड़ें से चीनी हैं, इन को निकालने का आदेश दे दिया था जिस के फलस्वरूप हमने बिना तैयारी के और सामान के अपने कुछ सैनिक वहां भेज दिये थे। थागला क्षेत्र में वे घिर गये थे और उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिला।

मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय सुरक्षा के बारे में न केवल आत्म-संतुष्ट है, बल्कि सदन को कोई भी जानकारी नहीं देना चाहता। कांग्रस विधायक दल के स्थान पर यह हमें क्यों नहीं बताया जाता कि हम सेना की संख्या दुगनी कर रहे हैं और अब और आयुध कारखाने लगा रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने जांच समिति के बारे में कहा है। मैं इस का स्वागत करता हूं। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इतनी विलम्बकारी जांच पर कुछ लोगों को शक है। पहले कहा गया था कि इस में ४ महीने लगेंगे। अब बताया गया है कि आठ सप्ताह और लगेंगे। तब तक संसद का सत्र समाप्त हो चुका होगा और लोग यह भूल जायेंगे कि नेफा की हार के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं मंत्री महोदय से पूछंगा कि हमारी जो हार हुई है, क्या उनके आधारभूत कारण हमें बताये जायेंगें मैं समझता हूं कि ये कारण राजनीतिक हैं और इनके लिए प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। पहली बात यह है कि राजनीतिज्ञों को हमारी सैनिक आवश्यकताओं का बिल्कुल अन्दाज़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें अहिंसा के वातावरण में पाला गया है। राजनीतिज्ञ सेना को एक अनिवार्य बुराई समझते हैं और चाहते हैं कि जहां तक हो सके, इसे घटाया जाये। राजनीति ने हमारी सैनिक तैयारी को खराब कर रखा है। हमारी सेना के पास सामान बहुत अपर्याप्त था और जो भी था वह बिल्कुल पुराना था। तो क्या यह राजनीतिक गलती नहीं थी ? क्या हिन्दी चीनी भाई भाई का नारा राजनीतिक नहीं था। प्रतिरक्षा मंत्री से ले कर नीचे तक पाकिस्तान को मुख्य दुश्मन समझ जाता था, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान आक्रमण कर सकता है किन्तु चीनी साम्यबाद के खतरे को कम समझ गया और इस की गम्भीरता को नहीं समझा गया।

हमारी सेनाओं के पास पहाड़ी तोपें नहीं थी और न ही उनके पास हल्के टैंक थे। चीनियों के पास ये दोनों थे, जो कि उन्हें रूस ने दे रखे थे और इन के सामने हम बिल्कुल बेबस थे। आयुध कारखाने में सैनिक सामान तैयार करने की बजाय शहरी सामान तैयार किया जा रहा है और उनके काम में कोई उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि नेफा में जो निर्णय किये गये थे, क्या वे राजनीतिक निर्णय नहीं थे। क्या यह प्रतिरक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री का निर्णय नहीं था कि हमारी स्थल सेना को वायु सेना द्वारा सहायता न दी जाये और वायुसेना से कोई काम न लिया जाये ? यदि वायु सेना को सहायता दी जाती तो चीनियों को बड़ी भारी हार दी जा सकती थी।

[श्री फ्रैंक ऐंथनी]

जब श्री एवरिन हैरिमन यहां आये थे, उन्होंने भी इस बात को माना था कि हमारे जवान बहुत बहादुरी से लड़े हैं किन्तु हमारी जितनी भी गलतियां थी, वे युद्ध नीति सम्बंधी गलतियां थी। यह मानना बहुत कठिन है कि हमारी सेना और वायु सेना के नेता भयभीत हुए हुए थे। भय तो राजनीतिज्ञों में था और इसी कारण उन्होंने यह निर्णय किया था कि वायु सेना का प्रयोग न किया जाये। सच तो यह है कि हम पूरा युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं थे और हमने अपनी स्थल सेना को नष्ट होने दिया।

प्रतिरक्षा के मामले में आत्म-निर्भरता की बात करना बहुत ही खतरनाक है क्या ब्रिटेन और जर्मनी जैसे शक्ति शाली देश आत्म-निर्भर हैं, क्या वे अपने लिए प्रबंध नहीं करते ? हम जानते हैं कि ५ नहीं १५ वर्षों में भी हम वायुसेना के मामले में चीनियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यदि चीनियों ने पुनः हमला किया, तो क्या हम अपनी वायु सेना को जमीन पर रखेंगे या अन्य शक्तियों के साथ कोई साझौता करेंगें ? कांग्रस वालों को मालूम है कि एसी हालत में हमारी वायु सेना बिल्कुल बेकार होगी। साम्यवादी इस बात की भीआलोचना कर रहे हैं कि ३०० अमरीकी जो हमारे सैनिक और सामान ले जा रहे हैं एक विदेशी दस्ता है, जिन्हें यहां नहीं आना चाहिये था। हमें इस बात का प्रबंध करना चाहिये कि यदि चीनियों ने पुनः हमारे ऊपर हमला किया तो हम सामरिक दृष्टि से अपनी वायु सेना का प्रयोग करने योग्य होंग विदेशों से आने वाली सहायता के बारे में सत्तारूढ़ लोगों के दृष्टिकोण का यह परिणाम हुआ है कि सहायता अचानक कम होने लगी है। हम अमेरिका और राष्ट्र-मंडलीय देशों से केवल तीस तीस करोड़ की सहायता मिली है। यह साम्यवादियों और उन के साथियों के दबाव का परिणाम है कि अमेरिका और ब्रिटन दोनों समझते हैं कि हमें सहायता देने का कोई लाभ नहीं है। या वे हमारी आयोजनाओं की पसन्द नहीं करते।

मैं इस का उत्तर चाहता हूं कि प्रतिरक्षा उत्पादन और संभरण का पुनर्गठन कैसे किया जायेगा। मैंने श्री कृष्णमाचारी से पूछा था, किन्तु उन से कुछ मालूम नहीं हो सका। मुझे डर है कि हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन में सुधार होने की बजाये और भी गड़बड़ पैदा होगी। इस समय भी इस काम में बहुत अव्यवस्था है और इस में कोई आयोजना नहीं है, यद्यपि धन इतना अधिक खर्च हो रहा है। क्या माननीय मंत्री बता सकेंग कि टैंकों के उत्पादन में प्राथमिकताए क्या होंगी और मिग २१ के उत्पादन के बारे में हमारी नीति क्या होगी।

अन्त मैं, में वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री से कहूंगा कि वे दृढ़ता से समस्याओं का सामना करें और वे सदन पर अधिक विश्वास करें।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं नये प्रतिरक्षा मंत्री का हार्दिक स्वागत करता हूं। विरोधी पक्ष की इच्छाओं के अनुसार उन्होंने बहुत शीघ्रता से नेफा के पराजय के बारे में हमारी सेनाओं के कार्य की जांच के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है।

पर उन के एकाग्रचित्त का प्रतीक है कि वे साढ़े चार घंटे तक लगातार वाद विवाद को सुनते रहे हैं।

श्री चौह्वाण के नेतृत्व में केवल महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की सूची ही ऐसी तैयार की गई थी जिस में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्होंने नेफा की हार के सम्बंध में जांच के लिए समिति बना दी है। किन्तु हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें जिस से सेना में आत्मविश्वास कम होता हो।

श्री एन्थनी ने विपत्ति की बात कही किन्तु ऐसी विपत्ति तो द्वितीय युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस में भी आई थी और उन्हें पुनः खड़े होने में कुछ समय लगा था।

हम सेना के जवानों और अधिकारियों की अभ्यर्थना करते हैं जिन्होंने देश के हित जानें दी हैं और जो देश की रक्षा करते हुए अपंग हो गये हैं।

मैं सदा इस बात पर बल देता रहा हूं कि जब तक हम अपना वायु बल अपने सातों पड़ौसी देशों से अधिक नहीं बनाते हम सुरक्षित नहीं रह सकते। वायु बल के अत्यधिक महत्व को श्री चर्चिल और फील्ड मार्शल मिंटगुमरी ने भी स्वीकार किया था। हमारे लड़ाकू विमानों का उत्पादन तेज करना चाहिये, फालेंड ग्नार की त्रुटियां दूर करनी चाहियें। एवरो ७४८ के उत्पादन से लोगों को निराशा हुई है। हमारे लिए अति स्वन विमानों की आवश्यकता है उस के बिना हम चीनियों का मुकाबला नहीं कर सकते।

मैं श्रीमती शारदा मुकर्जी की इस बात का विरोध करता हूं कि भूटान, सिक्किम, नेफा का हमारे ऊपर दायित्व है। मैं तो उन्हें देश की सम्पत्ति मानता हूं।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि): माननीय सदस्य ने गलत समझा है। मैंने तो कहा था कि प्रतिरक्षा के दायित्व अन्य दायित्वों से भिन्न हैं।

महिला सदस्या ने दूसरी बात यह कही कि हो सकता है कि कोई सैनिक अधिकारी शक्ति को अपने हाथ में ले ले और हम सब को जेल में पटक दे। हमें इस प्रकार के विचारों को प्रचार नहीं देना चाहिये। यह अत्यंत आपत्तिजनक है।

प्रतिरक्षा वैज्ञानिक संगठनों के अणु शक्ति आयोग के सहयोग से काम करना चाहिये और उन विमान का उत्पादन करना चाहिये ताकि जब चाहें अणु अस्त्र तैयार कर सकें।

कुछ लोग सेनाओं में आत्मविश्वास और साहस के अभाव की बात करते हैं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): किसी ने भी सेना के साहस पर संदेह नहीं किया।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य के कथन का विरोध किया गया यदि पहले किसी सदस्य ने ऐसी बात नहीं कही तो उन्होंने इस का निर्देश क्यों किया?

†**श्री जोकीम आल्वा**: मैं अपराध स्वीकार करता हूं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जो विलम्ब और हानियों का उल्लेख है उनके सम्बंध में प्रतिरक्षा मंत्री को सख्त होना चाहिये।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी**: श्री आल्वा को चाहिये था कि मेरा विरोध करते मेरे भाषण का उद्धरण देते। उन्होंने जो कुछ कहा है गलत समझने के कारण कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय**: यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उन्हें अपने आप और श्री आल्वा के कथन की तुलना प्रस्तुत करनी चाहिये थी।

†**श्री बृजराज सिंह** (मालावाड): मैं विनीत भाव से वायु सेना के महत्व का उल्लेख करते हुए पहले इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आज सेना पैदल चल कर नहीं लड़ती बल्कि विमानों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बृजराज सिंह]

द्वारा उनका यातायात और आवश्यक सामान का परिवहन आवश्यक है। इस काम के लिए उपयोगी विमानों का उपयोग करना चाहिये ।

विमान द्वारा वस्तुओं और सामान को ले जाने और युद्ध क्षेत्र में ले जा कर सामान गिराने के दो भिन्न काम हैं। पहले काम के लिए ५०,००० से १००,००० पाउंड तक सामान ले जाने वाले और दूसरे काम के लिए हलके तेज रफ्तार विमान चाहियें। इसके लिए केरीबू विमान बहुत उपयोगी हैं और वह अधिक संख्या में खरीदना चाहियें ।

परिवहन के विमानों पर अत्यधिक व्यय होता है। अतः हमें केवल अच्छे प्रमाणित हुए विमान ही लेने चाहियें और कम से कम मूल्य पर उन का निर्माण होना चाहिये।

आज का युद्ध बहुत तेज रफ्तार है क्योंकि जेट विमानों को विमान नाशक तोपों से नहीं गिराया जा सकता। अतः आधुनिक क्षेप्यास्त्रों की अत्यधिक आवश्यकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने मिग २१ का निर्माण करने का विचार किया है। क्योंकि यह बहुत बढ़िया लड़ाका विमान है, एच० एम० २४ और मार्क II के निर्माण के बारे में भी मुझे प्रसन्नता है। आक्रांताओं के प्रवेश के बारे में जानने के लिए राडर की चेतावनी प्रणाली २८ घंटे के लिए चालू रहनी चाहिये।

पहाड़ी प्रदेश में लड़ाई का प्रशिक्षण देना चाहिये और वहां धीमे विमानों की आवश्यकता है और विमानों को भी पहाड़ों में काम करने का प्रशिक्षण देना चाहिये।

एच० ए० एल० के कारखाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं कि यहां दक्षिण का सर्वोत्तम प्रकार का कारखाना स्थापित किया गया है। विलिंगटन के कथन के अनुसार हमें सदा यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि पहाड़ी के उस पार क्या हो रहा है। आशा है हम इस सम्बंध में प्रयत्नशील होंगे ।

†श्री कृ० च० पन्त (नैनीताल) : वित्त मंत्री के अनुसार १९६३-६४ के आयव्ययक में प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों को सब से अधिक महत्व दिया है। इस का बजट ८६७ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पूर्व वर्ष की तुलना अधिकांश बजट वृद्धि प्रतिरक्षा के कारण है अर्थात अब यह कुल का ४० प्रतिशत है। अमरीका जैसा देश तो कुल का ६० प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय कर सकता है किन्तु हमारे लिए तो अपने आर्थिक कामों में बाधा न पहुंचाते हुए इतना सब करना बहुत है। इस का अभिप्राय है कि भारत स्वतंत्रता के उपस्थित खतरे के लिए तैयार है।

मैं श्री इंद्रजीत गुप्त की इस बात से तो सहमत हूं कि हमें सम्मान की खातिर विदेशों पर प्रतिरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिये किन्तु आज की प्रौद्योगिक प्रगति के युग में दूसरों पर निर्भर होना भी स्वाभाविक है। हमें उत्पादन कार्य को अधिकाधिक तेज करना चाहिये।

सीमांत पहाड़ी देशों के लोगों में इस बारे में आतंक फैला हुआ है कि चीन की सेनाएं तकलाकोट में एकत्र हो रही हैं। प्रतिरक्षा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ियों में अधिक सफलता से की जा सकती है।

हाउस आफ कामन्स के प्रतिवेदन के अनुसार अगले तीन वर्षों में ४,६०० गुरखों को छंटनी किया जा रहा है। भारत को उन्हें अपनी सेना में ले लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा की प्रतिरक्षा का संगठन करने के लिए एक तो यह आवश्यक है कि वहां मिलीशिया का संगठन किया जाये और इस में भर्ती होने के लिए अधिकाधिक लोगों से कहा जाए। इन प्रदेशों में भूतपूर्व सैनिक बहुत हैं वे मिलीशिया को दृढ़ बनाने में सहायक हो सकते हैं।

पहाड़ी प्रदेशों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सेना होनी चाहिये। अन्त में हम सब मंत्री महोदय से साहसपूर्ण नेतृत्व की आशा करते हैं।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय हम इन प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर ऐसे समय पर विचार कर रहे हैं जब कि हमारी भूलों के परिणामस्वरूप हमारे हजारों जवानों का बलिदान हो चुका है। उन लोगों को केवल मौखिक श्रद्धांजलि अर्पित करने से काम नहीं चल सकता है। सही श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जब हम सोचें कि कम से कम भविष्य में हम भूलें नहीं करेंगे और हम जवानों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सोच विचार करके काम करेंगे।

आज यह मंत्रालय इस स्थिति में है। मुझ से पहले इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात की चर्चा की है कि इस मंत्रालय को इस सदन में विश्वास नहीं है और इसीलिये यह सदन बहुत सी बातों से, जो कि इस सदन के सामने आनी चाहियें जिस में कि सदन के सदस्य अपने सुझाव दे सकें, वंचित रखा जाता है। अंग्रेजी के जमाने में तो यह बात सही हो सकती थी किन्तु आज ऐसी बात करना हमारे देश के हितों के विरुद्ध है और इस सदन के मान व प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। हम यह देखते हैं कि अनेक मंत्रालय अपने अपने तरीकों से सदस्यों को अपनी तरफ खींचते हैं, कोई फिल्म डिविजन की तरफ ले जाता है कोई जनरल भोंसले की नैशनल डिसिप्लिन स्कीम दिखाने के लिए हम को ले जाता है, कोई कामर्स एंड इंडस्ट्री के कारखाने दिखाने के लिये हम को ले जाता है, किन्तु हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय इतनी भी परवाह नहीं करता कि जो उस के सैनिक अभ्यास हमारी सेना में होते हैं जिस में इन्फैन्टरी या दूसरे लोग शामिल होते हैं, आर्टिलरी होती है टैंक होते हैं, उन को दिखाने की कोई योजना बनायें, ताकि हम समय पर जा कर अभ्यास देख सकें। आज हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि हमारे प्रतिरक्षा के जो काम हो रहे हैं उन के अभ्यास मैदानों में किस प्रकार से होते हैं, पर्वतों में किस प्रकार से होते हैं, इन सब अभ्यासों की जानकारी सदन के सदस्यों को कराई जाय। यह जानकारी तभी कराई जा सकती है जब माननीय सदस्य वहां पहुंचें और उन सब कामों को देखें ताकि उन्हें उन कठोरताओं का भी अनुभव हो जिन के बीच में रह कर हमारे जवानों को गुजरना पड़ता है।

इससे पहले कि मैं मूल बातों की तरफ जाऊं और बतलाऊं की हमारी सैनिक तैयारियां भारतवर्ष में क्या क्या हैं, उस पहलू की तरफ जाना चाहता हूं जिस की बार बार इस सदन में चर्चा होती है। आज एक रिवाज सा बन गया है कि जब कोई सदस्य बोलता है तब वह अलाइनमेंट और नानअलाइनमेंट की बात करता है, वह तटस्थता या किसी संस्था या गुट में मिलने की बात करता है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वह बात अब पुरानी और निरर्थक सी हो गई है। इस में कोई व्यावहारिक बात नहीं रह गई है। यह तो वैसी ही स्थिति बन गई है कि जैसे किसी ने जवानी में तो अपना विवाह करवाया नहीं और बुढ़ापे में कोई उसका विवाह करता नहीं। पहले अमरीका बार बार प्रयत्न कर रहा था कि किसी प्रकार से भारत उन के असर में आ जाये, उस समय हम ने अपना हित सोच कर उसका साथ नहीं किया। उस के बाद उस ने अपना हाथ पाकिस्तान पर रक्खा। जो दलील हम देते हैं कि अगर हम किसी गुट में जायेंगे तो यह शीत युद्ध हमारे सिर पर आ जायेगा, उस दलील की पाकिस्तान ने परवाह नहीं की। उस में रहस्य था। पाकिस्पान बना ही हिन्दुस्तान से नफरत करने के आधार पर है, और हम बार बार यह बात भूल जाते हैं, इसलिए उसका एक ही काम रहा है कि भारत उन से मजबूत न बने, वह कमजोर रहे और सारे काम पाकिस्तान इसी तरह से करता रहा। अमरीका बावजूद हमारे विरोध के उस की मदद करता रहा।

[श्री काशी राम गुप्त]

कुछ लोग कहते हैं कि हम रूसी गुट में चले जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूसी गुट में जाने का प्रश्न पैदा हो ही नहीं सकता क्योंकि रूस का गुट कम्यूनिस्ट कंट्रीज का गुट है। आज जो कम्यूनिस्ट देश हैं उन का एक तरीका हो गया है कि उन की एक बिरादरी है, उनके कुछ काम हैं। जब तक हम उन को पूरा न करें, इंडिविजुअल प्रापर्टी (व्यक्तिगत संपत्ति) का सफाया न करें, इस प्रजातन्त्र को ताक में उठा कर न रखें, तब तक वह हमें अपनी बिरादरी में लेने के लिये भी तैयार नहीं होते हैं। इसलिये उन के साथ जाने का प्रश्न ही नहीं था। उन की तो नीति रही है कि जो देश प्रगतिशील हैं, जैसे कि भारत है, उन के तटस्थ रहने में ही वे प्रसन्न होते हैं। आज स्थिति यह है कि न रूस चाहता है कि हम उस के साथ रहें और न अमरीका चाहता है कि हम उसके साथ रहें, लेकिन हम खामखाह के लिये गीत गाते रहते हैं कि अलाइनमेंट हो या नानअलाइनमेंट हो। कोई कहता नहीं कि हमारे साथ आओ और हम जबर्दस्ती उसकी बात करते हैं क्योंकि जो हमारे विचारों में राजनीतिक मतभेद हैं वे सामने आ जाते हैं। हम ने एक ऐसी नींव बना ली है चलने के लिये, जिस की अब आवश्यकता नहीं है। आज किस नीति का परिणाम हुआ है कि एक तरफ चीन जो रूस के गुट में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि ऐंग्लो अमरीकन गुट में है, दोनों साथी बन गये ? गुट वाले उनसे कुछ कहते नहीं। रूस ने एक पत्र लिख दिया चीन को कि आप जो समझौता कर रहे हैं पाकिस्तान से वह गलत है, अमरीका ने भी समझाया पाकिस्तान को लेकिन वह भी लापरवाही कर गया। यह सब इस बात के प्रमाण हैं कि यह गुटबन्दी वगैरह के सोचने की जो बातें हैं वह खत्म कर दी गई हैं। आज प्रत्येक राष्ट्र अपना हित किस में है यह समझता है। सूझ बूझ के साथ हो या जल्दी के साथ हो, यह दूसरी बात है, किन्तु उस का दृष्टिकोण यह है। इसलिये जो पुरानी गुटबन्दी है उस में हेर फेर होने के आसार हो रहे हैं। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम आज बहुत बुरी अवस्था में आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दूसरी तरफ चीन हमारा दुश्मन है। हमारे बहुत से साथी चीन की बातें करने लगते हैं, बहुत से साथी पाकिस्तान की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में दोनों हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने जो आपस में समझौता किया है उसका असर हम पर क्या पड़ा है यह हमको देखना चाहिये। हमारे सरदार स्वर्ण सिंह जी बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा हो उनकी बातचीत सफल हो और हमारी विचारधारा को लोग गलत कह दें। लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी सफलता की बहुत कम सम्भावना है। जो कुछ पाकिस्तानी करने जा रहे हैं, उसकी चर्चा अखबारों में हो रही है और उसकी हरकतें ऐसी हैं जिनसे मालूम होता है कि समझौते के कोई आसार नहीं हैं। समझौता हो कैसे। अमरीका, जिसके गुट में वह है, खुल्मखुल्ला यह कहने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान अगर गड़बड़ करेगा तो हम हिन्दुस्तान का साथ देंगे। और रूस चीन से जो कि उस के गुट में है, यह खुल्लम-खुल्ला कहने को तैयार नहीं है कि अगर चीन और पाकिस्तान गड़बड़ करेंगे तो वह (रूस) भारत का साथ देंगे। तो फिर इस समस्या का हल कैसे हो। जो राजनीतिक उलझन पैदा हो गयी है वह कैसे पूरी हो। यह तभी ठीक हो सकती है जब कि हम रूस और अमरीका दोनों को यह बता सकें और उनके दिमाग में यह जमा सकें कि जो हमारा चीन से झगड़ा है वह सीमा का झगड़ा है, और जब आप दोनों भी यह मानते हैं कि यह सीमा का झगड़ा है तो अगर हम और चीन लड़ते हैं तो आप अपने अपने साथियों को मदद न करें, रूस चीन को मदद न करे और अमरीका पाकिस्तान को मदद न करे। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। यदि यह तै हो जाए तो फिर प्रश्न यह रह जाता है कि हम केवल अपनी शक्ति के आधार पर अपनी सीमा की समस्या को हल करेंगे चाहे इसमें कुछ देरी भले ही लग जाए।

८६७ करोड़ रुपया हमने सुरक्षा के लिए दिया है। रुपया तो और भी दिया जाएगा यदि आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि हमारी राजनीतिक स्थिति डांवाडोल रही और यदि हमारी सैनिक तैयारियां ऐसी ही रहीं—जिसके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा—तो चाहे हम देश का सारा बजट भी सेना पर खर्च कर दें, उससे भी लाभ होने वाला नहीं है।

इस देश में दूसरी रक्षा पंक्ति की आवश्यकता है और वह तभी हो सकती है जब तक कि हमारी जो तीन चार कमजोरियां हैं वे दूर हो जाएं। जब तक वे दूर नहीं होंगी तब तक हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। हमारी पहली कमजोरी तो यह है कि हमारे प्रजातंत्र में घुन लग गया है। आज प्रजातंत्र की दशा क्या है ? यह बात किसी से छिपी नहीं है। रूलिंग पार्टी की क्या दशा है। किस प्रकार छोटी छोटी बातों के लिए मिनिस्टर बयान देते रहते हैं। वे कहते हैं कि हमने कोई चन्दा नहीं लिया। जिस देश में हालत यह हो कि मिनिस्टरों के जरिये से चन्दा करा कर चुनाव लड़े जाएं उस देश में प्रजातंत्र की क्या हालत हो सकती है। आज अवस्था यह है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ कम्युनिस्ट चुनाव लड़ रहे हों और जन संघ वालों से कहा जाये कि तुम कांग्रेस की मदद करो तो वे वैसा करेंगे। अगर कहीं जन संघ वाले कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हों और कम्युनिस्टों को कहा जाए कि तुम कांग्रेस का साथ दो, तो वे कांग्रेस का साथ देंगे। तो फिर कांग्रेस को रहना है। यदि ऐसा ही है तो विरोधी दलों की क्या आवश्यकता है। ये जो हमारे प्रजातंत्र में त्रुटियां है इनको बदला जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ ने कहां कांग्रेस का साथ दिया।

श्री काशी राम गुप्त: जहां कांग्रेस का कम्युनिस्टों से मुकाबला हुआ वहां दिया। तो यह झगड़ा विचारधारा का है। जब तक इस तरीके में संशोधन नहीं होगा और जब तक इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की जायेगी कि इस देस में कम से कम पार्टियां हों, और उनकी विचारधारायें स्पष्ट हों और उन विचारधाराओं के आधार पर चुनाव हों, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकना। और यह तभी संभव हो सकता है जब लोक सभा के चुनाल बिलकुल अलग से किए जाएं और विधान सभाओं के चुनाव अलग से किए जाएं। । अगर हमारे प्रजातंत्र का यह घुन दूर नहीं किया जाएगा तो हमारा वही हाल होगा जो च्यांग काई शेक का हुआ था। उसको खूब अमरीका की मदद मिली, उसके पास खब सेना थी, लेकिन फिर भी उसको मुंह की खानी पड़ी। इसलिये हमारे प्रतिरक्षा के कार्य को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रजातंत्र को स्वस्थ बनाएं और सबल बनाएं।

हम को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि आज हमारी सैनिक दशा क्या है। हमको चीन से लड़ना है। चीन में क्रान्ति के बाद जो फौजी तैयारियां हुईं उन में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि वहां फौजी अफसरों और जवानों के रहन सहन के तरीकों में बहुत अन्तर नहीं रहा। इसके अतिरिक्त वहां की आर्थिक प्रणाली का भी फौज की उन्नति में बड़ा हाथ रहा है। हमारे यहां हम देखें तो फौजी अफसरों का रहन सहन आरामतलबी का हो गया है और कठोर जीवन बिताने में उनको कठिनाई का अनुभव होता है। आज फौजी अफसर दफ्तर में बैठता है और अगर पंखा नहीं तो उसको शिकायत होती है। वह कार से कम में चलने में अपनी शान नहीं समझता। अंग्रेज के जमाने में करनल लोग साइकिलों पर चलते थे। लेकिन क्या आज हमारे यहां के करनल साइकिल पर जाना पसन्द करेंगे। आज फौजी अफसर अपने बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलवाते हैं हिन्दी के माध्यम करेंगे। मैं उस इलाके से आता हूं जहां फौजी लोग बहुत हैं और मैं उस परिवार से आता हूं जिसका फौज से संबंध रहा है। आज भी मेरे मित्र ब्रिगेडियर और बड़े बड़े अफसर हैं। मैं देखता हूं कि वे मौखिक रूप से तो जवानों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन रहन सहन के मामले में उनसे बहुत दूर हैं। यह खतरनाक स्थिति है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि फौजियों के जीवन में परिवर्तन आवे और उसका यही तरीका हो सकता है वे कठोर जीवन बिताय। यही काफी नहीं है कि दैनिक परेड कर ली जाए। उससे कठोरता का अभ्यास नहीं हो सकता। उनको अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिये कि वे कठोरता को सहन कर सकें। यह इस देश की सुरक्षा के लिये बहुत आवश्यक है।

हमको अपनी आर्थिक प्रणाली में भी परिवर्तन करना होगा। जब हम किसी दुश्मन का मुकाबला करते हैं तो हमको अपनी आर्थिक प्रणाली भी उसके उपयुक्त बनानी चाहिए। हमारे देश में प्रजातंत्र

[श्री काशी राम गुप्त]

है, इसलिए हमारी आर्थिक प्रणाली निश्चित रूप से चीन की आर्थिक प्रणाली से भिन्न है। किन्तु हमारी आर्थिक प्रणाली में जो घुन लगे हैं उनको दूर करना हमारा काम है, और उन घुनों में सबसे बड़ा यह है कि आज हमारे यहां बाल विवाह धड़ा धड़ हो रहे हैं, बेरोजगार लोगों के विवाह हो रहे हैं। लड़का बी० ए० पास नहीं कर पाता और उसका विवाह कर दिया जाता है। नतीजा यह हो रहा है कि हमारी दशा सोचनीय होती जा रही है। देश गिरावट की तरफ जा रहा है, और इसका सुरक्षा से बहुत बड़ा संबंध है ।

इसी प्रकार से हम रोज के जीवन में देखते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गयी है, लेकिन क्या हो रहा है ? उसी प्रकार से शादी विवाह हो रहे हैं, उसी प्रकार से गुलछर्रे उड़ रहे हैं, वही तौर तरीके हैं और वही रहन सहन है। सब कुछ उसी प्रकार से हो रहा है। कहीं पर इमरजेंसी नहीं दिखायी देती। दुनिया म ऐसा इमरजेंसी के समय कहीं नहीं होता। इमरजेंसी के समय हम को अपना पेट काट कर भी देश की रक्षा के लिए धन जुटाना होगा। आज जनरल बजट के बारे में हम देखते हैं कि अमीर कहता है कि हम से धन मत लो। जन साधारण तो कहेगा ही हम से मत लो। कोई भी यह नहीं कहता कि जो टैक्स लगे हैं वे ठीक लगे हैं। मैं कहता हूं कि यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है देश की सुरक्षा का। उसके लिए जो धन चाहिये उसको देने म भी हम झगड़े करते हैं। इस तरह से हमारा काम चलने वाला नहीं है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन् में आपका ध्यान आडिट रिपोर्ट १९६३ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार ५ करोड़ से अधिक रुपया तो ऐसे नुकसानों का होगा जो कि १५ हजार से अधिक थे अथवा ५० हजार से अधिक के थे। इससे कम वालों का तो कोई अनुमान ही नहीं किया गया। जो कार्यक्रम सन १९५२ में शुरू हुआ वह ९ वर्ष में जा कर पूरा हुआ है। अगर हमारी सुरक्षा का यही क्रम रहा और इसी कार्यक्रम पर हम चलना चाहते हैं तो इस देश की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी और किसी और देश को वह सुरक्षा सौंप देनी चाहिये।

आगे चल कर मैं अर्ज करूं कि जो ट्रैक्टर्स बनने थे और जितनी उस में तादाद निकली थी उस से एक चौथाई या एक तिहाई ही बन सके।

श्री इकबाल सिंह : टैंक बनवाइये न ? टैंकों की जरूरत है।

श्री काशी राम गुप्त : अभी श्री इकबाल सिंह जैसा कि कह रहे हैं कि ट्रैक्टर्स नहीं टैंकों की जरूरत है तो मैं भी कहता हूं कि आज टैंकों की देश को जरूरत है।

मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जिसकी जरूरत नहीं बतला रहे हैं वे पूरे बने नहीं लेकिन जिसकी जरूरत है वह तो बन ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा कह कर आप की बात की ही ताईद कर रहा हूं।

फिर लीसेज के अलावा और इन सब बातों के अलावा मिलेटरी फार्म्स को देखें तो उसमें नुकसान दिखता है। दूध चौगुना मंहगा हो गया है और न मालूम क्या क्या बातें हैं ? जितनी ब्रांचेज हैं उनको देखिये, उनकी बाबत एक लम्बा चौड़ा चिट्ठा है और अगर उस सारे को मैं पढ़ने लगूं तो बहुत समय लगेगा। वह तो सब के पास है। इसलिए आडिट रिपोर्ट के ऊपर और अधिक न जाकर मैं मिनिस्ट्री आफ डिफेंस की सन् १९६२-६३ की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कल माननीय सदस्या श्रीमती शारदा मुकर्जी ने भी उसकी तरफ ध्यान दिलाया था। उस में एक जगह लिखा है कि फौरेन लैंग्वेजेज के साथ साथ फौजियों को हिन्दुस्तानी भाषा भी सिखायी जायेगी। इस रिपोर्ट के पेज ४३ पर स्कूल

ऑफ फौरेन लैंग्वेजेज के हैड के नीचे यह लिखा हुआ है :——

"स्कूल हिन्दुस्तानी में सेवा कर्मचारियों के लिए परीक्षा भी लेता है।"

जब हमारे देश की राष्ट्र भाषा स्वीकृत हो चुकी है तब मेरी समझ में नहीं आता कि यह हिन्दुस्तानी कहां बाकी रह गई ? इसी तरह पंजाबी, मराठी, नेपाली, लुशायी, आसामी और तेलगू आदि भाषाएं फौरेन लैंग्वेजेज के साथ जुड़ी हुई है . . .

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तान में जो रहे उसकी भाषा हिन्दुस्तानी है।

श्री काशी राम गुप्त : अब वह हिन्दुस्तान इस वर्तमान भारत से कोई जुदा ही हिन्दुस्तान होगा।

ऐसी बातें कहना और हिन्दी न लिख कर हिन्दुस्तानी लिख देना जाहिर करता है कि यह प्रतिरक्षा मंत्रालय आंख मूंद कर जो कुछ लिख दिया जाता है उसी को रिप्रोडयूस कर देता है और यह देखने की पर्वाह नहीं करता है कि वह गलत है या दुरुस्त है। हिन्दुस्तानी शब्द न लिखा जाकर हिन्दी लिखा जाना चाहिये था।

इसके अतिरिक्त श्री इकबाल सिंह जैसा कि अभी फरमा रहे थे कि हिन्दुस्तान ऐयरक्राफट फैक्टरी बंगलौर में रेल कोचेज बनती है तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर अब रेल कोचेज बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वहां पर जरूरी फौजी सामान की बनाने की आवश्यकता है।

मेरा निवेदन यह भी है कि आजकल जो इमरजेंसी कमिशन चल रहा है और उसमें टैकनिकल हैंडस नहीं आ रहे हैं उसका एक खास कारण यह है कि लोगों को यह भरोसा नहीं है कि जो सरकार अभी भरती कर रही है वह स्थायी रहेगी। सरकार यह तो बराबर ऐलान कर रही है कि हां हम पूरी तैयारी रक्खेंगे और हम अपनी तैयारियों में कमी नहीं करेंगे लेकिन भरती होने वाले यह सोचते है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि साल दो साल में कोई आपस में सुलह समझौता हो जाय और सरकार उस वक्त हमको निकाल बाहर करेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इमरजेंसी कमीशन में जो आज कमी पड़ रही है उस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय को साफ तौर से लोगों को यह बतलाना चाहिए कि भले ही टैकनिकल टर्म्स के लिहाज से तकनीकी परिभाषा में इमरजेंसी का अर्थ टैम्पोरेरी हो सकता है लेकिन अमली जीवन में हम जो अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ा रहे है उनको आगे चल कर बाहर नहीं निकाला जायगा और उनको वापिस नहीं किया जायगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने उम्र को ३० वर्ष कर दिया है जिससे कि नौजवानों को यह महसूस हो सके कि वें काफी दिन तक वहां रह कर सेवा कर सकेंगे।

नेफा और हिमालियन बोर्डर्स के बारे में अपनी सैन्यशक्ति में वृद्धि करने के बारे में बहुत से लोगों ने चर्चा की है। मेरा भी सुझाव है कि उधर विशेष रूप से प्रतिरक्षा मंत्रालय ध्यान दे और वहां पर मिलिशिया में और वृद्धि करने के अलावा वहां के लोगों को फौज में भरती करके उनको माउंटैन वायरफेयर के लिए विशेष रूप से तैयार करना चाहिये ताकि वह समय पर उपयोगी सिद्ध हो सकें।

बहुत से साथी कहते है कि हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी एक प्लान के मुताबिक हो। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि हमारी तैयारी का एक प्लान होना चाहिये। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कोई प्रोडक्शन प्लान नहीं है कि इसके कोई स्टैटिक्स तैयार हो सकें। यह प्लान तो इस आधार पर होगा कि हमारे चारों तरफ के मुल्कों का क्या रवैया है और हमारी प्रतिरक्षा को उन से कहां तक खतरा है ? उसका मुकाबला करने के लिए हम को शोर्ट टर्म और लौंग टर्म प्लांस बनाने की आवश्यकता है और यह देखना होगा कि परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ हम अपना परिवर्तन किस रूप में कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्लानों के लिये कोई स्थायित्व का प्लान इस प्रकार से नहीं आ सकता है।

[श्री काशी राम गुप्त]

हमको तो यह देखना पड़ेगा कि हमें अपनी तीनों जल थल और नभ सेनाओं में आज की अपनी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए क्या सुधार या तबदीली लानी आवश्यक है, किस तरह उसको बढ़ावा दे सकते हैं और किस प्रकार उसमें आज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार से हम अपने जवानों के हौसले को बढ़ा सकते है ?

मैं संक्षेप में कुछ चुनावों की चर्चा करना चाहूंगा। आज यह स्थिति है जनमानस की कि हमारे जो फौजी जवान होते है जब वह यह देखते हैं कि सरकार कांग्रेस की है और चूंकि फौज का काम सरकार की मदद करनी है इसलिए वोट डालते वक्त वह एक ही बात जानते हैं कि मौजूदा सरकार की मदद की जाय और उधर ही उनका वोट पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि फौज को प्रजातंत्र का सही अर्थ समझाया जाय क्योंकि इस तरह की भ्रामक धारणा फौजियों के अंदर बनी रहने से ऐसी फौज प्रजातंत्र के लायक नहीं होती है। इसलिए उनको इस बात की उचित शिक्षा दी जाय ताकि वह सही तौर से प्रजातंत्र को मजबूत कर सकें।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि यह प्रतिरक्षा मंत्रालय जिस नौजवान के हाथ में आज आया है वह देश के एक सफल राजनीतिज्ञ है किन्तु इसके साथ यह जरुरी है कि वे यह देखें कि उनके चारों तरफ क्या होता है और उसका क्या असर यहां पर आता है यहां पर यह देखा जाता है कि वायर पुलिंग होती है और अपनी गलती को छिपाने के लिए किसी एक व्यक्ति को बलिदान करने की कोशिश की जाती है। जो कुछ खाद्य मंत्री से गलती हुई है वह सारे कैबिनट की ज्वाएंट रिसपोसिबिल्टी है और वह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं हुई है। इस का कारण यह है कि हमारी जो लोक सभा है उस का कम से कम प्रतिरक्षा के मामले में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। उनका विश्वास नहीं किया गया और उसका नतीजा यह हुआ जो कि आज हमारे सामने है।

बस एक मिनट में मैं समाप्त किये दे रहा हूं। आज अमरीका जो हम से बार बार कह रहा है कि तटस्थ रहें उसका एक रहस्य है। वह यह जानता है कि पाकिस्तान उन का साथी है। अगर वह हमें अपने साथ लेने का प्रयत्न करता है तो पाकिस्तान जिसकी कि हम से कभी नहीं बनती उसका सिरदर्द कौन मोल ले ? इसलिए अमरीका की जो वर्तमान नीति है वह उनके अपने मतलब के लिए है। उसका मतलब यह है कि इस समय वह पाकिस्तान के हित को देखते हुए ही हमारी कोई बात पूरी करेंगे। यही कारण है कि अमरीका आज हमसे कहता है कि आप तटस्थ ही रहें तो ठीक रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री महोदय यदि उन से बात करते हैं तो अमरीका और रुस इन दोनों से खुशी से बात करें लेकिन जरा स्पष्टता से करें कि अभी तो यह लड़ाई बोर्डर की लड़ाई कहलाती है लेकिन अगर कल को यह बोर्डर की लड़ाई फुल स्केल लड़ाई में बड़ी लड़ाई में बदल जाय तो अमरीका और रुस यह दोनों देश उसके बारे में क्या रवैया अखत्यार करते हैं, अपने अपने गुटों के साथ रहते हैं या क्या करते हैं, उनकी साफ प्रतिक्रिया इस बारे में हमें मालम हो जानी चाहिये और उसके आधार पर ही हमें अपनी नीति बदलनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। मैं अन्त में आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

†श्री दि० ना० सिंह (मुज़फ्फरपुर) : मैं सब से पहले नेफा के जंगलों में देश की रक्षा करने वाले जवानों की अभ्यर्थना करता हूं और उन देशों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आपातकाल में हमें सहायता सैनिक शक्ति को दुगुना करने का निर्णय सराहनीय है। इसके साथ ही हमारी सेना के पास आधुनिकतम हथियार होने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में हमारी हार के बारे में तो जांच हो ही रही है और आशा है कि अपराधियों को दंड दिया जायेगा। लिज्ल हार्ट ने अपनी पुस्तक में चीनियों की चालों के बारे में लिखा है कि वे छोटे मोटे हमले करते रहेगें और बीच बीच में समझौते की बातचीत चलायेंगे।

पिंडी-पीकिंग समझौता भी बहुत खतरनाक और इस बार चीन ने आक्रमण किया तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। अयूब ने तो हाल ही में लायलपुर में भाषण देते हुए कहा है कि यदि भारत ठीक रास्ते पर न आया तो पड़ोसियों के साथ भीषण संघर्ष में ग्रस्त हो जायेगा।

आजाद काश्मीर के अब्बास और कयूम ने श्री जार्ज पेटसन के साथ भेंट में कहा कि वे भारत पर हमले करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा की तो पूरी तैयारी करनी ही चाहिये साथ ही प्रतिरोध करने की भी तैयारी जरूरी है अगली बार भारत की सेना यह बता देगी कि चीन की सेना ऐसी नहीं कि उसे जीता ही न जा सके ? मुझे इस में तनिक भी संदेह नहीं कि हमारी सेना चीनियों का खूब मुकाबला कर सकती है। हमें अपनी नौसेना को भी मजबूत बनाना चाहिये क्योंकि संभव है अगले आक्रमण में चीनी अपनी पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में भेज कर भारत की सपलाई लाइन तोड़ने की कोशिश करे। मुझे आशा है कि हमारे सूयोग्य मंत्री अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे।

†**श्री अ० व० राघवन** (बडागरा) : जिन वीर जवानों ने आक्रमणकर्ता का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहूतियां दी मैं उन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं समझता हूं कि चीन से खतरे के परिणामों को हमने पूरी तरह समझा नहीं है। इस से हमारे संसाधनों पर अभूतपूर्व बोझा पड़ने वाला है। विदेशों से जो ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता हमें मिली है उसके लिए हम उन देशों के आभारी है, परन्तु उसका पूर्ण उपयोग हम तभी कर सकते हैं यदि हम स्वयं सक्षम और सशक्त हों। चूंकि यह खतरा बहुत व्यापक है इसलिए हमें अधिक से अधिक प्रतिरक्षा संबंधी तैयारी करनी होगी और साथ ही साथ देश के निर्माण कार्यों में ढील नहीं लानी होगी ? रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर अत्यधिक धन की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्य आरम्भ हो भी चुका है विदेशों से हमें सहायता मिल सकती है परन्तु अन्ततः हमें देश में ही सभी प्रकार के हथियार और हवाई जहाज निर्मित करने होंगे। इसलिए हमें अर्थ संबंधी आवश्यकताओं को आंकना पड़ेगा।

जवानों के प्रति हम भावुकता का प्रदर्शन तो करते हैं परन्तु उन की सेवा की शर्तें अनुचित हैं। उनके वेतन संसार में सब से कम है। सहस्त्रों जवान पदोन्नति बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अधिकतर जवान एफ, जी और एच० वर्ग में हैं जिन का मासिक वेतन केवल ५५ रुपये है। इस के अतिरिक्त एक वर्ग के जवान को केवल अपने ही वर्ग में तरक्की मिल सकती है। एक सब लैफ्टिनेंन्ट को कुछ समय के पश्चात्, लैफ्टिनेंट बना दिया जाता है, परन्तु एक जवान पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् केवल २½ रुपये बढ़ोत्तरी पाता है और दस वर्ष की सेवा के पश्चात् फिर २½ रुपये बढ़ोत्री पाता है। एक अधिकारी को २४ वर्ष की सेवा में २५० प्रतिशत वृद्धि मिलती है जहां कि एक जवान को इस काल में केवल ९ प्रतिशत वृद्धि मिलती है। इस प्रकार की अनियमितता और असमानता अनुचित है।

निवृत्ति-वेतन मान की भी यही हालत है। एक जवान को १५ से २० रुपये तक निवृत्तिवेतन मिलता है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि १७ वर्ष की सेवा के पश्चात् भी जवान को परिवार निवृत्ति-वेतन नहीं दिया गया क्योंकि उस की मृत्यु अस्पताल में हुई। मेरा अनुरोध है कि निवृत्ति-वेतन संहिता में उचित रुप भेद लाये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० व० राघवन]

अधिकारागण को जो परिवार स्टेशन पर नहीं रहता ५०रुपये प्रतिमास परिवार से अलग रहने का भत्ता दिया जाता है, परन्तु जवान को न तो क्वार्टर संबंधी उचित सुविधा दी गई है और न परिवार से अलग रहने का भत्ता ही दिया जाता है ।

भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी भी नहीं मिल पाती । राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में २५ प्रतिशत स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षित होने चाहिएं ।

प्रतिरक्षा सम्बंधी उद्योगों और योजनाओं पर हम करोडों रुपया व्यय कर रहे हैं परन्तु यह खेद का विषय है कि आंध्र प्रदेश और केरल की इस क्षेत्र में अवहेलना की जा रही है । इस से इन क्षेत्रों में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि वह देश की रक्षा सम्बंधी कार्यों में भाग नहीं ले रहे । इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

नेफा तथा लद्दाख में हमारे जवानों को पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करना पड़ता है । उन्हें वहां रहने और युद्ध करने सम्बंधी उचित सुविधायें दी जायें इस बारे में वैज्ञानिकों और अनसन्धान करने वालों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिस के आदेश का पालन सैनिक करें और जिस के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना दिखायें । यदि ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे तो सैनिकों का नैतिक साहस कम होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर): मैं कठिन परिस्थितियों में यद्ध कर रहे वीर जवानों को मुबारकवाद पेश करता हूं ; और नये प्रतिरक्षा मंत्री का स्वागत करता हूं ।

नये प्रतिरक्षा मंत्री के आगमन के फलस्वरूप अनेकों सुधार हुये हैं । जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह भी स्पष्ट और संतोषजनक है । उसमें हमारी आवश्यकताओं, उनकी पूर्ति, गत वर्ष की त्रुटियों और अन्य बातों का स्पष्टतः उल्लेख है ।

इस प्रतिवेदन में यह वर्णित है कि आपात के समय हमारी सेनाओं ने अच्छा काम किया । मैं मानता हूं कि हमें हार हुई, हमारी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा, परन्तु हमें देखना यह है कि ऐसा क्योंकर हुआ । उस का एक कारण तो यह है कि आरम्भ में आक्रामक की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी होती है । दूसरे, हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है और चीन के समान हमने सेना बढ़ा कर और तैयारी कर के किसी पड़ौसी देश पर आक्रमण की बात कभी नहीं सोची थी । हम तो देश के विकास कार्यों में जुटे हुए थे । हमारे देश में एक भाग लोगों का ऐसा भी है जो इस आपात काल में हमारे नेतृत्व को नीचा दिखाना चाहता है हमारी सेना के नैतिक साहस को कम करना चाहता है और प्रतिरक्षा का नाम ले कर विकास योजनाओं को ठप्प करना चाहता है । परन्तु ऐसे लोगों के होते हुए भी हमारी जनता ने और सेना ने आपात में अच्छा काम किया । आरम्भ में हार होना बहुत बड़ी बात नहीं है । चर्चल को डंकर्क में निरन्तर दो वर्षों तक हार होती रही फिर भी स्टालिन और अमरीका उस के समर्थक थे । मैं ऐसा कह कर अपनी हार की महत्ता को कम नहीं करना चाहता, परन्तु मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि लोकतंत्र युद्ध की तैयारी में रत नहीं रहता बल्कि देश के निर्माण और विकास में विश्वास रखता है गत १५ वर्षों से हम देश के विकास कार्यों में जटे हुए हैं और देश का आर्थिक विकास काफी सीमा तक सम्पन्न हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी आर्थिक विकास के आधार पर हम आयद्ध कारखाने स्थापित कर सकते हैं। और जो गत ८ मास से कार्य हुआ भी है वह भी इसी आर्थिक विकास के वल पर ही हुआ है। युद्ध सम्बंधी तैयारी के पीछे सेना और आयुद्ध कारखाने ही नही होते बल्कि समस्त देश और देश की आर्थिक स्थिति होती है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो अवश्य ही हमने सराहनीय और सन्तोषजनक कार्य किया है।

स्थल सेना के साथसाथ हमें अपनी वायु सेना को भी अत्यधिक सशक्त बनाना है। परन्तु एक बात हमें सदैव अपने सम्मुख रखनी है कि हमारी वाय सेना शक्ति का विस्तार हमारे द्वारा निर्धारित गुट बन्दी से अलग रहने की नीति के अनकूल हो। जिन विदेशी सरकारों ने संकट के समय हमारी सहायता की उनके हम आभारी हैं और हमें विदेशी सहायता को निर्बाध रूप से स्वीकार करना है, परन्तु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि हम सदैव अपनी ही इच्छा के अनकूल काम करें और अपनी सैनिक सत्ता को किसी अन्य देश के हवाले न करें। सत्ता को स्वयं हमारे हाथों में रहना चाहिए और किसी देश की अधीनता स्वीकार नहीं होनी चाहिए। भले ही हम ऋण के रूप में सहायता लें, परन्तु हमें किसी गुट में शामिल न होकर, और किसी अन्य देश को अपनी सत्ता न देते हुए, स्वयं अपनी नीतियों के अनुसार कदम उठाने योग्य बनना है। इस बात को ध्यान में रख कर ही हमें अन्य देशों से सहायता स्वीकार करनी है और अपनी वायु शक्ति को बढ़ाना है।

चीन सरकार का एक मिशन इस समय ब्रिटेन में कुछ वाययान खरीदने के लिये गया हुआ है। हमें इस बात का अत्यन्त खेद है। यदि ब्रिटेन ने चीन को वाययान दिये तो निश्चय ही यह एक अमित्रतापूर्ण बात होगी।

गत वर्ष नेफा आदि क्षेत्रों में जो हमारी सेनाओं को हार हुई उस के बारे में जांच होनी चाहिए और अपने पूर्व के अनुभवों से हमें सबक सीखना चाहिए परन्तु मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस जांच को एक सीमा से परे न ले जाया जाय। ऐसा करने से भविष्य में हमारे सेना के प्रयासों में विघ्न पड़ने की आशंका है। ऐसी जांच पर अधिक बल देने से और इसे एक सार्वजनिक जांच बना देने से हमें हानि होगी।

निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा एक शिकायत की जा रही है कि प्रतिरक्षा प्रयासों में उन को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि इस में अत्यधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता है, एवं विदेशों से अधिक सामान मंगवाया जाना है तो बेहतर है कि प्रतिरक्षा संबंधी कार्य स्वयं सरकार द्वारा किये जायें और निजी क्षेत्र की आवाज़ न सुनी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): हमारे जवानों ने नेफा तथा लद्दाख में जिस साहस का प्रमाण दिया है, और कई एक कठिनाइयों के बावजूद भी वह जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में लड़े हैं, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। निश्चय ही यह बलिदान की भावना देख कर भारत का सम्मान अन्य देशों की दृष्टि में बढ़ गया है।

गत वर्ष जो हमें हार हुई उस की जांच हो रही है और यह देखने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कौन कौन सी त्रुटियां और कमियां रह गई थीं जिन के कारण हमें हार हुई। यह समर्थन योग्य बात है। परन्तु मेरा सुझाव है कि इस जांच का अधिक विस्तृत आधार होना चाहिए ताकि हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बंधी दुर्बलताओं का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री प्र० चं० बरुआ]

यह कहना गलत है कि आयुद्ध कारखानों में सन्तोषजनक उत्पादन नहीं हुआ है। ४८ से भी अधिक पुष्पक वाययानों का उत्पादन कृषक वायुयानों के निर्माण कार्य में विकास, आरफियस-७०१ जेट इंजनों के निर्माण कार्य में प्रगति, यह सब इस बात के द्योतक हैं कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है।

चीन जैसे आक्रमक का मुकावला करने के लिये हमें न केवल आंतरिक संसाधनों को ही जुटाना है बल्कि विदेशों से सहायता भी प्राप्त करनी है।

चीनी आक्रमण से सिद्ध हो गया है कि हमारी गुट वन्दी से अलग रहने की नीति उचित है। जहां अमरीका ने और ब्रिटेन ने हमारी सहायता की वहां रूस ने भी मिग कारखाना स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है और शायद उसी के प्रभाव डालने पर चीन को युद्ध-विराम घोषित करना पड़ा।

चीन के पास स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना बहुत सशक्त है अतः उस का सामना करने के लिए उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिए।

अणु शक्ति विभाग की मांगों पर बहस के समय हमें बताया गया कि चीन अभी अणु बम नहीं बना सकता और कि भारत का परमाणु आयुद्ध उत्पादन का विचार नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस बारे में हमें अधिक विचार करना चाहिए। यदि भविष्य में चीन अणु बम तैयार करके हमारे ऊपर गिरा दे तो हमें क्या करना होगा। चीन के ऊपर विश्वास न करते हुए हमें अणु शक्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

गत वर्ष के आक्रमण के समय सब से अधिक नेफा क्षेत्र ही प्रभावित हुआ। ऐसा कहा जाता था कि चीनी समस्त असम पर कब्जा करने वाले हैं। अब भी असम के लोगों में से यह भय नहीं गया है क्योंकि चीनियों की तैयारियों संबंधी सूचनायें वहां पहुंचती रहती हैं और अपने क्षेत्र में भारतीय सेना वहां पर उपस्थित ही नहीं है। असम को डर है कि उस क्षेत्र को उस की किस्मत पर छोड़ दिया जायगा। इस का कारण यह है कि द्वितीय महायुद्ध में वहां के लोगों ने युद्ध संबंधी गतिविधियों को देखा और आज जब कि चीन हमारी सीमाओं पर बैठा है हमारी सेनायें वहां पर नहीं हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आधुनिक आयुधों से लैस अधिक से अधिक सेना को इस क्षेत्र में तैनात किया जाय ताकि वहां की जनता में विश्वास बढ़े।

असम में बाढ़ की अवस्था बड़ी भीषण है। आप तब तक प्रतिरक्षात्मक दृष्टि से वहां विकास नहीं कर सकते जब तक इस बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से हल न करें। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा की दृष्टि से सड़कों और पुलों का होना आवश्यक है। असम क्षेत्र में सड़कों और पुलों की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

रेलवे संचार की व्यवस्था भी अत्यधिक आवश्यक है। सिलिगुडी से जोगीघोपा तक बड़ी लाइन बना कर बहुत अच्छा काम किया है परन्तु अधिक अच्छा यह होता कि यह लाईन गौहाटी तक ले जायी जाती।

आसाम राईफल्स और काश्मीर मिलिशिया को सैनिक स्तर पर लाना चाहिए और उन की सेवा की शर्तें भी वैसी ही होनी चाहिएं। उन कठिन मार्गों और क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले यह लोग बहुत सहायक सिद्ध होंगे।

†श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : सर्वप्रथम, मेरा अनुरोध है कि इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये बहुत कम समय आवंटित किया गया है। इस समय प्रतिरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है और हम अपने आयव्ययक का ३० प्रतिशत इस के लिये दे रहे हैं तो हमें अधिक समय मिलना चाहिये ताकि हम अपने विचार सभा के समक्ष रख सकें।

इस समय अहिंसावादी भी तलवार में विश्वास पैदा कर रहे हैं यह सन्तोषजनक बात है।

गुट बन्दी से अलग रहने अथवा गुट में शामिल होने संबंधी चर्चा आज बहुत की जा रही है, परन्तु हमें एक बात सम्मुख रखनी चाहिये कि अपनी रक्षा करना सर्वोत्तम महत्व की बात है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की बजाय स्वयं सब कुछ तैयार करना चाहिये। परन्तु यह कैसे हो सकता है कि थोड़े समय में वायुयान बना लिये जायें, सेना को प्रशिक्षित भी कर लिया जाय, और आधुनिक हथियार भी प्राप्त कर लिये जायें। जब युद्ध आरम्भ हुआ था तो हर तरफ तैयारी हो रही थी परन्तु आज वह गति नहीं रही है। इसलिये सम्मुख रखने वाली बात यह है कि हमें अपने देश की रक्षा करने के लिये हर तरह से तैयार रहना चाहिये और यदि विदेशों से सहायता लेनी पड़े तो उसमें भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिये।

हमारी अच्छे और सहयोगी देशों से मित्रता स्थापित करने की नीति ठीक नहीं रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सच्चे मित्र को पहचाने और उसके साथ अपने संबंध घनिष्ट करें ताकि वह समय पर हमारे काम आये। हमने देख लिया है कि जिसे हम भाई कहते रहे उसी ने हमें धोखा दिया।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिये जो धन जुटाया जा रहा है मैं समझता हूं कि इस से भी अधिक धन के जुटाने की आवश्यकता है। परन्तु जिस प्रकार यह राशियां प्राप्त की जा रही हैं उससे मुझे शिकायत है। आप फिजूल खर्ची को रोकने और मितव्ययता लाने की बजाय जो लोग आगे ही दबे हुये हैं उन पर और करों का बोझा डाल रहे हैं। जब तक आप फिजूलखर्ची बन्द नहीं करते और मितव्ययता नहीं लाते तब तक अधिक कर लगाने का आपको अधिकार नहीं है। मेरा सुझाव है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित किया जाय जो प्रशासन में मितव्ययता आदि के बारे में सुझाव दे। यदि ऐसा किया जाय तो अधिक बचाया जा सकता है और इन करों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मेरा सुझाव है कि हम आक्रमण की प्रतीक्षा करने की बजाय स्वयं शत्रु पर हमला करने की योजना बनायें।

हमें प्रतिरक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना चाहिये जो एक वर्ष के लिये हो और हमारा आयव्ययक उसी योजना अथवा कार्यक्रम के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये।

अच्छे सेना अधिकारियों का होना आवश्यक है। परन्तु इस के लिये उचित सेवा की शर्तें होनी चाहियें। पदोन्नति और अमण के बारे में पुनर्विचार होना चाहिये। जिन अधिकारियों का अवमण हुआ है उनके मामलों की जांच होनी चाहिये।

सेवानिवृत्त वरीय पदाधिकारियों को पुनः सेवा में लिया जाना चाहिये। उनके अनुभवों से काफी लाभ उठाया जा सकता है।

†**श्री बाल कृष्णन** (कोइलपट्टी) : चीनी आक्रमण से हमें उसी तरह लाभ प्राप्त हुये हैं जिस तरह प्राचीन काल में दैत्यों से हुआ करते थे ; इससे हम ने अपनी सैना की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया है, देश में एकता बढ़ी है। हम ने इस आक्रमण से सबक ले कर अपनी शक्ति को बढ़ाना आरम्भ किया है और भविष्य में हम ऐसे आक्रमण का सामना कर सकेंगे।

आयव्ययक में प्रतिरक्षा कार्यों के लिये जितना धन उपलब्ध किया गया है यह उत्साहजनक बात है। चीनी आक्रमण के समय हम ने देखा कि किस प्रकार जनता ने बलिदान की भावना व्यक्त की। जवानों ने नेफा और लद्दाख में वीरता का प्रदर्शन किया। मुझे विश्वास है कि पूर्व के सबक से हम अधिक शक्तिशाली बन गये हैं।

जो धन हम प्रतिरक्षा कार्यों के लिये उपलब्ध कर रहे हैं वह अन्य देशों की अपेक्षा अधिक नहीं है। अमरीका प्रतिरक्षा पर अपनी राष्ट्रीय आय का ९.८ प्रतिशत ब्रिटेन ६.५ प्रतिशत, फ्रांस ६.२ प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। हमारा व्यय केवल २.५ प्रतिशत ही है। आज १५ वर्ष से हमारे देश की सरकार देश के विकास कार्यों में मग्न थी इसलिये प्रतिरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। परन्तु आज आपात काल में यह आवश्यक है कि अधिक धन इस क्षेत्र में व्यय किया जाय।

वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रयत्न किये जाने चाहियें। क्योंकि इस क्षेत्र में हम अधिक पिछड़े हुये हैं। यह खेद की बात है कि नेफा में सामान गिराने के लिये एक निजी क्षेत्र के वायु समवाय को नियुक्त किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिये था।

सैनिक स्कूल हमारे देश में बहुत कम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक सैनिक स्कल खोले जायें और साथ ही साथ गरीबों के लिये इन स्कूलों में शुल्क रहित शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केवल धनी लोग ही इन स्कूलों का लाभ उठा सकते हैं।

सेना में भर्ती के लिये बहुत से जवान गये परन्तु परीक्षा अधिक कठिन होने के कारण उन्हें नहीं लिया गया। मेरा अनुरोध है कि वीरता कद लम्बा होने और छाती चौड़ी होने से नहीं आती। यह तो दृढ़ता और साहस की बात है। अतः भर्ती के लिये परीक्षा इतनी कठिन नहीं होनी चाहिये।

जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उनके लिये अधिक प्रादेशिक सेना शिविर खोले जाने चाहियें।

अणु बम बनाने संबंधी अपनी नीति पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। क्योंकि संसार के बहुत से देश आज अणु बम बना रहे हैं। इस क्षेत्र में हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिये।

अणु बम से भी अधिक शक्तिशाली एक और हथियार है, वह है प्रचार। प्रतिरक्षा मंत्री को चाहिये कि वह देश में घूम कर प्रचार करें और लोगों को अधिक से अधिक योगदान देने के लिये कहें।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवल्ला) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा भारतीय सैनिकों की वीरता की सराहना करता हूं। मैं नये प्रतिरक्षा मंत्री के प्रति भी अपनी सद भावना प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने इस संकट काल में इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस वर्ष प्रतिरक्षा बजट लगभग तिगुना है। इस बजट से कोई भी असहमत नहीं होगा क्योंकि प्रतिरक्षा का कार्य देश की सब से महत्वपूर्ण आवश्यकता है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्र दल के सदस्यों ने इसकी आलोचना की है और यह कहा है कि जब हमारे मित्र राष्ट्र, अमरीका इत्यादि, हमें सहायता देने के लिये तैयार हैं तो जनता पर इतना भार लादने की क्या आवश्यकता है। कोई भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि यह बजट प्रतिरक्षा के लिये पर्याप्त है। किन्तु हम इस कार्य के लिये किसी दूसरे राष्ट्र पर भी निर्भर नहीं रह सकते। स्वतंत्र नागरिकों के कुछ कर्त्तव्य और दायित्व हैं। यह हो सकता है कि कोई प्रतिरक्षा में आत्मनिर्भर न हो किन्तु इसके लिये यदि कोई अपना सर्वस्व नहीं दे देता तो निश्चय ही वह स्वतंत्र रहने का अधिकारी नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि प्रतिरक्षा की पूर्ण तैयारी के लिये यह आवश्यक है, कि हम आधुनिक अस्त्रों का निर्माण करें। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्वावलम्बनीयता का गुण-गान किया था। मैं भी स्वावलम्बनीयता के पक्ष में हूं। किन्तु स्वावलम्बनीयता और आत्म निर्भरता में अन्तर है। जब शत्रु सिर पर चढ़ा हुआ हो, तब केवल दीर्घ कालीन तैयारियों पर सारा ध्यान केन्द्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिये मैं सरकार की प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने और बाहर की सहायता से संसाधनों में वृद्धि करने की नीति की सराहना करता हूं।

सदस्यों ने हमारी सेना की शक्ति बढ़ाने और नेफा में हमारी पराजय के कारणों की जांच करने के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं इन बातों की पुनरावृत्ति करना तो नहीं चाहता, किन्तु यह अवश्य कहूंगा कि इस समय हमारी युद्ध संबंधी नीति के पुनिरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। जबकि युद्ध क्षेत्र में युद्ध-संचालन से संबंधित निर्णय लेना सेना का कार्य है, वहां सामान्य युद्ध नीति के विषय में राजनैतिक निश्चय की आवश्यकता है। हम किसी के प्रति आक्रमक नीति अपनाना नहीं चाहते किन्तु बचाव की युद्ध की नीति भी खतरनाक और आत्मघाती है।

आपातकालीन संकल्प पर बोलते हुये मैंने चीन की क्रांतिकारी नीति के स्वरूप को समझने के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने अपनी इस नीति को अपने गृह-युद्ध जापान से हुये युद्ध और कोरिया युद्ध में पूर्ण रूप से विकसित कर लिया है। वह अधिकतर चल-युद्ध नीति में विश्वास करते हैं। और यह स्थिति भारत में विद्यमान है, क्योंकि हमारी चीन से मिली हुई सीमा काफी विस्तृत है। और यह पहाड़ी क्षेत्र है।

हम इस प्रकार की युद्ध नीति का सामना किस प्रकार कर सकते हैं। क्या हम बचाव के युद्ध से ऐसा कर सकते हैं? चीन एक लम्बे और चल-युद्ध क्षेत्र में विश्वास करता है। हम इसका सामना उस समय तक नहीं कर सकते जब तक हम अपनी सेना को पहल करने का अधिकार नहीं दे देते जिससे कि वह शत्रु के रुख को मोड़ सके, उसे चकित कर सके, उसकी सेना के जमाव को और उसकी युद्ध सम्बन्धी चालों को छिन्न भिन्न कर सके। जब तक शत्रु के संभरण और संचार के समस्त मार्गों को ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक हम इस संकट का सामना नहीं कर सकेंगे। यह सब बातें राजनैतिक निर्णय पर निर्भर करती हैं। जब तक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता, सेना देश की प्रतिरक्षा करने में सफल नहीं हो सकेगी। चाहे पर्वतीय प्रदेश हो अथवा मैदान जब तक हमारी सेना के हाथ में विभिन्न प्रकार के आक्रमण करने और उनके संचार पथ को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं दे दिया जाता तब तक इस प्रकार के शत्रु पर विजय पाना कठिन है।

अन्त में मैं फिर इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि हम चीनी आक्रमण के विरुद्ध अपने संघर्ष में विजयी होंगे।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : हमारी प्रतिरक्षा की नीति की असफलताओं के विषय में जांच करने से यह पता चला है कि इसमें पांच दोष थे : सेना के दिन-प्रतिदिन के कार्य में मंत्रालय का हस्तक्षेप, दलबंदी, पक्षपात आदि से सेना के हौसले को कम करना, प्रतिरक्षा सम्बन्धी हर बात को गुप्त रखना, प्रतिरक्षा की दीर्घकालीन योजनाओं का अभाव और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को राजनैतिक प्रवृत्तियों के अधीन रखना।

मैं इन पिछली बातों पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, किन्तु यदि हम इन पर विचार न करें तो भविष्य में भी संतोषजनक कार्य नहीं कर सकते। इसलिये यह आवश्यक है कि हम पिछली ग़लतियों से शिक्षा ग्रहण करें।

नये प्रतिरक्षा मंत्री ने पांच में से कम से कम दो बुराइयों को, मंत्रालय के हस्तक्षेप और पक्षपात आदि को दूर कर दिया है। अब सक्षम, ईमानदार, सत्यनिष्ट कर्मचारियों को यह भय नहीं कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय किया जायेगा। बहुत धैर्य और कौशल के साथ श्री चह्वाण ने सेना के गिरे हुये हौसले को उठाने का प्रयास किया है।

सेना में हौसला बना रहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब तक यह बना रहता है तब तक यह सेना अजेय है। यदि यह न रहे तो किसी भी प्रकार के सशक्त हथियार सेना की शक्ति को क्षीण होने से नहीं रोक सकते। जिन्होंने सेना का हौसला गिराने की कोशिश की है उन्होंने देश के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे आशा है कि श्री चह्वाण शेष तीन बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे।

पहली ही बात लीजिये। हर बात पर यह कह दिया जाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में इसे नहीं बताया जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि सरकार अपनी प्रतिरक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में शत्रु को भुलावे में नहीं रख सकी, केवल देश को ही गुमराह किया है। अपनी कमजोरियों को छिपाये रखा है। कई बार सभा में साधारण बातें पूछी गईं किन्तु उन्हें भी 'सुरक्षा के हित में नहीं हैं।' कह कर टाल दिया गया। प्रधान मंत्री ने यह भी बताया कि ब्रिटिश शासन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है। किन्तु यह कितने शर्म की बात है। उस समय इन बातों को इसलिये नहीं बताया जाता था कि यदि यहां के लोगों को यह पता लग गया कि देश की रक्षा किस प्रकार की जा रही है तो हमें यह भी पता लग जायेगा कि उन लोगों को यहां से कैसे हटाया जा सकता है। किन्तु अब वह बात नहीं है। ब्रिटेन में क्या प्रथा है ?

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये] ।

वहां के नवीनतम प्रतिवेदन को देखन से प्रतीत होता है कि उसमें प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी जानकारी दी हुई है।

ब्रिटेन अपनी सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बारे में पूरी पूरी जानकारी देता है तथा एक सामान्य व्यक्ति भी यह जान सकता है कि वे किस प्रकार के हथियारों का उपयोग कर रहे हैं।

अब मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन लेता हूं इसमें जो कुछ लिखा गया है वह इतना अस्पष्ट है तथा हास्यास्पद है कि न तो इससे हमारी जानकारी बढ़ती है और न ही कुछ सूचना ही प्राप्त होती है यह सब देश की सुरक्षा के हित में किया जाता है। मेरे विचार से इस प्रकार के प्रतिवेदन से केवल जनता के धन का अपव्यय ही होता है।

---

†मूल अंग्रजी में

मेरे विचार से विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां के लोग, तथा जहां के सदस्य इस प्रकार अनजान रखे जाते हैं ।

आंभिक सर्वेक्षण के समान प्रतिरक्षा के बारे में अधिक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिये और सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

दुःख का विषय यह है कि हमारी कोई सामरिक नीति नहीं है । जनता का प्रतिरक्षा मंत्री श्री चह्वाण पर बहुत विश्वास था किन्तु उन्हें भी पाबन्दियां लगा कर निरुपाय कर दिया गया है ।

इससे पहिले प्रतिरक्षा का कार्य वैदेशिक कार्य विभाग के अधीन रखा जाता था । अब समय आ गया है जब हमें देखना है कि विकास, वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा में एकता व समानता होनी चाहिये । मैं तो यहां तक कहूंगा कि आवश्यकता होने पर विकास और वैदेशिक कार्य प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के अधीन होने चाहियें ।

आज हमारी जो करारी हार हुई है उसका कारण यही है कि न हमारी सेना के पास कपड़े थे, न जूते, न वर्दी और न साज सामान । दुःख का विषय यह है कि श्री कृष्ण मेनन, भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री, ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में यह कहा था कि हमें चीन से कोई खतरा नहीं है वह शांतिप्रिय देश है, तथा चीन के हमला करने पर हम कभी आपसे सहायता की याचना नहीं करेंगे । यह बात श्री कृष्ण मेनन ने १९५८ में कही थी जब कि चीन ने बड़ाहोती पर १९५४ में आक्रमण कर दिया था ।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हू कि अधिकारियों की कमी पूरी करने के लिये सेना के पद-निवृत्त अधिकारी २ या ३ वर्ष की सीमित अवधि के लिये बुला लिये जायें ।

हमारे सैनिकों को जो पेंशन दी जाती है वह बहुत कम है । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक जमेदार का लड़का हमारे साथ कैद में था उसे क्षय हो गया । उसका कोई ऐसा रिश्तेदार न था जो उसकी सहायता करता, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । कुछ दिनों पश्चात् हमारे बाप ने कहा :

> "हम जानते नहीं कि हम क्या करेंगे । लोग सलाह देते हैं कि हम पाकिस्तान चले जायें ।"—मुसलमान था वह बेचारा—"लेकिन कैसे जायें ? हम यहां पैदा हुए । यही हमारा वतन और देश है । मगर साहब, कुछ जमता नहीं है अभी ।"

मैंने उसे एक कप चाय पिलायी, उसकी आंखों में आंसू आ गये वह बोला :

> "बहुत दिनों के बाद ऐसी चाय हमें मिल रही है । हम चोरी नहीं कर सकते । हम व्यापार नहीं कर सकते । हमें तो इस का ज्ञान नहीं था । हम ने तो सिर्फ नौकरी करना जाना है । अब हमारी यह हालत बन गई हैं ।"

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम न केवल देश को बचाने में समर्थ हों बल्कि इतने शक्तिशाली हों कि कोई हमारी ओर आंख उठा कर देखने का भी साहस न कर सके ।

†**श्री बासप्पा** (तिलचुर) : सभा में जो भाषण दिये जा रहे हैं उनसे हम शत्रुओं की अधिक सहायता करते प्रतीत होते हैं । हमें इस सम्बन्ध में अधिक सक्रिय रुख अपनाना चाहिये क्योंकि चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बास्पा]

इस सम्बन्ध में यह प्रसन्नता की बात है कि प्रतिरक्षा मंत्री सेना की संख्या दुगनी करने जा रहे हैं ।

मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा के लिये न हमें सेना को ही सुदृढ़ बनाना है । अपितु आन्तरिक प्रशासन, कूट नीति, गुप्तचर विभाग सभी का पुनर्गठन करना है ।

यद्यपि हमारे सर पर खतरा खड़ा है तथापि फिर भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि, आपात काल समाप्त कर दिया जाये ।

कमीशन की परीक्षाओं में ८० प्रतिशत व्यक्ति केवल इस कारण फेल होते रहैं कि वे अंग्रेजी में कमजोर हैं । अतः हमें परीक्षा प्रणाली में ही परिवर्तन करना चाहिये ।

भर्ती के मामले में भी बहुत भेदभाव की बातें सुनने में आई हैं । इस मामले की भी सावधानी से जांच होनी चाहिए । इस मामले में किसी प्रकार का लिहाज नहीं होना चाहिए । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक हवाई अड्डों की भी बड़ी आवश्यकता है । प्रतिरक्षा विषयक उत्पादन के बारे में इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि माल बढ़िया कोटि का बनाया जाय । रखा परीक्षण प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है इस पर गौर नहीं किया जा सकता । ट्रकों के निर्माण की बात खेद जनक है, इस से तो विदेशी विनिमय को भी कोई लाभ नहीं हुआ ।

'नेफा' की पीछे हटने की गड़बड़ी की जांच करने वाली समिति के निदेश निबंधों का आधार विस्तृत होने चाहिए और जो लोग अपराधी सिद्ध हों, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । यहां तो हर बात गोपनीय रखने का यत्न किया जा रहा है, परन्तु वहां सब भेद निकल जाते हैं । इस बात का पूरा नियंत्रण देश को सैनिक दृष्टि से तैयार करने और समाजवाद में कोई विशेष विरोध की बात नहीं है । तटस्थता की नीति को वाम और दक्षिण पक्ष के लोग काफी भ्रांति में डाल रहे हैं । लोगों को सेचेत रहना चाहिये । हमें यह बात याद रखना चाहिए कि केवल सैनिक शक्ति ही कि राष्ट्र की शक्ति नहीं होती । राष्ट्र का चरित्र भी एक बहुत बड़ी शक्ति है । आज शांतिदूत जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का युद्ध कालीन नेतृत्व सम्भाले हैं, हमें उस पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना चाहिए । अन्तिम निर्णय उनका ही होना चाहिए । इस तरह ही वह देश को चीनी आक्रमण से मुक्त कर सकेंगे ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा** (खम्मम) : केवल भाषणों से ही कुछ बनने वाला नहीं । खेद की बात है कि विरोधी दलों ने देश में एक पराजित और निराशमय स्थिति का निर्माण कर दिया है । परन्तु मुझे इस बात पर हर्ष तथा सन्तोष हैं कि हमारी तटस्थता की नीति तथा अन्य नीतियां सफल रही हैं । यह संतोष का विषय है कि सरकार देश की प्रतिरक्षा शक्त को मजबूत करने के लिए सब प्रकार की कार्यवाही कर रही है । हमारा प्रतिरक्षा उत्पादन भी युद्धकालीन गति से बढ़ाया जा रहा है । हम आधुनिक स्वचालित तथा विभिन्न प्रकार के अपेक्षित अस्त्र शस्त्रों का भी काफी मात्रा में निर्माण कर रहे हैं । हमारे यहां जो भी कार्य हुआ है विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने भी उसकी प्रशंसा की है । सब ने ही यह महसूस किया है कि हमें विभिन्न राष्ट्रों से जो सहायता मिल रही है हम उसका उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

हमें कुछ राष्ट्रों ने इस कठिनाई के समय में सहायता दी है। परन्तु इस बात का संतोष है कि उन में से किसी ने भी हमें अपनी नीति छोड़ने को नहीं कहा है । हम इन राष्ट्रों के कृतज्ञ हैं। हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के फलस्वरूप हम दोनों गुटों की सहायता प्राप्त कर सके हैं। यह हमारी नीति की सफलता का चिह्न है। कुछ माननीय सदस्यों ने जो इस बात पर बल दिया है कि हमें इस नीति को छोड़ पश्चिमी गुट में शामिल हो जाना चाहिए ठीक नहीं कही जा सकती ।

यह सन्तोष का विषय है कि आज देश जाग उठा है और जवानों की सहायता तथा देश की प्रतिरक्षा के लिए लोग सभी भार सहन करने को तैयार हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिये यह जरूरी है कि शक्ति असैनिक प्राधिकार के पास ही हो । यह ठीक है कि हमें साम्राज्यवादी काल की परम्पराओं में तबदीली लानी है, परन्तु मेरा निवेदन है कि इस मामले पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये ।

प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि सैनिकवाद किसी खास जाति विशेष की बपौती नहीं है । इसी तरह यह किसी एक सेक्स की भी नहीं है। हमारे देश में तो सैनिक क्षेत्र में भी औरतों ने बहुत बीरता के कारनामें किये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि महिलाओं को सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। हमें देश की प्रतिरक्षा के साथ साथ अपने लोकतंत्रीय आदर्शों की भी रक्षा करनी है। इस आदर्श के नाते ही संसार के सभी लोकतंत्रीय राष्ट्र हमारी स्वतंत्रता में रुचि प्रकट करेंगे और समय आने पर हमारी सहायता करेंगे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर): मैं पुरानी भूलों को दोहराना नहीं चाहता । देश के हित की दृष्टि से उस से कोई लाभ होने वाला नहीं । हमें अब शब्दों और भाषणों की आवश्यकता नहीं और न ही प्रदर्शनों की आवश्यकता है। हम तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सेना के लिए ३५० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी है । इस में कोई सन्देह नहीं कि हमें बड़ी मजबूत सेना की आवश्यकता है परन्तु हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि शत्रु को जीतने के लिए स्थल सेना, समुद्री सेना, और वायु सेना इन तीनों की आवश्यकता है । समुद्री सेना के लिए केवल २० करोड़ रखे गये हैं। वायु सेना के लिए ८७ करोड़ रुपये निर्धारित हुए हैं। इतना भारी अन्तर क्यों रखा गया है ? इसका मुझे तो कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि यदि हम तैयार हो चुके हैं तो हमें भी आक्रांता पर आक्रमण करने की सोचनी चाहिये । यही समय है कि जब कि हमारी सरकार को यह सोचना है कि हम अपने शत्रुओं को अपने देश से निकालने के लिये क्या कार्यवाही कर सकते हैं ? अब जो स्थिति चल रही है उसे अनिश्चित काल तक चलने देना बुद्धिमता नहीं कही जा सकती। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हम यह प्रतीक्षा क्यों करते रहे कि जब शत्रु हमारे ऊपर हमला करेगा तब हम कोई कार्यवाही करेंगे । हमला होगा तब ही हम अपना बचाव मात्र करेंगे, यह खेल अब समाप्त हो जाना चाहिये । हमारा देश और राष्ट्र बड़ा महान है। हमें आगे बढ़ कर और शत्रु के पास पहुंच कर उस से लड़ना चाहिये । हमें मामले पर गम्भीरता से विचार करना है । चीन की युद्ध विराम की घोषणा का वास्तविक उद्देश्य समझने का प्रयत्न करना है। क्योंकि हम आगे ही अठाहार हजार वर्गमील क्षेत्र प्रतीक्षा करते करते ही खो बैठे हैं। देखा जाय तो यह हमारे लिए लज्जा की बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवदी]

मेरा निवेदन है कि सरकार को एक ठोस और सबल नीति अपनानी चाहिये। देश की जनता इस मामले में पूर्ण रूप से सरकार के साथ है और सब प्रकार की सहायता और सहयोग सरकार को देने के लिये तत्पर है। इस पर भी यह खेद की बात हैं कि सरकार देश में पंचगामियों को रोक नहीं सकी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पंचगामियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार को बड़ा कड़ा कार्यवाही करनी चाहिए।

देश की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व आपके हाथ में है। हम आपकी नितियों में दोष नहीं निकालना चाहते परन्तु देश के हित में जो हमारा कर्त्तव्य है उस दृष्टि से जो कुछ कहना चाहिये वह कहने का अवश्य प्रयत्न करते हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में बड़ी स्पष्ट बात कही गयी है कि व्यय के लिए इतनी राशि चाहिये। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन बहुत ही भद्दा चित्र प्रस्तुत करता है। हम तो बार बार कहते रहे हैं कि हमने जो कुछ भूलें की हैं वह आंखें खोल कर की हैं। खेद है कि अब भी हम अपनी पुरानी नीति में सुधार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्रालय के अधीन विविध विभागों में, विशेषकर कैंटीन स्टोर विभाग में, भ्रष्टाचार को सख्ती के साथ समाप्त करना चाहिये। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे लोगों का चरित्र ऊंचा उठे, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, हमारी सेनाएं सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। मैं आशा करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री सभय की मांग को पूरा करेगा और उन समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से हल करेगा।

हमें एक बात याद रखनी चाहिये कि देश की प्रतिरक्षा का प्रश्न एक दल का प्रश्न नहीं है। यह तो सारे राष्ट्र का प्रश्न है अतः इसका निर्णय दल को नहीं संसद् को करना चाहिये। आज की स्थिति में संसद् इस मामले में आप पर पूर्ण विश्वास प्रकट कर चुकी है। अब हमें दोषों की ओर कोई ध्यान नहीं देना है। देश की इस समय सामुहिक इच्छा यही है कि हमारी सरकार को आगे बढ़ना चाहिये और शत्रु को देश से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त करनी चाहिये।

†**श्री वीरभद्र सिंह** (महासू) : प्रतिरक्षा मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। परन्तु आज की आपातकालीन स्थिति में इस का महत्व और अधिक हो गया है। गत अक्तूबर में हमें कुछ पराजित भी होना पड़ा था क्योंकि हम पर एकदम चीन ने हमला कर दिया था। इस का यह मतलब नहीं था कि हम में शक्ति अथवा क्षमता की कोई कमी थी अथवा हमारे सैनिकों में वीरता की भावना कम थी। मुझे इस बात का हर्ष है कि अब उचित दिशा की ओर हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रतिरक्षा मंत्रालय अपनी सेनाओं को आधुनिक ढंग का प्रशिक्षण देने लगा है। विभिन्न प्रकार की सेनाओं को सबल बनाने के लिये समुचित कार्यवाही की जा रही है। सारा देश आज महसूस कर रहा है कि हम आज शत्रु का मुकाबला करने के लिये काफी अधिक मजबूत हो गये हैं। हम इतने मजबूत हो गये हैं कि जितने पहले कभी नहीं थे।

हमें बड़ी विकट स्थिति का सामना करना है। अतः इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का अपना गुप्तचर विभाग होना चाहिये। यह ठीक है कि सेना के प्रधान कार्यालय में सैनिक गुप्तचर की व्यवस्था है किन्तु उस के पास अपना कोई व्यापक संगठन नहीं है। उन्हें अधिकतर गुप्तचर सेवा ब्यूरो पर निर्भर करना पड़ता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार कर के कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी विभिन्न सेनाओं में नितान्त अभाव है। सशस्त्र सेनाओं के तीनों कक्षों के बीच अधिक से अधिक समन्वय होना चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्रालय इस महत्वपूर्ण कार्य को तभी कर सकता है जब उस के पास स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना इन तीनों सेनाओं के विषयों को समझने वाले तथा निपटारा करने वाले अधिकारी हों। इस प्रकार के अधिकारियों की सेवा प्राप्त की जानी चाहियें। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सेना अध्यक्षों की समिति के कार्य की अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें और प्रतिरक्षा मंत्री का इस समिति के साथ सक्रिय सम्बन्ध होना चाहिये।

हमें अपनी सेनाओं को पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रुओं की शस्त्रास्त्र सम्बन्धी तैयारी के मुकाबले में पूर्णतया सज्जित करना चाहिये। सरकार को अपनी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक ढंग का बनाने तथा सबल करने के लिये तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये और उस को आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सज्जित करना चाहिये। हमें मित्र राष्ट्रों से सैनिक सहायता लेने में नहीं झिझकना चाहिये।

हमें वायु बल को समृद्ध करने के लिये आधुनिकतम किस्म के विमान प्राप्त करने चाहियें, तथा सरकार को यह भी प्रबन्ध करना चाहिये कि देश में आधुनिकतम किस्म के विमानों का ही निर्माण किया जाय।

सरकार को स्थानीय पर्वतीय लोगों के 'यूनिटों' की संख्या और शक्ति बढ़ा देनी चाहिये, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में ऐसे और अधिक 'यूनिट' बनाये जाने चाहियें। सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषत: हिमाचल प्रदेश, के लोगों में सन्तोष और विश्वास का वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता हैं। सरकार को उन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक पग उठाने चाहियें।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें अपने नये प्रतिरक्षा मंत्री पर बहुत आशायें हैं। उन में योग्यता और क्षमता तो है ही, सारे देश का विश्वास भी उन्हें प्राप्त है। उन के नेतृत्व में हमारी सेनाओं की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायेगी और वह हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए एक प्रबल प्रहरी का रूप धारण कर लेगी।

†**श्री सुरेंद्र पाल सिंह** (बुलन्द शहर): मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सशस्त्र सेनाओं की संख्या बढ़ाने का जो निर्णय सरकार ने किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं। यह ठीक दिशा की ओर उठाया गया एक कदम है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो अधिकारी प्रतिरक्षा मंत्रालय में कार्य करते हैं उन की अधिकतम आयु ३५ वर्ष है। कहा जा रहा है है कि अब उसे कम कर के ३० किया जा रहा है। मेरे ख्याल में यह भी ठीक नहीं। इसे ३० से घटा कर २५ किया जाना चाहिये। यह सन्तोष का विषय है कि गत कुछ महीनों में हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रयोजन के लिये सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का पूर्ण उपयोग करना चाहिये। सरकार को यह बताना चाहिये कि प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में असैनिक क्षेत्र के उद्योगों ने कितना योग दिया है। क्या यह उन की उत्पादन क्षमता के अनुरूप था? यदि नहीं, तो क्या उन उद्योगों पर कुछ सीमा तक दबाव डालना अनुचित होगा?

इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी "ऑर्डीनेन्स फैक्ट्रीज" में उत्पादन बढ़ाना चाहिये। और जिन चीजों का उत्पादन अति आवश्यक है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेंद्र पाल सिंह]

मेरा मत तो यह है कि इस समय सब से अधिक ध्यान उन अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में लगाया जाना चाहिए जिन की हमारे जवानों को सब से अधिक आवश्यकता है। हमारा ध्यान केवल उस पर ही सब से अधिक केन्द्रित होना चाहिये। भारी टैंक बनाने के बारे में बात हुई है, मेरा विचार है कि सरकार को भारी टैंक बनाने के पूर्व हल्के टैंक बनाने के मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यदि सम्भव हो तो आपातकालीन स्थिति में हमें वायुयान-रोधी तोपों के स्थान पर प्रेक्षेपणास्त्र के निर्माण का प्रयत्न किया जाना चाहिये। परन्तु जब तक यहां निर्माण की व्यवस्था न हो उन का आयात जारी रहना चाहिये।

वायु सेना के लिए इस समय सब से अधिक आवश्यकता "सुपरसोनिक" वायुयानों की है। अतः इन के निर्माण की ओर सब से अधिक ध्यान देना चाहिये। इस के अतिरिक्त मैं जल सेना के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारी जल सेना में अधिकांश जहाज पुराने ही थे। इस बात की आवश्यकता है कि इन के स्थान पर नये जहाज लाने की व्यवस्था करनी चाहिये। जब हम इस स्थिति में हैं कि नौ सेना के विस्तार के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था कर सकते हैं तो हमें पन डुब्बियों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अन्त में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। जो लोग देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उन के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था होनी ही चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): सब से पहले मुझे उन जवानों को श्रद्धांजली अर्पित करनी है जिन्हों ने देश के लिए जीवन का बलिदान दे दिया। हथियारों का उत्पादन १९५६ से बढ़ रहा है और आपातकाल म काफी बढ़ा है। इस के लिए कारखानों के मजदूर और अधिकारियों ने दिन रात काम किया है। हमें उन के प्रयास की सराहना करनी वाहिये।

हथियार बनाने के कारखाने के कर्मचारियों के काम के सम्बन्ध में सन्देह करना सर्वथा अनुचित है। उन का नाम आपाताकाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उन्हों ने बहुत कुर्बानी की है।

नेफा में हमारी सैनिक असफलताओं की जांच से पता चलेगा कि वहां हमें एक जनरल की गलतियों के कारण असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस जनरल को सरकार ने वैसे ही छोड़ दिया। लद्दाख में भी काफी सेना थी जिस ने चीनियों का डट कर मुकाबला किया। व्यापक जांच होनी चाहिये।

माननीय सदस्यों ने मांग की है कि प्रतिरक्षा उत्पादन और उद्योग की जांच होनी चाहिये। मेरे विचार में यह जांच १९५२ से १९६२ तक के समय के लिए होनी चाहिये। इस अवधि में कई प्रशिक्षित कर्मचारियों को हमारा विरोध करने पर भी हटा दिया गया।

प्रतिरक्षा उत्पादन के विभिन्न कारखाने प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियन्त्रक के अधीन होने चाहियें। इन में समन्वय होना चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय इस बात पर विचार करे कि बात-चीत द्वारा झगड़ों को निपटाने की व्यवस्था पुनः आरम्भ कर देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६० की हड़ताल के कारण जिन लोगों को निकाल दिया गया था और जिन्हों ने अब सरकार का पूरा समर्थन करने का आश्वासन दिया है उन्हें वापिस नौकरी में ले लेना चाहिये।

डी० एम० आर० एस० संगठन को ईसापुर से हैदराबाद ले जाने से पूर्व उचित जांच की जानी चाहिये ।

विशेष मिश्रधातु का संयन्त्र कानपुर में स्थापित किया जाना चाहिए। वहां चार हथियार बनाने के कारखाने हैं। इस प्रकार सब चीजों के बनाने के लिए कानपुर एक पूरा एकक बन सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री इकबाल सिंह** (फीरोजपुर) : नेफा और लद्दाख में हमारी सेना ने जो अच्छा काम किया उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। हम संभल गये हैं।

हमें आधुनिकतम किस्म के हथियारों का प्रयोग करना चाहिये। हमें द्वितीय युद्ध के के बातावरण में नहीं सोचना चाहिए। हमें आधुनिकतम स्वयंचालित हथियारों को बनाना चाहिये। या प्राप्त करना चाहिए ।

हमें चीन और पाकिस्तान को ठीक प्रकार से समझना चाहिये। वे दोनों मिल कर भारत के लिए जाल बिछा रहे हैं। हमें उस जाल में नहीं फंसना है। पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, परन्तु उन के वर्तमान नेताओं पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के साथ युद्ध नीति और हथियारों आदि के प्रयोग की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारे जवानों के पास हल्के हथियार होने चाहिये ताकि वे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें।

जवान हमारी सेना की जान हैं। उन की सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। युद्ध में उन की हालत में सुधार होना चाहिए। उन को अच्छा वेतन मिलना चाहिए। वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलनी चाहिए :

कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों की सेवा शर्तें भी ठीक नहीं हैं। अब सेना का जो विस्तार हो रहा है उस में ५० प्रतिशत अधिकारी कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों में से लिये जाने चाहिएं।

सेना के सभी वर्गों को एक ही प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिएं। सेना में एकता कायम रखनी चाहिये ।

हमारी सेना के नेता बहादुर और बहुत उत्साह वाले होने चाहिएं । तभी विजय होगी।

पंजाब सरकार ने जवानों के लिए काफी सुविधाएं दी हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

अन्य राज्यों को भी पंजाब का अनुसरण करना चाहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भूमि दे कर सहयोग दिया है। सैनिकों के लिए प्रत्येक राज्य को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इकबाल सिंह]

६ कारखाने स्थापित किए जाएंगे। उन में से कम से कम एक कारखाना पंजाब में स्थापित किया जाना चाहिए।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरघना) : युद्ध में हौंसले की और बहादुरी की आवश्यकता है। दूसरे एक लड़ाई में हार जीत युद्ध के निष्कर्ष या निर्णय नहीं करती। स्वीडन और परुशिया ने युद्ध में अपनी सेना छः गुनी कर ली थी। इस तरह से लोगों ने संकट में अपने देश की सहायता की।

यदि हमें चीन के साथ युद्ध करना पड़ा तो चीनियों का मुकाबला बहुत से लोगों को करना पड़ेगा।

हमें दो बातें याद रखनी हैं। पहले, वर्तमान युद्ध इतिहास की संकट कालीन स्थिति है। दूसरे चीन अतिक्रमण की नीति में विश्वास रखता है। अपने सैनिकों को भी यही पढ़ाते हैं कि भारत के सीमान्त क्षेत्र का भाग चीन का हिस्सा है, उन्हें लेना चाहिए।

भारत और चीन दोनों देश आर्थिक तौर पर विकसित नहीं हैं। अतः उन दोनों में लम्बा युद्ध होना असम्भव है।

नेफा में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिये। पहाड़ों में युद्ध कठिन होता है।

जनरल में साहस बहुत प्रशंसनीय योग्यता है।

देश की आर्थिक स्थिति का सुधार किया जाना चाहिये। देश की शक्ति को बढ़ाया जाए और लोगों का नैतिक साहस कायम रखा जाए।

†**डा० म० श्री अणे** (नागपुर) : सरकार ने भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री को बदल कर जनता की भावनाओं का आदर किया। आशा है कि नए प्रतिरक्षा मंत्री प्रतिरक्षा मंत्रालय में नई जान पैदा करेंगे और देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाएंगे ताकि हम चीनियों को खदेड़ बाहर करें।

चीन की सेना बहुत अधिक है। उस का मुकाबला करने के लिए हमें थोड़े से समय में अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहिए। इस प्रकार से चीनियों को बाहर निकाल दिया जाएगा।

हमें प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दो नीतियां अपनानी चाहियें—एक थोड़े समय के लिए और एक लम्बे समय के लिए। हमें कुछ मित्र देशों से भी सहायता लेने के लिए उन्हें पहले कह देना चाहिए। प्रतिरक्षा मंत्रालय को यह बात सामने रखनी चाहिए कि चीन शीघ्र पुनः आक्रमण करता है तो हमारी इतनी शक्ति हो कि उस के लिए हमारी भूमि में आगे बढ़ना कठिन हो जाए। यदि ऐसी तैयारी हो तो आशा है कि सारा देश प्रतिरक्षा मंत्रालय का समर्थन करेगा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में परिवर्तन और इस वर्ष के बजट से स्पष्ट है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक है :

हम जितना धन प्रतिरक्षा पर व्यय कर रहे हैं उस से कहीं अधिक हमें करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें दूसरे देशों से सहायता लेने में शर्माना नहीं चाहिए। इग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों को भी सहायता लेनी पड़ी थी। इस से देश के क्षेत्र और सम्मान की रक्षा होगी।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने डिफेंस की डिमांड्ज़ पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, मैं नेपाल के बार्डर से आता हूं। मैं सब से पहले अपने नये डिफेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जितनी बातें आज इस हाउस में बताई गई हैं, उन पर आप कृपा करके अमल करेंगे। मैं निराशावादियों में से नहीं हूं। मैं आशावादी हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम उनकी सन्तान हैं जो राणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के मैदान में घास की रोटियां खा खा कर अकबर के मुकाबले में लड़े थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं :

चार बांस चौबीस गज़ अंगुल अष्ट प्रमाण।
ता ऊपर सुल्तान है मत चुक्के चौहान॥

आज श्री चह्वाण से मेरी प्रार्थना है कि यह जो अपोजीशन यहां बैठा हुआ था वह सिफर हो गया, वे सब लोग बातें कर के चले गये। वे निराशावाद की बात करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन मैं आप को सचेत करना चाहता हूं, कि आप सर्वगुण सम्पन्न हैं, बम्बई छोड़ कर आप आये हैं। प्रतिरक्षा हिन्दुस्तान के सब से अच्छे मन्त्रियों में से एक के हाथ में है। अब हम चीन और पाकिस्तान आदि को देख लेंगे। अकेला पंजाब हमारा काफी है जो कि पाकिस्तान को देख सकता है। काश्मीर हमारा बहादुर है, काश्मीर के हमारे चीफ मिनिस्टर कमजोर नहीं हैं। मैं नेपाल बार्डर पर रहता हूं। मैं अपने डिफेन्स मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हमारा बच्चा बच्चा आप के कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ने के लिये तैयार है। लेकिन इस बार्डर को आप देखिये। अगर दो हजार आदमी इस बार्डर की रक्षा नहीं कर सकते तो दस हजार का इन्तजाम किया जाये। ट्रेनिंग दी जाय, सड़कें ठीक की जायें, मीन्स आफ कम्यूनिकेशन ठीक किये जायें।

आपत काल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी"

हम लोग धीरजवाले हैं, धैर्य के साथ आप के साथ हैं और देश के साथ हैं। आप में देश का विश्वास है, पंडित नेहरू में देश का विश्वास है। सारी कौम उनके पीछे है। हाल में पंडित जी बम्बई गये थे, वहां इसका नमूना हमने देखा। यहां पर अपोजीशन वाले इतना उत्पात मचाते हैं लेकिन बम्बई में हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत जबर्दस्त रिसेप्शन हुआ, जो कि इस बात का सबूत है कि हमारे साथ कौन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि हमने गलती की, उन्होंने गलती को तसलीम किया, लेकिन धोखा नहीं दिया। सही बात कही। अगर गलत बात कोई इंग्लैंड में कहे, गलत बात कोई अमेरिका में कहे तो इसका क्या जवाब है। जो लूज टाक करते हैं उनको करने दीजिये। हाथी अपनी चाल जाते हैं और कुत्ते पों पों करते रहते हैं अगल बगल। आज हमारे पास एक गम्भीर डिफेन्स मिनिस्टर है, मैं ऐश्योरेन्स देता हूं कि हमारा मुल्क आगे है, पीछे नहीं है। हमने बड़े बड़े रिवर्सेज देखे हैं। माननीय सदस्य ने पानीपत की बात कही, पलासी की बात कही, हमने उन दोनों को देखा। मीर जाफर और मीर कासिम देश में मौजूद हैं। मैं अपने मिनिस्टर से अपील करता हूं कि देश भर में फिफ्थ कालम के लोग घूम रहे हैं, वे उनको पनपने न दें, आज इस बात की आवश्यकता है।

जिस दिन हमारे डिफेन्स मिनिस्टर ने चार्ज लिया, दिल्ली के उस मैदान में मैं मौजूद था जब जनता ने ५१ हजार रु० की थैली दी और सोने की तलवार दी और यह बतलाया

[श्री शिव नारायण]

कि उनमें दिल्ली शहर की जनता का विश्वास है। जब वहां पर मिनिस्टर साहब की स्पीच हुई तो दिल्ली शहर की जनता ने हर महीने ५१ हजार रु० देने की बात कही। आज हमारे डिफेन्स मिनिस्टर के पीछे सारी कौम है। हम बहादुर हैं, कमजोर नहीं हैं। मैं हरिजन हूं, आप हरिजन फंड में जो भी देते हैं वह सब मैं डिफेन्स फंड में दे दूंगा। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। देश सुखी रहेगा तो हम भी बाद में सुखी हो सकते हैं। मैं निराशावादी नहीं हूं, आशावादी हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे किस्म की ट्रेनिंग दें, नये आफिसर्स को ट्रेन करें। हर एक ने नेफा में जो कुछ हुआ उसकी निन्दा की, लेकिन लद्दाख को वे भूल गये। हमारे श्री डी० सी० शर्मा ने कहा था कि लद्दाख में हमारे जवानों ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिये थे। जो भी हमारे जवान नेफा में मारे गये, उनमें से एक एक ने तीस तीस चीनियों को मारा, मगर उनके छुरा सामने लगा, पीठ के पीछे नहीं लगा; यह भारतीय कैरेक्टर है। हमारे देश का मोराल आज भी ऊंचा है, कल भी ऊंचा रहेगा और भूतकाल में भी ऊंचा रहा है। हिन्दुस्तान आगे है, वह कमजोर नहीं है।

जो हमारी नानअलाइनमेंट की पालिसी है वह गलत नहीं है। भगवान बुद्ध ने हमें सत्य और अहिंसा की चीज दी थी? गांधी जी ने भी दी। जवाहरलाल जी उस पर अमल कर रहे हैं। हम उनके पीछे चल रहे हैं और कौम उनके पीछे खड़ी है। हमारे दुश्मन ने जो हम पर हमला किया है उसके लिये जो कुछ यहां कहा गया वह ठीक है। उसने मित्र बन कर हमारे छरा मारा है, मित्र ने हम पर हमला किया है यह नया शिगूफा दुनिया में आया। जब यह नया ढंग आया है तो दुनियां में कौन चीन का विश्वास करेगा? नेपोलियन को भी हमने पढ़ा है, हिटलर को भी पढ़ा है, लेकिन उस वक्त ऐसा नक्शा नहीं था जैसा कि चीन ने आज दुनिया के सामने रक्खा है। यदि कोई नई चीज एक व एक आ जाय, पंचशील पर दस्तखत करके यहां से चीन चला जाय और फिर उससे उलटा करने लगे तो क्या किया जाय?

"विश्वासं फलंदायंक"

विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। आज हम लोग आपके साथ हैं और कल आप की पीठ में छुरा भोंक दें तो इसमें आपका क्या दोष है? नेहरू जी का इसमें क्या दोष है, भारत का क्या दोष है?

भारत की मिलिटरी बहुत अच्छी है, हमारे पास जो आफिसर हैं वे बहुत सुयोग्य हैं, यह गलत नहीं है। यह बात हमको इस समय मालूम हुई है। लेकिन इससे भी सुपीरियर पावर हमारे और आपके ऊपर है। सब कुछ भगवान की माया से होता है। जो भगवान है उसका भेद हम नहीं पा सकते। विलियम कैसर ने अमरीका से क्या कहा था जब वह ५२ राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था? लेकिन जब अमरीका के जहाज को इंग्लिश चैनेल में डुबाया गया तो उसने कहा कि अगर आखिरी जहाज डुबाया गया तो अमरीका वार डिक्लेअर कर देगा और विलियम कैसर ने उस का जवाब दे दिया। उसने कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूं, खुदा मियां आ जायेंगे तो भी तैयार हूं। लेकिन वह विलियम कसर मिटा, नेपोलियन मिटा, हिटलर मिटा। हम वह गलती नहीं करना चाहते हैं। हमें धीरे-धीरे आज हमारे नेता ले चल रहे हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। हमने हमला नहीं किया, लेकिन आगे के लिये हमको अपनी शक्ति पूरी करनी है।

हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों ने जो कुछ कहा है मैं अपील करूंगा कि वे उस पर अमल भी करें। उन्होंने बहुत सुन्दर उपदेश दिया है लेकिन अगर सारे कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग उस पर अमल करें तो हम समझेंगे कि वे देश के शुभचिन्तक हैं। प्रोफेसर रंगा यहां नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको निराशावाद की बात नहीं करनी चाहिये। वह भावी मिनिस्ट्री में आने के चक्कर में हैं, लेकिन मैं उनको बतलाऊंगा कि वे यहां ऐसी चीजें न कहें जिससे दूसरे दिन आने वाले लोग वहां पर उनकी नुक्ताचीनी करें।

मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे जवानों और आफिसर्स की जो विधवायें हैं उनके लिये आप पांच साल वाली या चार साल वाली पेंशनें न दें, उनके लिए आजीवन प्रबन्ध करने की आवश्यकता है जिसमें हमारे जवान यह समझ लें कि अगर वे रण में मारे जायेंगे तो उनके बच्चों की रक्षा होगी।

हमारे पूर्व एअर मार्शल साहब की श्रीमती जी यहां नहीं हैं। उन्होंने कल जो कुछ कहा उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम को ऐसी बात कहनी चाहिये जिससे देश का भला हो। देश का कल्याण हो और जो देश आगे बढ़ रहा है वह कमजोर न हो जाय।

यहां पर हर एक किसान काम कर रहा है, हर एक मजदूर काम कर रहे जो कि फैक्ट्रियों में हैं। लेकिन उनके ऊपर थोड़ी चेकिंग की जरूरत है। आपका जो मिलिटरी इंटलिजेंस डिपार्टमेंट है उसको होम डिपार्टमेंट की इंटलिजेंस से थोड़ा दूर रहना चाहिये। आज सारे देश को आगे बढ़ना है। आज जो नौजवान हैं वह हमारी रक्षा कर रहे हैं लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको उन नौजवानों के सिर पर हाथ रखना पड़ेगा। आपके यहां इंसाफ की तराजू होनी चाहिये। मिलिटरी में आज भी तीन किस्म के मेसेज हैं। आज आई एन ए की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, सुभाष चन्द्र बोस की मिसाल आपके सामने है। उनसे आपको सबक लेना है। आज देश को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है।

आज मिलिटरी आफिसर्स जो हैं हमारे उन लोगों में से कुछ ने कहा कि हम पाकिस्तान के अनुग्रहीत हैं कि वह हम से छुट पुट लड़ाई करता रहा, झगड़े करता रहा जिसके कारण हमने अपने जवानों की ट्रेनिंग दी है। हमने जो भूल की है उसको हम तसलीम कर लें और ध्यान रक्खें कि "आगे सोची सदा सुखी"। हमें सोचना है और सोच कर आगे बढ़ना है। मैं अपने डिफेन्स मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आज डिफेन्स के काम के लिये वे हमारे हरिजन बच्चों को भी लें वर्ना दस करोड़ आदमी आपके खिलाफ हो जायेंगे। हमें यह शिकायतें मिली हैं कि आज हमारे बच्चों को नहीं लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो चिकने चिकने गाल वाले हैं वे काम करने वाले नहीं हैं क्योंकि आज तो हमको मजबूत आदमी चाहियें, पहलवान चाहियें जिसमें अगर आप उनको हुक्म दें कि तुम आगे चले जाओ तो वे चले जायें। आप उनसे ट्रेंच खुदवाइये, सड़कें बनवाइये तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे आदमी ट्रेन्ड हो जायेंगे और डिसिप्लिड ढंग से चलेंगे। वे भी आगे बढ़ कर आयेंगे। वे आपके देश के रक्षक हैं, भक्षक नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

†**श्री राजा राम** (कृष्णगिरि) : सेना ने जो अच्छा काम किया है उसके लिए वे बधाई की पात्र है। अन्य देशों में शान्ति का काम भी सेना ने बहुत अच्छी तरह से किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजाराम]

हमारी दो सीमाएं हैं। एक भूमि की और दूसरी समुद्री। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए हमें अपनी नौसेना को मजबूत बनाना चाहिए। मद्रास के नजदीक समुद्री और औद्योगिक डीजल इंजन बनाने की परियोजना को यथाशीघ्र जल्दी आरम्भ किया जाए।

चीनी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाना है, सैनिक सामान के उत्पादन को बढ़ाया जाए और सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। हर प्रकार का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए।

सैनिकों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिएं तभी वे देश की रक्षा कर सकते हैं।

सैनिक स्कूल और अन्य स्कूलों में सैनिक शिक्षा हमारे बच्चों में सैनिक जीवन और अनुशासन पैदा कर देंगे।

सरकार को और अधिक सैनिक स्कूल खोलने चाहियें। सैनिक स्कूलों में जो फीस रखी गयी है बहुत अधिक है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य की जाये।

सेना में हिन्दी थोपने से लोगों में काफी असंतोष बढ़ रहा है। मेरे विचार से यह अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों को दिये गये आश्वासन के प्रतिकूल है। अतः सेना में हिन्दी न लादी जाये।

एक ओर चीनी हिमालय के सीमान्त में सड़क बना रहे हैं और दूसरी ओर ३२१३ भारतीय युद्ध बन्दियों को छोड़ने जा रहे हैं अतः हमें चीन की कूटनीति से बहुत सावधान रहना चाहिए।

आपातकाल तब तक कायम रहना चाहिये जब तक कि हम शत्रु का सामना करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हों। ऐसे समय एक ओर सरकार भ्रष्टाचार को निर्दयतापूर्वक दबाये और दूसरी ओर मितव्ययिता में एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

†**श्री गजराज सिंह राव** (गुड़गांव) : प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में मतभेद की कोई गुंजायश नहीं होनी चाहिये क्योंकि मुख्य प्रश्न यह है कि देश को किस प्रकार बचाया जाये। यदि आवश्यकता हो तो अन्य विभागों से भी राशि ले कर इस विभाग को दी जानी चाहिये जिससे कि देश इस दिशा में पूरा प्रयत्न करे तथा इस सम्बन्ध में व्यय में कोई सीमा न रखी जाये।

इसमें संदेह नहीं कि हमें अपने मित्र देशों से सहायता प्राप्त करनी चाहिये तथापि हमारा अंतिम उद्देश्य स्वावलंबन होना चाहिये। यदि हम प्रतिरक्षा के मामले में स्वावलम्बी होना चाहते हैं तो हमें बजट की आलोचना नहीं करनी चाहिये तथा अपने मित्रों से यथासंभव पूरी सहायता लेनी चाहिये।

"दोस्तंआ वाशद कि गीरद दस्ते दोस्त दर परेशांहालो व दरमांदगी"

दोस्त वह होता है जो मुसीबत में काम आये आज दोस्तों की आजमायश करने का वक्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज हम पुरानी चीजें छोड़ रहे हैं।

"सूनिश्ता रसलवट आयंदा अहातियात ;—

पुरानी चीजों को छोड़ कर हम कहीं के नहीं रहेंगे।

सभा में जो आलोचनायें की जाती हैं कि चीन इतना शक्तिशाली है तथा हम उसके मुकाबले में कुछ नहीं हैं ठीक नहीं है क्योंकि इनका विदेशों में अच्छा असर नहीं पड़ता है।

संवाद पत्रों में जिस प्रकार की रिपोर्टें छपी हैं उनसे यह स्पष्ट है कि हमारे सिपाहियों ने बहुत बहादुरी दिखाई है तथा वे अंतिम दम तक लड़ते रहे तिस पर यह कहना कि हम चीन के मुकाबले कुछ नहीं हैं बहुत घातक है तथा अनुचित है।

मेरे विचार से आपातकाल में द्विवर्षीय या पंचवर्षीय योजना का कोई मूल्य नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिये कि देश में पंच मार्गी भी हैं।

'घर का भेदी लंका ढावे' आज तक जब भी किसी ने हिन्दुस्तान पर हमला करके कामयाबी हासिल की है तो घर के भेदी की सहायता से की है।

दूसरे तरह के लोग मुनाफ़ाखोर तथा चोर बाजार वाले हैं जो आपातकालीन स्थिति का लाभ उठा कर कीमतें बढ़ा रहे हैं। तीसरे वे लोग हैं जो पराजय वादी लोग हैं ये भी देश का अहित ही करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को माननीय सदस्य की सराहना करनी चाहिये कि इन्होंने अपने तीसरे पुत्र को भी सेवा में भेजा है।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिरक्षा मंत्रालय के बजट पर यह जो वार्षिक वाद-विवाद हो रहा है, इस में भाग लेते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

सब से पहले मैं इन शहीदों के प्रति अपनी हार्दिक भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जो कि इस लड़ाई में शहीद हुए हैं। इस के साथ ही जो बहादुर इस समय भी मोर्चे पर डट कर मुकाबला कर रहे हैं और असाधारण कठिनाइयों के बीच में भी डटे हुए हैं, उन को भी मैं अपनी बधाइयां और शुभकामनायें प्रेषित करता हूं। साथ ही इस अवसर पर अपने नये रक्षा मंत्री महोदय का भी मैं अभिनन्दन करता हूं, इस लिए नहीं कि मैं केवल एक रस्म अदा कर रहा हूं बल्कि इस लिए कि इस समय तक हमारे देश में जितने भी प्रतिरक्षा मंत्री हुए हैं, उन में से इस पद के लिए मैं उन को सब से अधिक उपयुक्त मानता हूं। जिस समय उन्होंने महाराष्ट्र से विदाई ली थी, उस समय उन्होंने जो वाक्य कहा था, वह अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्होंने कहा था, "आज मैं राजनीति से सन्यास ले रहा हूं।" उन्होंने मितभाषी होने, कम बोलने, और अधिक कार्य करने का एक बड़ा भारी ज्वलन्त उदाहरण पेश किया है और इस कारण इस सदन में चाहे मंत्रालय की बड़ी आलोचना की गई हो, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय के बारे में सब स्दस्यों ने प्रशंसात्मक बातें ही कही हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन अब दस घंटे से माननीय सदस्य उन को मजबूर कर रहे हैं कि वह बहुत बोले। वह तो कम बोलना चाहते हैं, लेकिन दस घंटे से जो बहस हो रही है, वह उन को ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि वह इतनी देरी से—कल से अभी तक—जिस धैर्य से इस वाद-विवाद को सुन रहे हैं। उस से भी सिद्ध होता है कि वह कितने धीरज के साथ देश के रक्षा-साधनों को जुटाने में लगे हुए हैं।

चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं दो तीन बातों की ओर ही इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं इस सदन के उन सदस्यों में से रहा हूं, जो अपनी प्रतिरक्षा की तैयारियों के सम्बन्ध में आलोचना करते रहे हैं। पिछले दिनों हम पर जो विपत्ति आई, इस के कारणों में जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस में सब सहमत होंगे कि हमारी ओर से कुछ ग़लतियां ज़रुर हुई हैं। पर अब मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहने का साहस करता हूं कि इस बीच में हमारी हिमालयी सीमा पर जो तैयारियां की गई हैं, उन से संतोष का एक नया वातावरण पैदा हो गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में, जहां बड़ाहोती का वह इलाका है, जिस पर सब से पहले चीनियों ने १९५६ में हमला किया था, जिसका मैं इस सदन में प्रतिनिधित्व भी करता हूं और जिस के बारे में समय समय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। मेरी यह शिकायत रही है कि उस की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अब मैं बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले तीन चार महीनों में जो तैयारियां की जा रही हैं, उन से वहां की जनता का मनोबल, जो कि पहले ही ऊंचा था, और भी ऊंचा हो गया है। मैं यह तो नहीं कहता कि जो तैयारियां हैं, वे पर्याप्त हैं। तथ्य यह है अभी भी उन में और ज्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस इलाके की जनता देश के रक्षा मंत्री की और देश की सरकार को यह आश्वासन देना चाहती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली की एक आम सभा में घोषित किया था, कि जब तक गढ़वाल, और कुमाऊं का एक भी व्यक्ति जीवित है, तब तक चीनी सेनायें आगे नहीं बढ़ सकतीं। वहां की जनता हर प्रकार से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे सेना उस की सहायता करे या न करे। क्योंकि उन्हें तो अपने घरों की रक्षा करनी है उस क्षेत्र में हज़ारों लाखों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्धों में नामवरी हासिल की थी। वे स्वयं और उन की सन्तान संकट के समय कभी भी देश को धोखा नहीं देंगे।

श्रीमन्, लेकिन हम को उन की कठिनाइयों पर भी कुछ ध्यान देना होगा। अभी मुझ से पहले कुछ आदरणीय मित्रों ने एक दूसरी रक्षा-पंक्ति का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में मैं विशेष तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को लड़ाई का इतना बड़ा अनुभव है और वे पहले भी बड़े साहस का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी लिए इस अवसर पर उन की सेवाओं का सदुपयोग किया जाना चाहिये। उन में से कुछ को ज़रूर सेना में दोबारा बुला लिया गया है, जिसके लिए मुझे बड़ा संतोष और प्रसन्नता है, लेकिन अभी भी उन में से हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैं, जिन की बाहें फड़क रही हैं, जो चाहते हैं कि उन के हाथों में हथियार दिये जायें, ताकि वे अपने देश की रक्षा में हाथ बंटा सकें। अतः सरकार को उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये और उन की सेवाओं का सदुपयोग किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान एक बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। भूतपूर्व सैनिकों में एक बड़ा भारी वर्ग उन लोगों का है, जिन्होंने आजाद हिन्द फौज में कार्य किया था। लगभग बाइस हजार उनकी संख्या है, जिनमें से दो ढाई हजार तो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के निवासी हैं। उनमें से दो तीन तो यहां माननीय मंत्री हैं। उन से कुछ को बड़े बड़े पदों पर ले लिया गया है, उन को जगह जगह

नौकरियों में खपा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला कि राजनीतिक पीड़ितों को जो सुविधायें दी जाती हैं, वही सुविधायें उनको भी दी जायें। यह सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कलंक का टीका उनके माथे पर अभी भी लगा हुआ है और वह यह है कि उनका बकाया हिसाब अभी तक उनको नहीं दिया गया है। करीब एक करोड़ रुपए का हिसाब बतलाया जाता है। वह अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कई बार इस प्रश्न को इस सदन में उठा चुका हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समस्या पर नये सिरे से विचार करें।

इस मांग के विरुद्ध दो तर्क दिये जाते हैं। कहा जाता है कि समय बहुत हो गया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सन् १९३० में पेशावर कांड हुआ था, जहां गढ़वाली सैनिकों ने हथियार चलाने से इन्कार कर दिया था और उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। पर १९५६ में अर्थात् २६ वर्ष बाद उन का हिसाब दिया गया था। इसका रिकार्ड मौजूद है। ये लोग १९४५ में डिस्पर्स किये गए थे। और अभी १७ या १८ साल का समय हुआ है। इसलिए उनका हिसाब उनको दिया ही जाना चाहिए।

मुझे विश्वस्त सूत्र से यह बताया गया है कि दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि आजाद हिन्द फौज के लिए देश में लाखों रुपये जमा हुए थे और वे उनको दिये जा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक पेशावर कांड का सम्बन्ध है, स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू ने सारे देश को अपील की थी और "गढ़वाल दिवस" मनाया गया था तथा बहुत से लाखों रुपए उनकी सहायता के लिए दिये गए थे। यह तर्क उनके विरुद्ध क्यों नहीं दिया गया। माननीय प्रधान मंत्री जी शायद इस पर निर्णय दे चके हैं। पर मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें। और शीघ्र अनुकूल निर्णय करें।

यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने इस ओर माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया है कि नीफा और अन्य क्षेत्रों में हमारी सब से बड़ी कमजोरी यह रही कि ऐसे लोगों को वहां भेजा गया, जिन को ट्रेनिंग नहीं थी, जो अभ्यस्त और ऐक्लिमैटाइजड नहीं थे। इस बारे में कुछ विचार किया जा रहा है, यह प्रसन्नता की बात है, लेकिन इस दिशा में मुझे संतोष नहीं है। इस बारे में सबसे बड़ी दो आवश्यकतायें हैं। एक तो यह है कि जो लोग पहले से अभ्यस्त हैं, जो वहां रह चुके हैं, जो वहां की टैरेन को जानते हैं, ऐसे अधिक से अधिक लोगों को लिया जाये। शिकायतें आ रही हैं कि जो लोग भर्ती के दफतर में जाते हैं, उनको पूरी संख्या में नहीं लिया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में खुला आदेश होना चाहिए और अधिक उदारता से उनको लिया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाया है ——मुझे क्षमा करें——कि हमारे अनेक अफसरों में कुछ ऐयाशी का माद्दा, कुछ लखनवीपन, कुछ नजाकत आ गई है।

श्री यशपाल सिंह : अब नहीं है, पहले थी।

श्री भक्त दर्शन : मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं कि सेला के मोर्चे पर जब हमारे सैनिक पीछे हट रहे थे, तो उन्हें हमारे कुछ अफसरों को अपने कंधों पर लाना पड़ा अर्थात् उनकी यह हालत हो गई थी कि वे चल भी नहीं सकते थे। मैं सबकी बात नहीं कहता। मैं किसी अफसर विशेष को दोष नहीं देता। पर इसका असली कारण यह है कि हमने उनको आवश्यक ट्रेनिंग नहीं दी, उनको इन परिस्थितियों का अभ्यस्त नहीं बनाया।

[श्री भक्त दर्शन

मुझे बताया गया है कि हमारे दुश्मन, चीन, के सैनिकों को एक एक दिन में तीस तीस मील पहाड़ों पर दौड़ाया जाता है और उनके अफसर आगे आगे चलते हैं। वे लोग बिना खाये-पीये अपने हाथ में सत्तू, चावल और चाय की बोतल लिए हुए दिन भर मार्च करते हैं। उनको इतनी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अतः हमारे अफसरों और जवानों को भी इसी तरह की सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको जरा कठोर बनाया जाना चाहिए और उनमें जो कोमलपन और मुलायमियत आ गई है, उनको दूर करना चाहिए।

इमर्जेन्सी कमीशन के सम्बन्ध में कोई शिकायतें की जा रही हैं। एक तो यह है कि जो पब्लिक स्कूल्ज के लड़के अंग्रेजी में गिटपिट बोल सकते हैं, उनको एकदम भर्ती किया जाता है। यहां तक शिकायतें आ रही हैं—इस बारे में कोई उदाहरण मैं नहीं दे सकता—कि बड़े बड़े लोगों की सिफारिश पर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में लोग लिए जा रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि जो लोग पहले फौज में सैनिक रह चुके हैं, जो उस अग्नि-परीक्षा से निकल चुके हैं, उनमें से जो क्वालिफाइड हों, सबसे पहले उनको लिया जाये। उसके बाद जो एन० सी० सी० और टेरीटोरियल आर्मी में कार्य कर चुके हैं, उनको लिया जाये और उसके बाद ओपन मार्केट से लोगों को लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आशा करता हूं कि रक्षा मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : द्वितीय युद्ध में हमने भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सिपाहियों से लड़ते हुए देखा था उन्होंने उनके द्वारा भारतीय राष्ट्र का एक चित्र खींचा था। तथापि भारत के नागरिक बनने के पश्चात् नेफा में जो भारतीय सेना की हानि हुई थी उससे हमें काफी धक्का लगा।

अतः हमें चाहिये कि हम आदिम जातियों के दिल और दिमाग से यह बात निकाल देवें तथा उनको यह बताये कि हम भी शत्रुओं के मुकाबले में कम नहीं हैं। इसके लिये कुछ सुझाव इस प्रकार हैं।

उस क्षेत्र के आदिवासियों को, जो ८००० से १०,००० फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। तथा वहां के क्षेत्र से परिचित ह उन्हें सेना में भरती किया जाये।

इन क्षेत्रों के लिये सीमांत सेना संगठित किया जाये। इसके साथ हमें स्थानीय व्यक्तियों को हथियार देने चाहिये आप भले ही इन्हें गृह-रक्षक के नाम से संबोधन करें या किसी और नाम से हमसे उन्हें आत्मरक्षा के लिये बहुत बल मिलेगा।

इसके अलावा हमें सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का भी जाल बिछाना चाहिये जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वहां आवश्यक युद्धास्त्र पहुंच जायें।

सीमांत क्षेत्र में सीमांत सड़क संगठन द्वारा जो सड़के बनायी जा रही हैं वे काफी नहीं न तो कार्य कुशलता से किया जा रहा है और ना हीं इस कार्य में समन्वय ही किया जा रहा हैं।

आसाम रजिमेंट की दूसरी बटेलियन को किसी अपराध के कारण समाप्त कर दिया गया तथा उनमें से कई लोग अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं, मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें छोड़ दिया जाये।

सीमांत क्षेत्रों में सैनिक अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे वहां के स्थानीय लोगों पर बुरा असर होता है। हमारे अतिरिक्त हमारे जवानों के कार्यों से भी स्थानीय जनता में असंतोष फैला है। उनसे कहा जाये कि वे स्थानीय लोगों से अच्छे सम्पर्क बनाये रखें।

नागा विद्रोहियों के खिलाफ जो कार्यवाही हमारी सेना ने की है वह सफल नहीं रही है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस देश के अन्तर्गत जो सीमान्त प्रदेश आते हैं, उनकी हमारे बहादुर भारतीय फौज ने, जवान सिपाहियों ने रक्षा की है, लद्दाख और नेफा के मोर्चे पर बड़ी बहादुरी के साथ राष्ट्र की रक्षा की है जो बहादुरी उन्होंने वहां दिखाई है, उसके कारण उनके नाम अमर हो गए हैं और यह इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। भारतवर्ष के जवानों का इतिहास पुनीत है। इस देश में राणा प्रताप और शिवाजी हो चुके हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि गतवर्ष इसने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। हमारे सैनिकों को नेफा के अन्दर कुछ इलाकों से अगर हटना पड़ा कुछ कमजोरी की वजह से या और किसी कारण से, तो उसका यह अर्थ नहीं हो सकता है कि उन्होंने वहां उत्तम कार्य नहीं किया है। जब कभी देश के अन्दर अकाल पड़ा, बाढ़ आई, या रेलवे दुर्घटना हुई, हमारे सैनिकों ने वहां जा कर बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। देश के अन्दर ही नहीं, विदेशों में जा कर उन्होंने बड़ी प्रशंसा का काम किया। अभी मातृ भूमि का एक अंग गोआ, डामन और ड्यू, जो पुर्तगाल के हाथ में था, उस की भी जा कर उन्होंने रक्षा की और उसे भी भारत माता के साथ मिला दिया। परन्तु मुझे यह नहीं भूलना चाहिये, इस सदन को भी नहीं भूलना चाहिये कि चीनियों ने हिमालय के द्वारा आप के देश पर आक्रमण किया। हिमालय सिर्फ भारतवर्ष का भू-खंड ही नहीं है बल्कि हमारे देश की संस्कृति, गरिमा और प्रतिष्ठा भी हिमालय से ही निकलती है। देश का खून और हड्डी हिमालय से बनी है। अगर हिमालय हिन्दुस्तान का नहीं है तो हिन्दुस्तान निर्जीव है। यह मंत्रालय उसी तरीके से है जैसे कि शरीर में प्राण होता है। रक्षा मंत्रालय किसी भी राष्ट्र के लिये वैसे ही होता है जैसे कि शरीर के लिये प्राण होता है। अगर हमारा रक्षा मंत्रालय सुदृढ़ न हो, मजबूत न हो, तो देश की रक्षा नहीं हो सकती है।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि इस मंत्रालय को आक्रमणकारी होना चाहिये। यह बात सही है, लेकिन यह मंत्रालय आक्रमणकारी तभी हो सकता है जब वह सुदृढ़ हो, ताकतवर हो। जब तक वह ताकतवर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जिस किसी विशेष विदेश से सहायता मिले उसे हम को लेना चाहिये लेकिन जब तक देश स्वतः मजबूत नहीं होता है तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकती। अभी आपने देखा कि क्यूबा में क्या हुआ। ख्रुश्चेव भी मजबूत है इस में कोई शक नहीं, लेकिन अमरीका भी मजबूत है और अमरीका की मजबूती के कारण रशिया क्यूबा से हट गया।

आज भारतवर्ष की जो स्थल सीमा है वह कई हजार मील है, तथा समुद्री सीमा भी कई हजार मील है। इस लिये आवश्यक है कि वायु सेना, स्थल सेना, और नौसेना, तीनों की तरक्की होनी चाहिये। लेकिन कोई भी देश, चाहे उस के अन्दर कितनी ही नौसेना हो,

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय]

कितनी ही वायु सेना हो, कितनी ही स्थल सेना हो, अपनी रक्षा नहीं कर सकता है जब तक देश के अन्दर लोगों का मनोबल ऊंचा न हो। मनोबल तब ऊंचा हो सकता है जब देश के अन्दर जागृति हो । हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ आदमी बसते हैं उन का सब का कर्त्तव्य है कि वे मिल कर देश की रक्षा करें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, देश उसके साथ है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि चाइना की रण नीति ऐसी है कि उस ने रण स्थल के अन्दर अपने जवानों को झोंक दिया, सारी जन-शक्ति लगा दी । कहा गया कि वे तब तक लड़ते रहते जब तक कि दुश्मन के गोले खत्म न हो जायें । ऐसी स्थिति में आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप के पास इतना सामान हो कि उन के जितने भी सैनिक आयें आप उन को मार भगायें, आप के पास इतनी स्थल सेना होनी चाहिये कि उन की फौजों का आप मुकाबला कर सकें। अगर उन के पास २५ लाख फौज हो तो आप के पास ६० लाख होनी चाहिये, अगर उन के पास १ करोड़ फौज हो तो आप के पास २ करोड़ होनी चाहिये । इसी तरह से विजय आपकी हो सकती है। विजय आपकी होगी । इस में कोई शक नहीं है । जब यहां हमारे चव्हाण साहब पधारे हुए हैं जो कि जसवन्त है, बलवन्त हैं, और छत्रपति शिवाजी के अनुगामी हैं तब विजय आप के हाथ में अवश्य है । लेकिन यह विजय तभी होगी जब जनता का मनोबल ऊंचा हो ।

इसके साथ साथ एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं कि :

"भूखे भजन न होय गोपाला"

यह एक देहाती कहावत है। जो आप के सैनिक नेफा और लद्दाख मोर्चे पर १८,००० और १६,००० फीट की ऊंचाई पर लड़ रहे हैं, बर्फ और जाड़े में लड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ कर अपनी जानों की बाजी लगा कर लड़ रहे हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रक्खा जाना चाहिये । यदि वे उस स्थल पर रह कर अपने घरों की तरफ देखें कि उन के बच्चे कैसे रहेंगे, वे शिक्षा पा सकेंगे, या नहीं, तो हमारा काम ठीक से नहीं हो सकता है । इसलिये आवश्यक है कि उन के बच्चों के पढ़ने का आप इन्तजाम करें, और जो सैनिक सेवा से मुक्त हों, उन के लिये आप काम दें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का इतिहास यह बतलाता है कि जब भी इस देश की पराजय हुई तो यहां के लोगों के कारण ही हुई । यहां के पंचमांगियों के कारण पराजय हुई । यहां पर जयचन्दों का काम नहीं है और जयचन्दों पर हमको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है । आप का गुप्तचर विभाग इतना मजबूत होना चाहिये, इतना ताकतवर होना चाहिये कि जिस से आप इन पंचमांगियों से बच सकें।

इन शब्दों के साथ जो अनुदान हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय के द्वारा सदन के सामने रखा गया हैं, उस का मैं अनुमोदन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हेम राज भी दो चार मिनट में कुछ बोल लें ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से माफी चाहता हूं । मैं दो चार मिनट के लिये बाहर गया हुआ था, इस लिये जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं यहां पर खड़ा नहीं हो सका ।

आज जो डिस्कशन हुआ है उस में जहां मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं वहां चव्हाण साहब को भी इस लिये बधाई देता हूं कि जिस समय नेफा में हमारी रिवर्सेज हुई उस के बाद उनकी

नियुक्ति हुई तो मुल्क के अन्दर एक विश्वास पैदा हुआ कि हमारी हार नहीं हो सकती । यह मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं । जहां यह हुआ वहां उसी के साथ साथ जवानों के अन्दर भी यह चीज पैदा हो गई कि उन के सिर पर एक ऐसे आदमी ने हाथ रक्खा है जो उन को जीत की तरफ ले जायेगा ।

यह ठीक है कि, जिस तरह से मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, चाइना जो है, उस ने पन्द्रह सालों में तैयारी की, दूसरी तरफ पाकिस्तान है उस ने दस सालों में तैयारी की। एक ने सामान लिया रशिया से और दूसरे ने सामान लिया है अमरीका से। यह ठीक है कि इन दोनों सीमाओं के पार जो लोग हैं उन की जो तैयारी है उस को देखते हुए हमें उन का मुकाबला करना है। इस के लिये हम ने जो भी लक्ष्य इस समय रक्खा है, उस को हमें पूरा करना है। यह ठीक है कि उनको पूरा करने के लिये आप ने छः डिवीजन कायम करने की बात सोची है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि उन की फौज २५ लाख की है तो कम से कम दूसरी बड़ी लड़ाई से पहले जो हमारी फौज थी उतना तो उस का नम्बर हो जाना चाहिये ताकि हम किसी तरह से चीन का मुकाबला कर सकें ।

आज मुझ से पहले जो वक्ता बोले हैं उन्होंने सोल्जर्स की जो कंडिशन्स हैं उन के बारे में कुछ सजेशन्स दिये हैं। मैं भी दो तीन सजेशन्स देना चाहता हूं, उन के लिये ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । पहली बात तो यह है कि आप के जो फौज का कंसेट्रेशन्स हैं वे पठानकोट में हैं। पठानकोट एक तरफ से पाकिस्तान से लगता है । माउनटेनियरिंग वारफेअर और जंगल वारफेअर जो हैं उस के लिये आप का डिस्पर्सल नहीं है । इस बारे में मुझे यह कहना है कि जो जम्मू से लेकर कांगड़ा हिमाचल तक डोगरा एरिया है उसके किनारे किनारे धौलावार है। उस की ऊंचाई १० हजार से १५ हजार फीट तक है। उस के साथ ही मेन रोड है जो कि पठानकोट से कुल्लू तक चलती है। मैं चाहता हूं कि इस का स्पिर्सल करें । माउनटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिये वह सब से बेहतरीन इलाका साबित हो सकता है और आप की छावनियां अलहिलाल तक बन सकती हैं ट्रेनिंग सेंटर्स बन सकते हैं पालमपुर में और बैजनाथ में। योल कैम्प जो है . .

अन्तर्बाधा आप को लड़ाई नहीं लड़नी है। लड़ाई तो डोगरों को लड़नी है । यह मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि जो डोगरा लोग हैं उन की जो अपनी फाइटिंग क्वालिटीज हैं वह सारे देश में पूरी तरह से रोशन हैं। मैं समझता हूं कि डोगरा एरियाज में एक या दो सैनिक स्कूल होने चाहियें । आप के यहां जो डोगरा फौज में हैं उन की तादाद लाखों तक जाती है । मैं चाहता हूं कि उन के बच्चों के लिये वहां पर सैनिक स्कूल हो जायें और मिलिटरी कालेज हो जायें । यह जो लोग हैं अगर वहां पर उन की लोकल मिलीशिया बन जाये तो उस से आप को और फायदा हो सकेगा । हमारे घर घराट जो हैं वे उन के किनारे पड़ते हैं। हमारे घर घराट जो हैं हमें उनकी हिफाजत करनी है। अगर वहां पर लोकल मिलीशिया बन जायेगी तो आप की सरहद महफूत होती चली जायेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस इलाके में इन दोनों चीजों की तरफ जरूर खयाल किया जाये । वहां मिलिटरी कालेज बनाइये, ट्रेनिंग स्कूल कायम कीजिये, सैनिक स्कूल कायम कीजिये । जो हमारे बहुत से फौजी भाई हैं वह इस तरह के सजेशन्स भी दे चुके हैं। यहां पर श्री इकबाल सिंह ने भी दिये हैं।

जो आप के जे० सी० ओज हैं और एन० सी० ओज हैं उनका हमेशा ताल मेल अपने ऊपर के आफिसर्स से होता है और ओ आर्स जवान होते हैं उनसे ताल मेल भी होता है। अंग्रेजों के जमाने में उनका ताल मेल पूरा चलता था लेकिन वह ताल मेल आज टूटा पड़ा है । चूंकि उनकी ट्रेनिंग लड़ाई के लिये हो चुकी है इस लिये उन में से इमर्जेन्सी कमिशन के लिये

[श्री हेमराज]

आदमी लिये जाने चाहियें । और सारी पोस्ट्स में से ५० फीसदी, या मैं तो कहूंगा कि ७५ फीसदी तक पोस्ट्स, उन के लिये होनी चाहियें क्योंकि वे अच्छे आफिसर्स होंगे और ट्रेन्ड होंगे। वे लड़ाई के लिये पहले से तैयार हैं। मेरे भाई श्री भक्त दर्शन जी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा कि आखिर आराम तलब हो गये हैं। उसको मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। इस लिये मैं मानता हूं कि उन के लिये परसेन्टेज ज्यादा बढ़ा कर ५० परसेंट भी आगे ले जाना चाहिये ताकि आपके लिये बेहतरीन अफसर मिल जाएं ।

जहां तक ताल्लुक है एनक्वायरी का, मैं चाहता हूं कि एनक्वायरी होनी चाहिये और उसका जो नतीजा हो उसके मुताबिक जिन अफसरों ने खराबी की हो उन के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये ताकि बाकी लोगों में डिसिप्लिन रह सके। मैं यह नहीं कहता कि जरूर ही किसी के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। लेकिन जिनको गिल्टी पाया जाए उन के खिलाफ ऐक्शन लेने से आगे डिसिप्लिन कायम रहेगा और लोगों में जोश कायम रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि बावजूद मेरी गलती के आपने मुझे मौका दिया। मैं इन डिमांड्स को सपोर्ट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको चांस न देता तो डोगरे कैसे रिप्रेजेंट होते । मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर सोमवार को देंगे। अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ८ अप्रैल, १९६३/१८ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, ६ अप्रैल, १९६३
१६ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३५६३–८७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
७४१	भाप इंजनों का निर्यात	३५६३–६४
७४२	"भारत के मानचित्र" वाले डाक टिकट	३५६५–६६
७४४	"भूख से छुटकारा" आन्दोलन	३५६६–६९
७४५	क्षेत्रीय परिवहन निगम	३५६९–७१
७४६	अलीगढ़ में कृषि औजार केन्द्र	३५७१–७३
७४७	रेलवे के लिये विश्व बैंक ऋण	३५७३–७४
७४८	सरकार द्वारा गेहूँ की खरीद	३५७४–७७
७४९	दिल्ली में रेल संग्रहालय	३५७७
७५०	बर्मा से लकड़ी के स्लीपरों का आयात	३५७७–८०
७५१	आदर्श गांव	३५८०–८१
७५२	खराब हुए खाद्यान्नों की बिक्री	३५८२–८३
७५३	सघन कृषि कार्यक्रम	३५८३
७५४	रात्रि विमान डाक सेवायें	३५८४–८५
७५५	संयुक्त खेती	३५८५–८६
७५६	चीनी का निर्यात	३५८६–८७
	प्रश्नो के लिखित उत्तर	३५८७—३६२२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
७४३	भारतीय नौवहन समवाय द्वारा जहाजों की खरीद	३५८७
७५७	सिलीगुड़ी जोगीगोपा रेलवे लाइन	३५८८
७५८	एयर लेन्स	३५८८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१५१४	ट्रंक टेलीफोन लाइनें	३५८६
१५१५	डीजल इंजन	३५८६
१५१६	उड़ीसा में कृषि की उन्नति	३५८६–६०
१५१७	उड़ीसा में फल उत्पादन का विकास	३५६०
१५१८	चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारी	३५६०–६१
१५१६	उत्तर प्रदेश में डाक सेवायें	३५६१
१५२०	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन	३५६१
१५२१	सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता	३५६१–६२
१५२२	उत्तर प्रदेश में खेती की उन्नति	३५६२
१५२३	उड़ीसा के लिये माल डिब्बे	३५६२
१५२४	अरहनपुर और निहालगढ़ के बीच हाल्ट स्टेशन	३५६३
१५२५	मालगाड़ी की भिड़न्त	३५६३
१५२६	खाद्य को डिब्बे में बन्द करने और उसे सुरक्षित रखने का केन्द्र	३५६३–६४
१५२७	केरल में टेलीफोन एक्सचेन्ज और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	३५६४–६५
१५२८	वारंगल में पुल	३५६५
१५२६	दिल्ली दुग्ध योजना की एजेंसी	३५६५–६६
१५३०	उड़ीसा में मीनक्षेत्रों का विकास	३५६६
१५३१	उड़ीसा में टेलीफोन	३५६६–६७
१५३२	सिंगरेनी कोयला खानें	३५६७
१५३३	रायपुर-वाल्टेयर रेलवे लाइन	३५६७
१५३४	लघु सिंचाई परियोजनायें	३५६८
१५३५	रेलवे द्वारा कोयले की ढ़लाई	३५६८
१५३६	किसानों को बीज देना	३५६८–३६००
१५३७	बाजार सम्बन्धी सूचना	३६००
१५३८	काजू की खेती	३६०१
१५३६	कारवार में नौका निर्माण कारखाना	३६०१
१५४०	फेरोक में रेलवे क्रासिंग	३६०१–०२
१५४१	वन विभाग, पोर्ट ब्लेयर	३६०२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५४२	रहरा में तारघर .	३६०२–०३
१५४३	राजस्थान में नलकूप लगाना	३६०३
१५४४	रेल डाक सेवा कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता	३६०३–०४
१५४५	बिहार के सीमा जिलों में परिवहन और संचार .	३६०४
१५४६	आंध्र में सड़कें और पुल	३६०४
१५४७	चीनी के सहकारी कारखाने .	३६०४–०५
१५४८	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़कें . .	३६०५
१५४९	घास व चारा गवेषणा संस्था	३६०५
१५५०	पर्यटन का विकास . .	३६०६–०८
१५५१	पौष्टिक भोजन का सम्भरण .	३६०८–०९
१५५२	मनीपुर में टेलीफोन . . .	३६०९
१५५३	सेहल रेलवे स्टेशन का लूटा जाना	३६०९–१०
१५५४	दिल्ली दुग्ध योजना . . .	३६१०
१५५५	दिल्ली के चिड़ियाघर में पक्षियों की संख्या .	३६१०
१५५६	अन्नमलाई विश्वविद्यालय में कृषि कालेज . .	३६११
१५५७	आसाम के पोस्टमास्टर जनरल का मुख्यालय	३६११
१५५८	खुदागंज स्टेशन का लूटा जाना . . .	३६११
१५५९	खेती की स्थिति का अध्ययन करने वाली समिति	३६१२
१५६०	बीकानेर डिवीजन में नये रेलवे स्टेशन .	३६१२
१५६१	टेलीफोन तथा तारघर .	३६१२
१५६२	मध्य प्रदेश में उड्डयन क्लब	३६१३
१५६३	केरल में कृषि परिवार .	३६१३
१५६४	टोंक जिले में टेलीफोन एक्सचेंज	३६१४
१५६५	सवाई माधोपुर में रेलवे पुल .	३६१४–१५
१५६६	मँत्रियों के टेलीफोन बिल .	३६१५
१५६७	यंत्रीकृत फार्म, जस्तर	३६१५
१५६८	टेलीग्राफ इँजीनियरिंग सेवा	३६१६
१५६९	रेलगाड़ियों की टक्कर	३६१६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नो के लिखित उत्तर —क्रमश:		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५७०	उज्जैन रेलवे स्टेशन पर विस्फोट	३६१६
१५७१	दिल्ली दुग्ध योजना . .	३६१७
१५७२	सिरोज-टोंक रेलवे लाइन	३६१७
१५७३	हवाई अड्डों के लिये राडार .	३६१७-१८
१५७४	चलते फिरते वैल्डिंग संयंत्र	३६१८
१५७५	इंटीग्रल कोच फैक्टरी . .	३६१८
१५७६	लालगुडा में बाक्स टाइप के वैगनों का निर्माण	३६१९
१५७७	दक्षिण रेलवे के लिये फिश प्लेट तथा टाई बार	३६१९
१५७८	इस्पात नगरों के लिये विमान सेवायें	३६१९-२०
१५७९	दिल्ली के गांवों में टेलीफोन	३६२०
१५८०	यात्रा अभिकरण . . .	३६२०-२१
१५८१	लखनऊ-बाराबंकी रेलवे लाइन .	३६२१
१५८२	कलकत्ता में पत्तन शुल्क .	३६२१-२२
१५८३	रेलवे सैलून .	३६२२
१५८४	मार्ग में खोई गई वस्तुयें	३६२२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३६२२-२३

(१) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य के बारे में वर्ष १९६१-६२ की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१२ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(दो) दिनांक २९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना सँख्या जी० एस० आर० ५७१ में प्रकाशित दिल्ली रोलर आटा मिलें गेहूँ की चीजें (मूल्य नियंत्रण) सँशोधन आदेश, १९६३ ।

(तीन) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७६ में प्रकाशित भारतीय मक्का (माण्ड उत्पादन में अस्थायी रूप से प्रयोग) संशोधन आदेश, १९६३ ।

लोक-सभा वाद विवाद

दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ (१६ चैत्र, १८८५ (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ ३६६७ (दैनिक संक्षेपिका) पर, पंक्ति ९ में

वित्त मंत्रालय के स्थान पर

प्रतिरक्षा मंत्रालय पढ़िये ।

विषय पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३६२३

चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पर राय ३६२३

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९६२ के बारे में, जिसे २२ जून, १९६२ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या २ सभा पटल पर रखा ।

अनुदानों की मांगें ३६२४–६२

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ८ अप्रैल, १९६३ / १८ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी विचार ।

GMGIPND—LS II—223 (Ai) LSD—30-5-63—160.

पृष्ठ

अनुदानों की मांग—जारी

प्रतिरक्षामन्त्रालय—जारी

श्री बासप्पा . ३६४३–४४

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा ३६४४–४५

श्री उ० मू० त्रिवेदी ३६४५–४६

श्री वीरभद्र सिंह . ३६४६–४७

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह . . ३६४७–४८

श्री स० मो० बनर्जी . ३६४८–४९

श्री इकबाल सिंह . . ३६४९–५०

श्री कृ० च० शर्मा . ३६५०

डा० मा० श्री अणे . . ३६५०–५१

श्री शिव नरायण . ३६५१—५३

श्री राजाराम . ३६५३–५४

श्री गजराज सिंह ३६५४–५५

श्री भक्त दर्शन . ३६५५—५८

श्री रिशांग किशिंग . . ३६५८–५९

श्री विश्व नाथ पाण्डेय . ३६५९–६०

श्री हेम राज ३६६०—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६६३—६७

PLS. 41. XVI. 36. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।